



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 48] नई दिल्ली, नवम्बर 23—नवम्बर 29, 2008, शनिवार/अग्रहायण 2—अग्रहायण 8, 1930
No. 48] NEW DELHI, NOVEMBER 23—NOVEMBER 29, 2008, SATURDAY/AGRAHAYANA 2—AGRAHAYANA 8, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृष्ठक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्यालय मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर

जयपुर, 18 नवम्बर, 2008

सं. 11/2008-09

का.आ. 3108.—आयकर नियम, 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43वां) की धारा 10 के खण्ड (23सी) की उप-धारा (vi) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य आयकर आयुक्त, जयपुर एतद्वारा निर्धारण वर्ष 2005-06 एवम् आगे के लिए कथित धारा के उद्देश्य से "शारदा विद्या मन्दिर प्रबन्ध समिति, जयपुर" को स्वीकृति देते हैं।

वर्शते कि समिति आयकर नियम 1962 के नियम 2 सी ए के साथ पठनीय आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के उपखण्ड (23 सी) की उप-धारा (vi) के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करे।

[क्रमांक : मुआआ/अआआ/(मु.) जय/10 (23सी) (vi)/08-09]

बी. एस. दिल्ली, मुख्य आयकर आयुक्त

4585 GI/08

OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF
INCOME TAX JAIPUR

Jaipur, the 18th November, 2008

No. 11/2008-09

S.O. 3108.—In exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962 the Chief Commissioner of Income-tax, Jaipur hereby approves "Sharda Vidya Mandir Prabandh Samiti, Jaipur" for the purpose of said section for the A.Y. 2005-06 & onwards.

Provided that the society conforms to and complies with the provisions of sub-clause (vi) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax Act, 1961 read with rule 2CA of the Income-tax Rules, 1962.

[No. CCIT/JPR/Addl. CIT (Hqrs.)/10 (23C) (vi)/2008-09]

B. S. DHILLON, Chief Commissioner of Income-tax

(6199)

(क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद् द्वारा भारत का उच्चायोग, फिक्कोरिया, माहे में श्री संजय कुमार सहायक को 27-10-2008 से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/1/2006]

आर. के. पेरिन्दिया, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 27th October, 2008

S.O. 3112.—In pursuance of the clause (ii) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officer (Oaths and fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorize Shri Sanjay Kumar Dey, Assistant to perform the duties of Assistant Consular Officer in the High Commission of India, Victoria, Mahe (Seychelles).

[No. T. 4330/1/2006]

R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2008

का.आ. 3113.—राजनयिक कौंसली अधिकारी (शपथ एवं शुल्क) अधिनियम 1948 (1948 का 41) की धारा 2 के अंक (क) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत का प्रधान कौंसुलरावास, जंजीबार में श्री संजय कुमार, उच्च श्रेणी लिपिक से सहायक कौंसली अधिकारी का कार्य करने हेतु प्राधिकृत करती है।

[सं. टी-4330/1/2006]

आर. के. पेरिन्दिया, अवर सचिव (कौंसुलर)

New Delhi, the 12th November, 2008

S.O. 3113.—In pursuance of the clause (ii) of the Section 2 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (41 of 1948), the Central Government hereby authorize Shri Sanjay Kumar, UDC to perform the duties of Assistant Consular Officer in the Consulate General of India, Zanzibar.

[No. T. 4330/1/2006]

R. K. PERINDIA, Under Secy. (Consular)

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2008

का.आ. 3114.—केन्द्रीय सरकार (संघ के शासकीय प्रयोजनों के प्रयोग के लिए) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उपनियम 4 के अनुसरण में, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित कार्यालय को जिसमें 90% से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्य-साधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :

1. केन्द्रीय मूगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय-भारत सरकार, लाइडोईगढ़-785 700 जोरहाट (असम)।

2. बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, बुनियादी तसर रेशमकीट बीज संग्रहण, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, पाल्लहडा-759 119 जिला-अनगुल (उड़ीसा)।

3. बुनियादी बीज प्रगुणन एवं प्रशिक्षण केंद्र, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, लक्ष्मी निवास, नौलाखा मंदिर के सामने, पो. आश्रम करनीबाद, देवघर-814 112 (झारखंड)।

4. आंचलिक कार्यालय, केन्द्रीय रेशम प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, दूसरा तल, सत्यम कार्पोरेशन कॉम्प्लेक्स, लिंक रोड, बिलासपुर-495 001 (छत्तीसगढ़)।

[सं. ई-11016/1/2005-हिन्दी]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 18th November, 2008

S.O. 3114.—In pursuance of Sub-rule 4 of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union), Rules, 1976 the Central Government hereby notifies the following office under the Ministry of Textiles, whereof more than 90% staff have acquired working knowledge of Hindi :

1. Central Muga eri Research and Training Institute, Central Silk Board, Ministry of Textiles-Govt. of India, Laidoigadh-785 700 Jorhat (Assam).
2. Basic Seed Multiplication and Training Centre, Basic Tasar Silkworm Seed organization, Pallahada-759 119, Distt. Angul (Orissa).
3. Basic Seed Multiplication and Training Centre, Central Silk Board, Laxmi Newas, Inform of Naulakha Temple, Post-Assam Karnibaad, Devghar-814 112 (Jharkhand).
4. Regional Office, Central Silk Technology Research Institute, Central Silk Board, 2nd floor, Satyam Commercial Complex, Link Road, Bilaspur-495 001 (Chattisgarh).

[No. E-11016/1/2005-Hindi]

BHUPENDRA SINGH, Jr. Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

(भारतीय मानक ब्यूरो)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

का.आ. 3115.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक

ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया है :-

अनुसूची

क्रम संशोधित भारतीय मानक संख्या को संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)
1 आई एस 13365 (भाग 1) 1998	1 अक्टूबर, 2008	31 अक्टूबर, 2008

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सीईडो राजपत्र]

ए. कं. सैनी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

New Delhi, the 14th November, 2008

S.O. 3115.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 13365 (Part 1): 1998	1 October, 2008	31 October, 2008

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: C.E.D. Gazette]

A.K. SAINI, Sc. 'F' & Head (Civil Engg.)

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2008

का.आ. 3116.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक

ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संशोधित भारतीय मानक संख्या (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)
1 आई एस 15111 (भाग 1): 2002 सामान्य प्रकारा व्यवस्थाओं के लिए स्वतः वातावरण के लिए स्वतः सुरक्षा अपेक्षाएँ	3 अक्टूबर, 2008	11 नवम्बर, 2008

इस भारतीय संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्तापुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी-23/टी-82]

प्रकाश बच्चानी, वैज्ञा. ई. (निदेशक) (विद्युत तकनीकी विभाग)

New Delhi, the 14th November, 2008

S.O. 3116.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standard, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :—

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 15111 (Part 1): 2002 Self Ballasted Lamps for General Lighting Services : Part/Safety Requirements	3 October, 2008	11 November, 2008

Copies of this amendment are available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: ET-23/T-82]

PRAKASH BACHANI, Sc. E (Director) Electronic Department

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 3117.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के विनियम (5) के उप-विनियम (6) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंसों को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया गया है :—

अनुसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या सीएम/एल	लाइसेंसधारी का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु/प्रक्रम सम्बद्ध भारतीय मानक का शीर्षक	रद्द करने की तिथि
1.	7486390	सुयोग इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ए-2, 2205 जी आईडी सी, हलोल, पंचमहल-389350	एल्युमीनियम कंडक्टर फार ओवरहैड ट्रांसमिशन परपस आईएस 398 पार्ट 4	27-8-2008

[संख्या सीएमडी-13 : 13]

पी. के. गम्भीर, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 19th November, 2008

S.O. 3117.—In pursuance of sub-regulation (6) of the regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988 of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies that the licences particulars of which are given below have been cancelled with effect from the date indicated against each :—

SCHEDULE

SL No.	Licences No. CM/L	Name and Address of the Licensee	Article/Process with relevant Indian Standards covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1.	7486390	Suyog Electricals Ltd. A-2, 2205, GIDC, Halol Distt. Panchmahal-389350	Aluminium Conductors for overhead transmission purpose IS 398 (Part 4)	27-8-2008

[No. CMD/13 : 13]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 3118.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम, 1988 के नियम 4 के उप-विनियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :—

अनुसूची

अगस्त 2008 में स्वीकृत किये लाइसेंस

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	फर्म का नाम तथा पता	उत्पाद का नाम तथा आई एस नंबर	स्वीकृत करने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	7861794	पद्मावती डैकोर प्रा. लि. प्लॉट नंबर 47/48, फेस 1, जी आई डी सी वापी 396195, वलसाद	प्लॉटवुड फार जनरल परपस आई एस 303 : 1989	08-08-2008
2.	7865705	पद्मावती डैकोर प्रा. लि. प्लॉट नंबर 47/48, फेस 1, जी आई डी सी वापी 396195, वलसाद	वीनरड डैकोरेटिव प्लॉटवुड आई एस 1328 : 1996	22-08-2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	7860489	श्रीजो कृपा बैंगल वर्क शॉप नंबर 5, पुनित शॉपिंग सेंटर बालाजी रोड, मुरत	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	04-08-2008
4.	7860590	ओम ज्वैलर्स, 1162 1, सोनो की खादकी के सामने एम जी हवेली रोड, मानेक चौक अहमदाबाद	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	04-08-2008
5.	7863293	बालकृष्णा ज्वैलर्स, डॉ. गांधी रोड, एट तथा पी ओ, माल्लुका डिम्बलनगर, सरवरनांग	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	12-08-2008
6.	7864804	पितृछाया बैंगल वर्क शॉप नंबर 1 पुनित शॉपिंग सेंटर, बालाजी गलर्स स्कूल के सामने, मुरत	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	18-08-2008
7.	7866707	के भीरचंदभाई गोहड फैलेस, 37-38, सिटी कंस्ट मार्केट, स्टेयन रोड, पाटन मेहसाणा	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	25-08-2008
8.	7866808	मानेकलाल वी ज्वैलर्स गामडीवाड के पास, सर्वोदय के सामने, आनंद	स्वर्ण तथा स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषणों शिल्पकारी शुद्धता एवं मुहरांकन आई एस 1417 : 1999	25-08-2008
9.	7868010	शालोमार ईलेक्ट्रिकल डेस्ट्रीज, बड़ोला रोड, लिलेसरा पावर स्टेशन के पीछे, धल्लेसर, गोधरा, पंचमहल	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	29-08-2008
10.	7867810	संगम इलेक्ट्रिकल, ई 9, चिरभू अपार्टमेंट, आनंद सेक्टर के सामने, अंबावाडी, अहमदाबाद-13	न्यारर्स फार फ्लोरोसेंट लैम्प आई एस 2215	28-08-2008
11.	7862089	धनुष प्लास्टो डेक्कन प्रा. लिमिटेड, एन एच 14, टीसा हाईवे, होटल गंगा बूड सामने बदरागा, परतनपुर उदर मुखर	सबमर्सिबल पम्पसेट आई एस 8034 : 2002	08-08-2008
12.	7862796	अमरज्योत इंडस्ट्रीज, खर्ब नंबर 208/2, एट तथा पी ओ माधवास, हसोल कलोल हाइवे रोड, कलोल	सबमर्सिबल पम्पसेट आई एस 8034 : 2002	12-08-2008
13.	7864703	वर्धमान एम्स, 212, आजीबाद, फुट मार्केट नगर रोड, अहमदाबाद	सबमर्सिबल पम्पसेट आई एस 8034 : 2002	18-08-2008
14.	7866101	श्रीराम मिमेंट लिमिटेड, 305, लोमरी भोजल, सम्मान कान्ठवला मल्लम मध्य के सामने, जोधपुर ब्रामरनगर	43 ग्रेड ओ पी सी आई एस 8112 : 1989	22-08-2008

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15.	7865503	साबर पम्प प्रा. लि. यूनिट 2, शिव शक्ति एस्टेट, खेमचंद दयालजी गोडाउन के पीछे, नेशनल हाईवे नंबर 8, नारोल अहमदाबाद	इलेक्ट्रिक मोनोसेट पम्प फार कलीयर कोल्ड वाटर फार एग्रीकल्चरल तथा वाटर सप्लाई आई एस 9079 : 2002	21-08-2008
16.	7864093	पंकज इलेक्ट्रिकल, 13/5, संकल्प एस्टेट, पन्ना एस्टेट रोड, बी ओ सी के पीछे, सोनी की चाल के पास, रखियाल अहमदाबाद	ओपलवैल सबमर्सिबल पम्पसेट आई एस 14220 : 1994	14-08-2008
17.	7865196	डिलाईट पम्प, 40, तिरुपति एस्टेट, अंबर सिनेमा के पीछे, बापुनगर अहमदाबाद	ओपलवैल सबमर्सिबल पम्पसेट आई एस 14220 : 1994	19-08-2008
18.	7867204	बालाजी फाइबर रैनफोर्स प्रा. लि. सर्वे नंबर 293-1 और 2, सकारदा, भादखा रोड, पोचा क्रासिंग के पास गाँव पोचा खंडी	जी आर पी पाईप जायंट तथा फिटिंग फार सिवरेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट तथा वाटर आई एस 14402 : 1996	26-08-2008
19.	7862695	सकेत बिजरेज, महालक्ष्मी मंदिर के सामने, नाडा रोड, शाहैरा, पंचमहल	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	12-08-2008
20.	7863394	शक्ति बिजरेज, 168, कृष्ण एस्टेट, कोठिनूद फ्लोर मिल के पास में, गोरेवा मढोदरा	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	13-08-2008
21.	7866909	एल एस बिजरेज इंडस्ट्रीज 39 महागुजरात इंडस्ट्रियल एस्टेट, रिलायेंस पेट्रोल पम्प के पास, गाँव मोरिया, चांगोदरा, ता. सानंद, अहमदाबाद	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	26-08-2008
22.	7867002	भूमि बिजरेज, भाग्योदय होटल बिल्डिंग, सरखेज सानंद हाइवे, अहमदाबाद	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	26-08-2008
23.	7867608	डिलक्स बिजरेज, जलाय मंदिर गामडी रोड के पास, दाहोद-389170	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	27-08-2008
24.	7868105	फ्रेश पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर ब्राह्मण फालिया, गुजराती स्कूल के पीछे, दिनडोली उधना	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	29-08-2008
25.	7868206	पैसिफिक फिनस्टाक लिमिटेड, 9 वीं मॉडल, गालव चैम्बर्स, सरदार स्टैचू के पास, सयाजीगंज, वडोदरा	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	29-08-2008
26.	7868408	सनराईस बिजरेज तथा फूड, 17-18, सम्राट इंडस्ट्रियल एस्टेट, रेलवे क्रासिंग के पास, गोदादरा दिनडोली रोड, सुरत	पैकेजबंद पेयजल आई एस 14543 : 2004	29-08-2008

New Delhi, the 19th November, 2008

S.O. 3118.—In pursuance of sub-regulation (5) of the regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations 1988, of the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given in the following schedule:

SCHEDULE**Granted licences for the month of August 2008**

S. No.	Licence No.	Name of the firm and address	IS Number & Product	Date of Grant
1	2	3	4	5
1	7861794	Padmavati Decor Pvt Ltd, Plot No 47/48 Phase-I GIDC Vapi 396195, Valsad	Plywood for General Purposes IS 303: 1989	8-8-2008
2	7865705	Padmavati Decor Pvt Ltd, Plot No 47/48 Phase-I GIDC Vapi 396195, Valsad	Veneered Decorative Plywood IS 1328:1996	22-8-2008
3	7860489	Shreeji Krupa Bangles Works Shop No 5 Punit Shopping Centre Balaji Road Surat	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	4-8-2008
4	7860590	Aum Jewellers 1162/1, Opp Soni Ni Khadki, M G Haveli Road, Manek Chowk, Ahmedabad	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	4-8-2008
5	7863293	Balkrushna Jewellers Dr. Gandhi Road, At & Po, Taluka Himatnagar Dist Sabarkantha	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	12-8-2008
6	7864804	Puruchhaya Bangle Works Shop No.1, Punit Shopping Centre, Opp. Balaji Girls School Surat	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	18-8-2008
7	7866707	K. Virchandbhai Gold Palace 37-38, City Point Market, Station Road, Patun Mehsana	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	25-8-2008
8	7866808	Maneklal V. Jewels Near Gamdivad, Opp. Sarvoday Anand	Gold and Gold Alloys, Jewellery/Artefacts-Fineness and Marking IS 1417:1999	25-8-2008
9	7868610	Shalimar Health Care Industries Baroda Road Behind Lilesra Power Station Lilesra Godhra Dist Panchmahals	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	29-8-2008
10	7867810	Sangam Electricals E/9, Birju Apartments, Opp. Azad Society, Ambawadi, Ahmedabad 15	Starters for Fluorescent Lamps IS 2215:2006	28-8-2008

1	2	3	4	5
11	7862089	Duke Plasto Technique Pvt. Ltd., N. H. 14 Deesa High Way, Opp. Hotel Green Wood, Badarpura, Palanpur (N. Gujarat)	Submersible Pumpsets IS 8034:2002	8-8-2008
12	7862796	Amarjyot Industries Survey No. 208/2, At & PO Madhwas, Halol-Kalol Highway Road, Tal-Kalol	Submersible Pumpsets IS 8034:2002	12-8-2008
13	7864703	Vardhman Pumps 212 Ashirwad Estate Opp Fruit Market Naroda Road, Ahmedabad	Submersible Pumpsets IS 8034:2002	18-8-2008
14	7866101	Shriram Cement Limited 305 Third Floor Samaan Complex, Opp Satyam Mall Jodhpur Premchandnagar Road Satellite, Ahmedabad	43 grade ordinary Portland cement IS 8112:1989	22-8-2008
15	7865503	Sabar Pumps Pvt. Ltd. (Unit 2), Shiv Shakti Estate Behind Khemchand Dayaljee S Godown National Highway No. 8 Narol, Ahmedabad	Electric Monoset Pumps for Clear, Cold Water for Agricultural and Water Supply Purposes IS 9079:2002	21-8-2008
16	7864093	Pankaj Electricals 13/5 Sankalp Estate Panna Estate Road B/H BOL Near Soni Cha Rakhial Ahmedabad	Openwell Submersible Pumpsets IS 14220:1994	14-8-2008
17	7865196	Delite Pumps 40, Tinupati Estate, B/H, Amber Cinema, Bapunagar	Openwell Submersible Pumpsets IS 14220:1994	19-8-2008
18	7867204	Balaji Fibre Reinforce Pvt. Ltd. Survey No. 293-1&2, Sakarda Bhadarya Road, Near Poicha Crossing, Village Poicha (Khandi)	GRP pipes joints and fittings for sewerage, industrial waste and water (other than potable) IS 14402:1996	26-8-2008
19	7862695	Sanket Beverages Opp Mahalaxmi Temple, Nada Road, Shahera Panchmahal	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	12-8-2008
20	7863394	Shakti Beverages 168, Krishna Estate, Beside Kohinoor Flour Mill, Gorwa Vadodara	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	13-8-2008
21	7866909	L. S Beverages Industries 39, Maha Gujarat Industrial Estate, NR Reliance Petrol Pump, Village Moriya Changodar, Tal Sanand, Dist Ahmedabad	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	26-8-2008
22	7867002	Bhoomi Beverages Bhagyoday Hotel Building Sarkhej Sanand Highway, Ta Ahmedabad	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	26-8-2008

1	2	3	4	5
23	7867408	Delux Beverages NR Jalai Mandir Gamdi Road Dahod 389170	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	27-8-2008
24	7868105	Fresh Packaged Drinking Water Brahmin Fatra Behind Gujarati School Dindori Taluka	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	29-8-2008
25	7868306	Pacific Finstock Ltd 9th Floor Gateway Chambers Near Sardar Statue Savajigunj Vadodara	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	29-8-2008
26	7868408	Sunrise Beverages & Co. Pvt. 17-18 Samrat Industrial Estate, Near Railway Crossing, Gododara-Dindoli Road, Vadod	Packaged Drinking Water IS 14543:2004	29-8-2008

[No. CMD 13:11]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

रविवार, 20 नवम्बर, 2008

का.अ. 3119.—भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन विनियम 1988 के विनियम 5 के उपविनियम 6 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न विवरण वाले लाइसेंस को उनके आगे दर्शायी गई तारीख से रद्द कर दिया गया है :- 26-7-2008 से 25-8-2008

अधिसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लाइसेंसधारि का नाम व पता	लाइसेंस के अंतर्गत वस्तु प्रकार सम्बद्ध भारतीय मानक का प्रतीक	रद्द करने की तिथि
1	1149948	आर आर विन्डल्स गाला नं. 3 अर्न्ड एन्-ए, 25वां फ्लोर, बॉल, बंदरपाकडी रोड, धानुकर वाडा कांदिवली पश्चिम, मुंबई 400067	भा. मा. 4246:2002 सिंगल, डबल, त्रिपल और फोर बर्नर स्टेनलेस स्टील बांटी के साथ ब्रास कॅप, सी आय बर्नर, एल पी जी के साथ प्रयोग हेतु चोरेन् गैस स्टोव	5-8-2008

[सोएमडी 13:13]

पी. के. गम्भीर, डी. महानिदेशक (मार्क)

New Delhi, the 20th November, 2008

S.O. 3119. In pursuance of sub-regulation (6) of regulation 5 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the licences particulars of which are given in the following schedule have been cancelled with effect from the date indicated against each.

SCHEDULE

S.No.	Licence No.	Name and address of the licensee	Article/Process with relevant Indian Standard covered by the licence cancelled	Date of Cancellation
1	1149948	R R Windals Gate No. 3 & A-19, Haveli, B. Singh Chawl, Bandarpakadi Road, Dhanukar Wada, Koliwali (W) Mumbai -400067 Greater Mumbai Kandivali West Maharashtra 400067	IS 4246:2002 Single, Double, Triple and Four Burner Stainless Steel Body with Brass Cap, C.I. Burner	5-8-2008

[No. CMD 13:13]

P. K. GAMBHIR, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2008

का.आ. 3120.—भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणन विनियम 1988 के विनियम 4 के उप-विनियम 5 के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे दिए गए हैं, वे स्वीकृत कर दिए गए हैं :- 26-7-2008 से 25-8-2008

अधिसूची

क्रम संख्या	लाइसेंस संख्या	लागू तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	उत्पाद	भा. मा. सं./ माग/अनु/वर्ष
1	2	3	4	5	
1.	7865095	18-08-2009	वीर इंजिनियरिंग अँड अप्लायन्सेस, पहला माला, रोड नं. 3, सिंग इस्टेट, ठाकुर बिलेज, कांदिबली (रूई), मुंबई-400101	एल पी जी के साथ प्रयोग हेतु घरेलू गैस स्टोव	भा. मा. 4246:2002
2.	7864396	17-08-2009	रुक्मिणीरामा स्टील रोलिंग्स, (मेंलिंग डिक्लीजन), प्लॉट नं. एल-17, कनकोलिम इंडस्ट्रियल इस्टेट, कनकोलिम, सालसेट, गोवा-403703,	सामान्य संरचना इस्पात में पुनर्वेल्लन के लिए कार्बन डलवाँ इस्पात, बिलेट, इंगट बिलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्टी	भा. मा. 2830:1992
3.	7860994	29-07-2011	कावेरी ज्वेलर्स, 7, साई-धाम निवास, यशोधाम नगर के नजदीक, बस स्थानक, लोकमान्य नगर नं. 2, ठाणे - 400606	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी- शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
4.	7863802	12-08-2011	प्रकाश ज्वेलरी ए-66, बिग-स्मॉल, सेक्टर 17, वाशी, नवी मुंबई 400705	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी- शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
5.	7863192	3-08-2011	मंगलमणी ज्वेलर्स, शॉप नं. 9, पैरव कृपा बिल्डिंग, लक्ष्मी मार्केट के सामने, एन जी आचार्य मार्ग, स्टेशन रोड, चेंबूर, मुंबई-400071	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी- शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
6.	7866606	24-08-2011	नवकार ज्वेलर्स, शॉप नं. 8, ठाकुर आर्कैड, विवा सुपर मार्केट, वसई विकास बैंक, विरार (पश्चिम), ठाणे 401303	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/शिल्पकारी- शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
7.	7862392	10/08/2009	वेस्ट कोएस्ट इनगॉट्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 1, कुदैम इंडस्ट्रियल इस्टेट, कुदैम, उत्तर गोवा 403115	सामान्य संरचना इस्पात में पुनर्वेल्लन के लिए कार्बन डलवाँ इस्पात, बिलेट, इंगट बिलेट, ब्लूम और स्लैब की विशिष्टी	भा. मा. 2830:1992

1	2	3	4	5	
8.	7864404	24/08/2009	क्वार्टिज मेटल इंडस्ट्रीज, (ए हिमिक्वा ऑफ बलबीर मेटल्स ऑन्ट प्रकर प्रा. लि.), एस नं. 363-368, मायली गौव, सिलवासा, 4910 और नगर हवेली -396230	सामान्य संरचना प्रयोजनों के लिए इस्पात-विशिष्ट	भा. मा. 2062: 1999
9.	7864295	12/08/2011	शा. ज्वेलरिंग लुम्याजी ओसवाल, 1999ए, वाजिरचंड, रत्नागिरी, चिपलुन 415605	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
10.	7859306	28/07/2011	ज्वेलरबा, 339, पुरुषोत्तम विला, 339, पुरुषोत्तम विला, सातवाँ रोड, खाण. मुंबई-400052	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
11.	7864497	13/08/2011	इकान अंडवाईजर लिमिटेड, चौदहवाँ माला, एक्सप्रेस टॉवर, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
12.	7861188	03/08/2011	आर जे बैंगल प्रा.लि., यूनिट नं. 252, ए-जेड इंडियस्ट्रियल इस्टेट, जी के मार्ग कोअर पोल, मुंबई 400013	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
13.	7862211	10/08/2009	मोहित इस्पात लिमिटेड, प्लॉट नं. 339/340, कुंदन इंडोमैन्स इस्टेट पीछा 1 नगर पंचायत 403115	सामान्य संरचना इस्पात में गुणवत्तान के लिये कार्यन दलवाँ इस्पात, पिमेंट, इंगट रिमेट, ब्लूम और स्लैब को विनिर्माण	भा. मा. 2830: 1992
14.	7866305	24/08/2009	श्री बैंगल इस्पात प्रा.लि., प्लॉट नं. 352, ऑफ भारत फर्टिलाइजर गेट, बागुल खेरबाड़ी, ताम्रका बाडी, टाण	सामान्य संरचना प्रयोजनों के लिए इस्पात विनिर्माण	भा. मा. 2062: 1999
15.	7859680	31/07/2011	अनमोल ज्वेलर्स, 3, विमला मदन चौक, फ्लोरो हा. नं. आय.आय.टी. मैन गेट, मुंबई, मुंबई-400076	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
16.	7861289	03/08/2011	आर्य गेटव, 209, पार्सन एंडोमैन्स इस्टेट, सर्गमल कोमेटेट, कोअर पोल, मुंबई 400013	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999
17.	7864501	13/08/2011	एल.एस. ज्वेलर्स, बी.2 सेक्टर 3/3/18,	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी शुद्धता व सुहराकन	भा. मा. 1417: 1999

1	2	3	4	5	6
18.	7863091	10-08-2011	कोहिनूर ज्वेलर्स, 7, सुकुमार कॉर्नर, दाऊद बाग, 127 जे.पी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400058	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
19.	7859508	29-07-2011	एस.जी. बाफना ज्वेलर्स प्रा.लि., 275, बाजारपेठ पोलिस स्टेशन, मिवंडी, ठाणे 400058	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
20.	7859104	28-07-2011	डो-निलएक्सपोर्टेड अँड इम्पोर्टेड, 502, रिगल, एस व्ही रोड, सांताक्रुज पश्चिम, मुंबई-400054	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
21.	7864905	12-08-2011	एडवेंचर ज्वेलर्स, सुप्रिम मार्केट, किलवानी रोड, सिल्वासा, दादरा अँड नगर हवेली-396230	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
22.	7864602	13-08-2011	ऑलिवन ज्वेलर्स, 307, गोल्डन प्लाजा, 93/95, धानजी स्ट्रीट, मुंबई-400003	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
23.	7860691	31-07-2011	जाधव ज्वेलर्स, शॉप नं. जी./37, नेहरू नगर, बवे रोड, कुर्ला पूर्व, मुंबई-400024	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999
24.	7858708	21-07-2011	हितेश ज्वेलर्स, 7/9, डी डी प्लाजा, तीसरा अगियारी लेन, 103/105, प्रथम तल, जावेरी बाजार, ग्रेटर बाम्बे, महाराष्ट्र 400003	स्वर्ण और स्वर्ण मिश्र धातुओं के आभूषण/ शिल्पकारी-शुद्धता व मुहरांकन	भा. मा. 1417:1999

[सं. सी एम डी/13 : 11]

पी.के. गम्भीर, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 20th November, 2008

S.O. 3120—In pursuance of sub-regulation (5) of Regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification) Regulations, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licences particulars of which are given below in the following schedule : (26 July, 2008 to 25 August, 2008)

SCHEDULE

Sl. No.	Licence No.	Validity Date	Name and Address (factory) of the Party	Product	IS No./Part/ Sec./Year
1	2	3	4	5	6
1	7865095	18-8-2009	Veer Engineering & Appliances, 1st Floor, Road No. 3, Singh Estate, Thakur Village, Kandivali (E), Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400101	Domestic Gas Stoves for use with Liquefied Petroleum Gases- Specification	IS 4246 : 2002

1	2	3	4	5	6
2	7864396	17-8-2009	Rukminirama Steel Rollings Pvt. Ltd., (Melting Division.) Plot No. L-17, Cuncolim Indl. Estate, Cuncolim, Salcete, GOA-403703 North Goa SAI, CETE Goa-403703	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	IS 2830 : 1992
3	7864441	29-7-2011	Kaveri Jewellers, 7, Sai-Dham Niwas, Near Yashodhan Nagar Bus Stop, Lokmanya Nagar No. 2, Thane, Maharashtra-400606	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999
4	7863802	12-8-2011	Prakash Zaveri, A-66, Big-Splash, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai Thane, Navi Mumbai, Maharashtra-400705	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999
5	7863192	3-8-2011	Mangal Mani Jewellers, Shop No. 9, Inside Bhairav Kripa Bldg., Opp. Laxmi Market, NG Acharya Marg, Station Road, Greater Bombay, Chembur, Maharashtra-400071	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999
6	7866606	24-8-2011	Navkar Jewellers, Shop No. 8, Thakur Arcade, Viva Super Market, Opp. Vasai Vikas Bank, Thane Virar (W) Maharashtra-401303	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking--Specification	IS : 1417 : 1999
7	7862392	10-08-2009	West Coast Ingots Private Limited, Plot No. 1, Kundaim Industrial Estate, Kundaim, GOA- 403115 North Goa, Kundaim Goa Marking-403115	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural purposes	IS : 2830 : 1992
8	7866404	24-08-2009	Quartz Metal Industries, (A Division of Balbir Metals & Power Pvt. Ltd.), S. No. 263/2/8 Village Sayli, Dadra and Nagar Haveli, Silvassa Dadra and Nagar Haveli 396230	Steel for General, Structural Purposes- Specification	IS : 2062 : 1999
9	7864295	12-08-2011	Sha Jawanmal Lumbaji Oswal, 1999, Bazaipeth Ramagiri Chiplun Maharashtra-415605	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999
10	7859306	28-07-2011	Jeweleravi, 339, Purshottam Villa, 7th Road, Greater Bombay Khar (W), Maharashtra-400052	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999
11	7864497	13-08-2011	ECAL Advisors Limited, 14th Floor, Express Towers, Nariman Point, Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400021	Gold and Gold Alloys, Jewellery Artefacts- Fineness and Marking- Specification	IS : 1417 : 1999

1	2	3	4	5	6
12.	7861188	03-08-2011	R.G. Bangle Pvt. Ltd., Unit No. 252, A-Z Industrial Estate, G.K. Marg, Lowerparel, Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400013	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking Specification	
13.	7862291	10-08-2009	Mohit Ispat Limited, Plot No. 339/340 Kundaim Indl. Estate, Kundaim, Ponda, GOA. North Goa, Kundaim, Ponda, Goa-403115	Carbon steel cast billet ingots, billets, blooms and slabs for re-rolling into steel for general structural pur- poses	IS 2830 : 1992
14.	7866303	24-08-2009	Shree Vaishnav Ispat Pvt. Ltd., gut No. 352, off Bharat Fertilizer Road, Bagul Kharewali, Thane Tal wada Maharashtra	Steel for General Structural Purposes- Specification	IS 2062 : 1999
15.	7859609	31-07-2011	Anmol Jewellers, 3, Vinla Sadan Chawl, Opp. Phulora Hsg. Soc., IIT Main gate, Powai, Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400076	Gold and Gold Alloys, IS 1417 : Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking- Specification	
16.	7861289	03-08-2011	Arya Gold, 209, Parvati Indl. Estate, Sunmill Compound, Lower Parel. Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400013	Gold and Gold Alloys, IS 1417 : Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking Specification	
17.	7864501	13-08-2011	S.M. Jewellers B/2, Sector 15, 13/18, Bldg. No. 8, Road No. 4 Vashi, Thane Navi Mumbai, Maharashtra-400703	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking- Specification	
18.	7863091	10-08-2011	Kohinoor Jewellers, 7, Sukumar Corner, Dawood Baug, 127 J.P. Road, Andheri (W), Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400058	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking- Specification	
19.	7859508	29-07-2011	S.G. Bafna Jewellers Pvt. Ltd., 275, Bazarpeth, Opp. Bazarpeth Police, Station Thane, Bhiwandi, Maharashtra-421302	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts 1999 Fineness and Marking- Specification	
20.	7859104	28-07-2011	Do-Nil Export and Import 502, Regal, S.V. Road, Santacruz (W), Greater Bombay, Maharashtra-400054	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts- 1999 Fineness and Marking- Specification	
21.	7864905	12-08-2011	Adventure Jewellers Supreme Market, Kilwani Road, Silvassa Dadra and Nagar Haveli Silvassa, Dadra and Nagar Haveli- 396230	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts- 1999 Fineness and Marking- Specification	
22.	7864602	13-08-2011	Allwin Jewellers, 307, Golden Plaza, 93/95, Dhanji Street, Greater Bombay, Mumbai, Maharashtra-400003	Gold and Gold Alloys, IS : 1417 Jewellery/Artefacts- 1999 Fineness and Marking- Specification	

1	2	3	4	5	6
23.	7860691	31-07-2011	Jadhav Jewellers, Shop No. G/37, Nehru Nagar, Barve Road, Kurla (E), Greater Bombay, Mumbai Maharashtra-400024	Gold and Gold Alloys, IS: 1417 Jewellery/Artefacts- 1999 Fineness and Marking- Specification	
24.	7858708	21-07-2011	Hitesh Jewellers 7/9, DD Plaza, 3rd Agiyari Lane, 103/105 1st Floor, Zaveri Bazar, Greater Bombay, Maharashtra-400003	Gold and Gold Alloys, IS: 1417 Jewellery/Artefacts- 1999 Fineness and Marking Specification	

[No. CMD 17/11]

P.K. GAMATIAK, Dy. Director General (Marks)

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3121. भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अंतर्गुण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिये गये मानक (को) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :

अनुसूची

क्रम संख्या	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने का दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आई एस 4326 : 1993	संशोधन संख्या 4, अक्टूबर, 2008	31 अक्टूबर 2008

इन संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पुणे तथा तिरुवनन्थपुरम में उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : सीईडी/राजपत्र]

ए. के. सैनी, वैज्ञानिक 'एफ' एवं प्रमुख (सिविल इंजीनियरी)

New Delhi, the 20th November, 2008

S.G. 3121—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

SCHEDULE

Sl. No.	No. and year of the Indian Standards	No. and year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1	IS 4326 : 1993	Amendment No. 4, October 2008	31 October 2008

Copy of this amendment is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneswar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: CED/Gazette]

A. K. SAINI, Sec. 'F' & Head (Civil Engg.)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3122.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 255 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मंडल-पालसमुद्रम, जिला-चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनास्वी कि रिकेनेरी से देवनगुडि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20-05-2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : पालसमुद्रम		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश	
गाँव का नाम	सर्वस्व स- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
47, श्रीकावेरिराजुपुरम	111	8	00	00	81
	111	9	00	00	81
	111	15	00	02	83
48, पालसमुद्रम	76	9	00	01	21
49, चैंगलराजुकुम्पम	185	2	00	02	83
	148	5	00	02	83
	86	2	00	00	81
	33	8	00	08	10
50, अमुदला	265	5	00	07	29
	251	10	00	01	62
51, अमिदुला पुत्तुर	98	1	00	00	81
	98	2	00	00	81
	98	3	00	01	21
	103	2	00	00	81

[फा. सं. आर-25011/5/2007-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

Ministry of Petroleum and Natural Gas

New Delhi, the 11th November, 2008

S.O. 3122.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O. No. 255 dated 09-02-2008 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Palasamudram, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited. And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20-05-2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;
And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

mandal : Palasamudram		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Acre	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
47, SRIKAVERIRAJUPURAM	111	8	00	00	81	
	117	9	00	00	81	
	113	15	00	02	83	
48, PALASAMUDRAM	79	9	00	01	21	
49, VENGALRAJUKUPPAM	186	2	00	02	83	
	145	5	00	02	83	
	80	2	00	00	81	
50, AMUDALA	33	2	00	08	10	
	265	5	00	07	29	
	251	10	00	01	62	
51, AMUDALA PUTTUR	93	1	00	00	81	
	93	2	00	00	81	
	82	3	00	01	21	
	107	2	00	00	81	

[F. No. R-25011/5/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3123.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 258 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मंडल-चित्तूर, जिला- चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिफ़ाइनरी से देवनगुडि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20-05-2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी वित्तीयगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : चित्तूर		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण स- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल			
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर	
1	2	3	4	5	6	
55, अनंतपुरम	212	2A	00	04	05	
	177	2	00	00	81	
	177	5	00	00	81	
	112	9	00	02	43	
	112	6	00	03	24	
	114	3	00	01	21	
	114	9	00	00	81	
	115	7	00	00	81	
57, तालांबेडु	51	5D	00	00	81	
	51	5C	00	00	81	
	51	8	00	01	21	
	63	1	00	00	81	
	63	2	00	01	21	
	63	5	00	02	43	
	63	6	00	02	02	
	63	9	00	01	21	
	63	10	00	00	81	

1	2	3	4	5	6
53, तालीबुद्दुल्ला	69	2	00	01	62
	69	1A	00	04	05
58, चिंत्तामूर्ता	41	11	00	01	21
60, नारिंगापल्लि	257	3	00	02	02
	68	3	00	00	81
61, अनुपपल्लि	153	7	00	00	81

[फा. सं. 25011/5/2007-ओ.आर.]

एम. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3123.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 256 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Chittoor, Dist. Chittoor, State Andhra pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20-05-2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal : Chittoor		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Aca	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
55, ANANTAPURAM	212	2A	00	04	05	
	177	2	00	00	81	
	177	5	00	00	81	
	112	9	00	02	43	
	112	6	00	03	24	
	114	3	00	01	21	
	114	9	00	00	81	
	115	7	00	00	81	
57, THALAMBEDU	51	5D	00	00	81	
	51	5C	00	00	81	
	51	8	00	01	21	
	63	1	00	00	81	
	63	2	00	01	21	
	63	5	00	02	43	
	63	6	00	02	02	
	63	9	00	01	21	
	63	10	00	00	81	
	69	2	00	01	62	
	69	1A	00	04	05	
58, CHINTALAGUNTA	41	11	00	01	21	
60, NARIGAPALLE	257	3	00	02	02	
	99	3	00	00	81	
61, ANUPPALLE	153	7	00	00	81	

[F. No. R-25011/5/2007-O.R.-I]

S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का.आ. 3124.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 257 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाब्ध अनुसूची मंडल-गंगावरम, जिला- चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिफ़ाइनरी से देवनगुडि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20-05-2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाब्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी वित्तीय मामलों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा।

अनुसूची

मंडल : गंगावरम		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश	
गाँव का नाम	सर्वेक्षण से- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
74. गंगावरम	751	7	00	02	43
	752	3A	00	16	32
	753	3	00	04	05
75. मारुधुपल्ल	131	7A	00	00	81
	129	3	00	02	02
76. रंठपल्ले	303	1B	00	00	48
78. पापाडुगु	601	2	00	01	62
	601	4	00	01	62
	523	1	00	08	10
	523	2B	00	07	29
	523	2C	00	01	21
79. पाँदकोडा	421	3	00	05	26
	421	1	00	08	48
	312	1A	00	12	96
	150	1	00	01	62
80. कोलाभोन्न	117	3	00	05	26
	91	1	00	03	07
	91	4	00	02	02

[फा. सं. आर-250/1/5/2007-ओ.आर. -1]

एन. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3124.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 257 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Gangavaram, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguithi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20 - 05 -2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal : Gangavaram		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Are	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
74, GANGAVARAM	761	7	00	02	43	
	739	3A	00	18	32	
	769	3	00	04	05	
75, MAREDUPALLI	131	7A	00	00	81	
	129	3	00	02	02	
76, DANDAPALLE	806	1B	00	06	48	
78, MAMADUGU	661	2	00	01	62	
	661	4	00	01	62	
	523	1	00	08	10	
	523	2B	00	07	29	
	523	2C	00	01	21	
79, PATHIKONDA	421	3	00	05	26	
	421	1	00	06	48	
	312	1A	00	12	96	
	150	1	00	01	62	
80, KEELAPALLI	117	3	00	05	26	
	91	1	00	06	07	
	91	4	00	02	02	

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3125.—केंद्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 258 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूची मंडल-विजयपुरम, जिला- चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिकैनेरी से देवनगुडि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20-05-2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केंद्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपावद्ध अनुसूचि में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से भुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : विजयपुरम		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश	
गाँव का नाम	सर्वेक्षण स- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
28. श्रीहरिपुरम	136	15A	00	01	62
	133	19	00	02	83
	124	2	00	04	86
	124	3	00	06	07
	124	5	00	01	21
29. महाराजपुरम	47	2	00	08	10
	48	5	00	07	29
32. पायअरकोट	246	3	00	02	43
	101	1	00	00	81
	154	3A	00	07	29
	154	3B	00	08	10
	155	6	00	07	29

[फा. सं. आर-25011/5-2007-जो.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S.O. 3125.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 258 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Vijayapuram, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20-05-2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

SCHEDULE					
Mandal : Vijayapuram		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh	
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area		
			Hectare	Are	Sq. Mtr.
1	2	3	4	5	6
28, SRIHARIPURAM	136	15A	00	01	62
	133	19	00	02	83
	124	2	00	04	86
	124	3	00	06	07
	124	5	00	01	21
29, MAHARAJAPURAM	47	2	00	08	10
	48	5	00	07	29
32, PATHA ARCOD	246	3	00	02	43
	101	1	00	00	81
	154	3A	00	07	29
	154	3B	00	08	10
	155	6	00	07	29

[F. No. R-25011/5/2007-O.R.-I]

S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3126.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 259 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मंडल-बैरेड्डीपल्लि, जिला-चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिफ़ैनेरी से देवनगुड्डि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20-05-2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : बैरेड्डीपल्लि		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सी- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल			
			हेक्टर	एकर	वर्ग मिटर	
1	2	3	4	5	6	
83, गालापायमिडपल्लि	05	1	00	04	21	
84, आन्नाडिपल्लि	020	1	00	06	07	

[फा. सं. आ. 25011/5/2007-ओ.आर.-1]

एम. के. चिट्ठारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3126.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 259 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its Intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Baireddypalli, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20-05-2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal : Baireddypalli		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Are	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
83. GOLLACHEEMANAPALLI	65	1	00	01	21	
84. ALAPALLI	269	1	00	06	07	

[F. No. R-25011/5/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3127.— केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 260 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मंडल-बंगारुपालेम, जिला- चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिफ़ैनेरी से देवनगुडि टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता. 20 - 05 -2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 का उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विलगनों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : बंगारुपालेम		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश	
गाँव का नाम	संवर्धन स- खण्ड सं.	उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
69, अंबुवरिपल्लि	103	2	00	01	62
	99	1	00	02	83
70, गोल्दामरुत्त	90	6	00	02	02
	90	8	00	01	21
	147	1	00	10	12
72, गांगिनि	173	2	00	02	02
	172	2	00	03	24
	99	2	00	04	05
	48	1	00	09	31
	140	5	00	02	02
	48	4	00	08	10
	51	4	00	11	34

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3127.—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas, S.O.No. 260 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Bangarupalem, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20-05-2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal : Bangarupalem		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Are	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
69, JAMBUYARIPALLI	103	2	00	01	62	
	99	1	00	02	83	
70, GOLLAPALLE	90	6	00	02	02	
	90	8	00	01	21	
	147	1	00	10	12	
72, MOGILI	173	2	00	02	02	
	172	2	00	03	24	
	99	2	00	04	35	
	48	1	00	09	31	
	146	5	00	02	02	
	48	4	00	08	10	
	51	4	00	11	34	

[F. No. R-25011/5/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3128.—केन्द्रीय सरकार पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 08-02-2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का आ. संख्या 261 तारीख 09-02-2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची मंडल-यादामारि, जिला-चित्तूर, राज्य आन्ध्रप्रदेश में चेन्नै पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मनाली कि रिफ़ेनेरी से देवनगुडि-टर्मिनल, बैंगलूर तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा पाइपलाइन बिछाने के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां ता 20 - 05 -2008 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लगमों से मुक्त होकर प्रकाशन की तारीख से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल : यादामारि		जिला : चित्तूर		राज्य : आन्ध्रप्रदेश	
गाँव का नाम	सर्वक्षण सं. खण्ड सं.	रूप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टर	एयर	वर्ग मिटर
1	2	3	4	5	6
64, पेरियांबाडि	246	1A	00	04	86
	246	1C	00	01	62
	246	1E	00	03	64
	243	3	00	02	02
	242	4	00	01	62
	237	1	00	14	02
68, बुडिटिरेडिपल्ले	76	3	00	04	86
	41	7	00	02	02
	42	5	00	04	05

[फा. सं. आर-25011/5/2007-ओ.आर.-I]

एम. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November. 2008

S. O. 3128.—Whereas by the notification of the Government of India. Ministry of Petroleum and Natural Gas. S.O.No. 261 dated 09-02-2008 under sub section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the schedule relating to Mandal Yadamari, Dist. Chittoor, State Andhra Pradesh, annexed to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Petroleum Product from Refinery of Chennai Petroleum Corporation Limited, manali to Devanguthi Terminal, Bangalore, by the Indian Oil Corporation Limited.

And whereas, the copies of the said Gazette Notification were made available to the general public on date of 20 - 05 -2008;

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act, submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government after considering the said report is satisfied that Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification should be acquired.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby direct that the Right of User in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests from the date of publication of this declaration in the Indian oil corporation limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal : Yadamari		District : Chittoor		State : Andhra Pradesh		
Name of the Village	Survey No.	Sub-Division No.	Area			
			Hectare	Acre	Sq. Mtr.	
1	2	3	4	5	6	
64, PERIYAMBADI	246	1A	00	04	86	
	246	1C	00	01	62	
	246	1E	00	03	64	
	243	3	00	02	02	
	242	4	00	01	62	
	237	1	00	14	02	
66, BUDITIREDDIPALLE	76	3	00	04	86	
	41	7	00	02	02	
	42	5	00	04	06	

[F.No. R-25011/5/2007-O.R.-I]

S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3129.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तामिलनाडु राज्य में चेन्नै से कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री आर. आर. जन्तु, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन डिवीजन, हाउस नं॰ 142/2, 2 - क्लस, मुनी रैंडो लेआउट, होरमाव मेन रोड, डोडा बानसवाड़ी, बेंगलुरु-560043 कर्नाटक को लिखित रूप में भेज सकेगा ।

अनुसूची

तालूका : मुलबागल	जिला : कोलार	राज्य : कर्नाटक		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं/उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
रामचन्द्रपुरा	82	00	00	48
पडाकास्ति	69/5	00	38	69
चित्थेरी	77	00	23	78
	78	00	05	04
	65/3	00	02	18
	64	00	18	60
	66/P1	00	39	60
बन्डहल्लि	4/1	00	27	36
	4/2	-	-	-
मिणिजेनहल्लि	20/5	00	01	83
	82/6	00	03	21

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3129.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Chennai in the State of Tamilnadu to Bengaluru in the State of Karnataka, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri R.R Jannu, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division, House No. 142/2, 2nd cross, Muni Reddy Layout, Horamavu Main Road, Dodda Banasavadi Bengaluru – 560043.(Karnataka)

SCHEDULE

Taluk : Mulbagal	District : Kolar	State : Karnataka		
Name of the village	SurveyNo/Sub-division No	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
RAMACHANDRAPURA	82	00	00	48
PADAKASTI	69/5	00	38	69
CHITTHERI	77	00	23	78
	78	00	05	04
	65/3	00	02	18
	64	00	18	60
	66/P1	00	39	60
BANDAHALLI	4/1	00	27	36
	4/2	-	-	-
MINIJENAHALLI	20/5	00	01	83
	82/6	00	03	21

[F. No. R-25011/8/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

दिनांक 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3130.—केंद्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तामिलनाडु राज्य में चेन्नै से कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, केंद्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 60) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता का उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री आर. आर. जन्नु, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कोर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन डिवीजन, हाउस नं० 142/2, 2 - कन्नस, मुर्ती रैंडो लेआउट, होरमाव मेन रोड, डोडा बानसवाड़ी, बेंगलुरु-560043 कर्नाटक को लिखित रूप में भेज सकेगा ।

अनुसूची

तालुका : बंगारपेट	जिला : कोलार	राज्य : कर्नाटक		
खेत का नाम	सर्वेक्षण संख्या-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
बादंडाहल्लि	16	00	00	20
	64	00	27	00
भावहल्लि	58/2	00	00	18
	57/2	00	04	75
मुगालाबेले	72/4	00	10	52
	156/2	00	00	40

New Delhi, the 11th November, 2008

S.O. 3130.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Chennai in the State of Tamilnadu to Bengaluru in the State of Karnataka, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to, Shri R.R Jannu, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division, House No. 142/2, 2nd cross, Muni Reddy Layout, Horamavu Main Road, Dodda Banasavadi Bengaluru – 560043. (Karnataka)

SCHEDULE

Taluka:-Bangarpet	District:- Kolar	State :- Karnataka		
Name of village	Survey No/Sub-division No	Area		
		Hectare	Acre	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
VADANDAHALLI	16	00	00	20
	64	00	27	00
MAVAHALLI	58/2	00	00	18
	57/2	00	04	75
MUGALBELE	72/4	00	10	52
	156/2	00	00	40

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3131.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तामिलनाडु राज्य में चेन्नै से कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री आर. आर. जन्तु, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन डिवीजन, हाउस नं॰ 142/2, 2 - क्रस, मुर्ती रैडी लेआउट, हंरमाव में रोड, डोडा बानसवाड़ी, बेंगलुरु-560043 कर्नाटक को लिखित रूप में भेज सकेगा ।

अनुसूची

तालुका : मालुर	जिला : कोलार	राज्य : कर्नाटक		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं/उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5
नाक्कनाहल्लि	74	00	27	00
निधरमंगला	155	02	26	15
कडसनहल्लि	9	00	03	60
पुरमाकनहल्लि	29	00	16	25
योशवन्तपुरा	98/1	00	19	15
	19/6P1	00	03	92
धाड्वाकडथुरु	60	00	11	87
	158	00	12	24

[फा. सं. अर-25011/8/2007-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3131.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Chennai in the State of Tamilnadu to Bengaluru in the State of Karnataka, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri R.R Jannu, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division, House No. 142/2, 2nd cross, Muni Reddy Layout, Horamavu Main Road, Doddabanasavadi Bengaluru – 560043. (Karnataka)

SCHEDULE

Taluka : Malur	District : Kolar	State : Karnataka		
Name of village	Survey No/Sub-division No	Area		
		Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5
NAKKANAHALLI	74	00	27	00
NIDHARAMANGALA	155	02	26	15
KADASANNAHALLI	9	00	03	60
PURAMAKANHALLI	29	00	16	25
YESHWANTHAPURA	98/1	00	19	15
	19/6P1	00	03	92
DHADDA KADATHURU	60	00	11	87
	158	00	12	24

[F. No. R-25011/8/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का. आ. 3132.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तामिलनाडु राज्य में चेन्नै से कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए ;

और, केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है और जिसमें पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ सार्वजनिक जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्री आर. आर. जन्तु, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पाइपलाइन डिवीजन, हाउस नं 142/2, 2 - क्रास, मुनी रैडी लेआउट, होरमाव मेन रोड, डोडा बानसवाड़ी, बेंगलुरु-560043 कर्नाटक को लिखित रूप में भेज सकेगा ।

अनुसूची

तालूका : होसकोटे	जिला : बेंगलुरु रुरल	राज्य : कर्नाटक		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं/उप-खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
		हेक्टर	एयर	क्व मीटर
1	2	3	4	5
कटिगेनाहल्लि	58	00	07	20
देवरगेल्लहल्ली	21	00	01	00

[फा. सं. आर-25011/8/2007-ओ.आर.-I]

एस. के. चिटकार, अवर सचिव

New Delhi, the 11th November, 2008

S. O. 3132.—Whereas, it appears to the Central Government that it is necessary in the public interest that for the transportation of petroleum products from Chennai in the State of Tamilnadu to Bengaluru in the State of Karnataka, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And, whereas it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (i) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date on which the copies of this notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein or laying of the pipeline under the land to Shri R.R Jannu, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited, Pipelines Division, House No. 142/2, 2nd cross, Muni Reddy Layout, Horamavu Main Road, Dodda Banasavadi Bengaluru – 560043. (Karnataka)

SCHEDULE

Taluka : Hoskote	District : Bengaluru Rural	State : Karnataka		
Name of village	Survey No/Sub-division No	Area		
		Hectare	Acre	Sq. mtr.
1	2	3	4	5
KATTIGENAHALLI	58	00	07	20
DEVROGOLLAHALLY	21	00	01	00

[F. No. R-25011/8/2007-O.R.-I]
S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2008

का.आ. 3133.— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1296 तारीख 5 जून, 2008, जो भारत के राजपत्र तारीख 7 जून, 2008 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मध्यप्रदेश राज्य में बीना संस्थापन से राजस्थान राज्य में कोटा तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए बीना-कोटा पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा एक पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 18 सितम्बर, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिये अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए, सभी वित्तीय वर्षों से मुक्त, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा ।

अनुसूची

तहसील : अशोक नगर		जिला : अशोक नगर		राज्य : मध्य प्रदेश	
क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हेक्टेयर में		
1	2	3	4		
1	खजूरिया खुर्द	173	0.1625		
2	बीरपुर	133	0.0800		
		113	0.5495		
		101	0.3900		
3	सागर	85	0.0585		
		86	0.2080		
		88	0.0910		
		110	0.3125		

क्र.सं.	ग्राम का नाम	सर्वे नंबर	क्षेत्रफल हैक्टेयर में
1	2	3	4
4	आमखोड़ा तुमेन	266	0.0715
		3	0.1755
		1	0.6910
5	डंगाही	257	0.1500
		252	0.2500
6	मैसरावास	732	0.0150
		614	0.1305
		496	0.2990
		499	0.1655
		475	0.1610
		473	0.0590
7	बासरा	131	0.3000
		133	0.4450
		122	0.2650
		107	0.4665
8	कुरवाय	117	0.0900
9	बहेरीपछार	12	0.0845
		14	0.3835
		15	0.3185
10	दमोह	245	0.1560
		244	0.1400
11	भडी कानूनगो	110	0.1235
		382	0.3705
		20	0.2600
		404	0.4945
12	विजयपुरा	96	0.1300
13	कैथाई	78	0.3030
		180	0.0050
		148	0.1040
14	केलारस	51	0.1885
		41	0.2210

[फा. सं. आर-31015/8/2008-ओ.आर.-II]

ए. गोस्वामी, अपर सचिव

New Delhi: The 27th November, 2008

IN pursuance of a resolution of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Mineral Gas No. 1295, dated the 5th June, 2008, issued by the sub-section (1) of section 5 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (30 of 1962) (hereafter referred to as the said Act) published in the Gazette of India dated the 7th June, 2008, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended hereto in confirmation for the purpose of laying a pipeline for transportation of petroleum products through Bina-Katni proposed Project Fund Pipeline located in the State of Madhya Pradesh to Kota in the State of Rajasthan by Bharat Petroleum Corporation Limited :

And that the maps of the said Government declaration were made available to the public on 12th June, 2008.

And that the map of the said Government declaration in sub-section (1) of section 5 of the said Act, is as follows :

And that the Government of India in pursuance of the said section 5 of the said Act being satisfied that the said Government declaration of the pipeline has decided to acquire the right of user therein.

Now, in pursuance of the said Government declaration by sub-section (1) of section 5 of the said Act the Government of India has decided to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended hereto in confirmation by acquired for laying the pipeline.

And that the Government of India in pursuance of sub-section (4) of section 5 of the said Act has decided to acquire the right of user in the said land for laying the pipeline for transportation of petroleum products from the Central Government, on the date of the publication of the said declaration in the said Petroleum Corporation Limited, for a term of

SCHEDULE**TEHSIL : ASHOK NAGAR DISTRICT : ASHOK NAGAR STATE : MADHYA PRADESH**

S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
1	KHAJURIA KHURD	173	0.1625
2	BIRPUR	133	0.0800
		113	0.5495
		101	0.3900
3	SAGAR	85	0.0585
		86	0.2080
		88	0.0910
		110	0.3125
4	AMEKHEDA TUMEN	266	0.0715
		3	0.1755
		1	0.6910
5	DANGAHI	257	0.1500
		252	0.2500
6	BHAISARWAS	732	0.0150
		614	0.1305
		496	0.2990
		499	0.1655
		475	0.1610
		473	0.0590
7	BASRA	131	0.3000
		133	0.4450
		122	0.2650
		107	0.4665
8	KURVAY	117	0.0900
9	BAHERI PACHHAR	12	0.0845
		14	0.3835
		15	0.3185
10	DAMOH	245	0.1560
		244	0.1400

S.No.	NAME OF VILLAGE	SURVEY NO.	AREA IN HECTARE
1	2	3	4
11	MADHI KANUNGO	110	0.1235
		382	0.3705
		20	0.2600
		404	0.4915
12	VIJAYPURA	96	0.1300
13	KAITHAI	78	0.3030
		180	0.0050
		148	0.1040
14	KELARAS	51	0.1885
		41	0.2210

[No. R-31015/8/2008 O.R.-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3134 — पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भू उपयोग अधिकार अधिग्रहण) अधिनियम 1962 (1962 के 50) के खंड 2 की धारा (क) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री के नागेश्वर राव, स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, आंध्र प्रदेश सरकार को आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की विशाख-विजयवाड़ा-सिकन्द्राबाद पाइप लाइन में श्री टी अप्पारव, जिन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3320 के द्वारा दिनांक 16 नवम्बर, 2007 को प्राधिकृत किया गया था, के स्थान पर उक्त अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने और कार्य निष्पादन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

[क्र. सं. आ. 31015/11/2003-ओ.आर. II]

ए. गोस्वामी, अवर सचिव

New Delhi, the 25th November, 2008

S.O. 3134.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri K. Nageswara Rao, Special Deputy Collector, Government of Andhra Pradesh to perform the functions of competent authority under the said Act within the territory of the State of Andhra Pradesh for Hindustan Petroleum Corporation Limited's Visakh-Vijayawada-Secunderabad Pipeline in place of Shri T. Appa Rao authorized vide notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 3320 dated the 16th November, 2007

[No. R-31015/11/2003-O.R.-II]

A. GOSWAMI, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2008

का. आ. 3135.—केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खण्ड (अ) अनुसूचन में, भारत के राजपत्र, तारीख 27 दिसम्बर, 2007 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3621 तारीख 29 दिसम्बर, 2007 का निम्नलिखित रूप से संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची के स्तम्भ 1 में “नं 719 ग्राउंड फ्लोर, 4th क्रॉस, 7th मेन रोड, कल्याण नगर, 1 ब्लॉक, बेंगलुरु -560043 (कर्नाटक)” शब्दों और अंकों के स्थान पर “हाउस नं 142/2, 2nd क्रॉस, मुनी रेड्डी लेआउट, होरमाव मेन रोड, डोडा बानसवाड़ी, बेंगलुरु-560043 (कर्नाटक)” शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आर-25011/12/2006-ओ.आर.-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 20th November, 2008

S.O. 3135.—In pursuance of clause (a) of section 2 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India number S.O. 3621 dated the 27th December 2007 published in the Gazette of India dated the 29th December, 2007 as follows, namely:-

In the said notification, in the schedule, under column 1, for the words and numbers, “No-719, Ground Floor, 4th cross, 7th Main Road, Kalyana nagar, 1st Block, Bangalore-560043 (Karnataka)” the words and numbers, “House No-142/2, 2nd Cross, Muni Reddy Layout, Horamavu Main Road, Dodda Banasavadi, Bengaluru-560043.(Karnataka)”, shall be substituted.

[F.No. R-25011/12/2006-O.R.-I]

S. K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2008

का. आ. 3136.—केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, तारीख 26 अप्रैल, 2008 में प्रकाशित भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना का. आ. संख्या 1893 तारीख 24 अप्रैल, 2008 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में, गुजरात राज्य में स्थापित कोयली – दहेज पाइपलाइन की शाखा आमोद से हजीरा तक पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन विद्यमाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी,

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 1 मई, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और संक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि, पाइपलाइन विद्यमाने के लिए इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है ।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सभी वित्तलगनों से मुक्त घोषणा के प्रकाशन की इस तारीख को निहित होगा ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तालुका	गांव	सर्वेक्षण सं.	उप - खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
						हेक्टेयर	एयर	वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुजरात	भरुच	आमोद	इंदोला	210	P1	00	13	71
				211		00	13	22
				212		00	12	10
				226		00	05	06
				290		00	39	80
				289		00	09	20
				281		00	14	45
				282		00	22	71
				283		00	00	51
				385		00	22	42
				388		00	00	32
				384		00	00	45
				382		00	16	13
				376		00	05	30
				375		00	04	82
				374		00	12	77
				360		00	05	54
				369		00	28	26
				451		00	04	25
				462		00	16	13
				460		00	08	41
				461		00	12	15
				459	1	00	04	52
				489		00	08	95
				488		00	06	53
				490	1	00	00	05
				491		00	14	51
				493		00	17	52
			कोलवणा	782	1	00	00	90
				782	2	00	04	51
				782	3	00	14	03
				781	1	00	15	77
				754		00	02	21
				780		00	06	09
				772	3	00	00	70
				779		00	09	10
				785		00	19	81
				776	A	00	21	04
				791		00	00	05
				773		00	01	44
				792	B	00	19	07
				793		00	25	06
				827		00	00	58
				827	B	00	10	87
				828		00	00	45
				826		00	18	32
				852	A	00	05	71
				851		00	23	76
				850		00	10	31
				853	B	00	00	08
				1028		00	09	23
				1016		00	00	38
				1017		00	01	44
				1018		00	02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कोलवणा	1019		00	01	87
			(जारी)	1025		00	05	64
				1024		00	01	59
				1020		00	09	95
				1023		00	02	18
				1021		00	16	08
				1022		00	00	09
				1011		00	17	84
				1010		00	10	98
				1099		00	00	05
				1114		00	12	09
				1128		00	03	98
				1115		00	00	67
				1116		00	07	64
				1117		00	34	97
				1118	P2	00	07	41
				1123		00	23	48
				1207		00	07	50
				1208		00	33	55
				1223		00	07	91
				1224		00	09	44
				1225		00	08	00
				1251		00	14	74
				1252		00	05	40
				1253		00	05	22
				1256		00	05	43
				1250		00	03	67
				1287		00	00	82
				1286		00	13	20
				1327		00	18	23
				1329		00	01	22
				866		00	05	45
				867		00	13	62
				1376		00	12	62
				1377		00	00	70
				1380		00	15	05
				1379		00	01	24
				1381		00	28	31
				1391		00	05	02
				648		00	21	71
				1409		00	05	43
				1408	3	00	02	61
				652	3	00	02	06
				654	3	00	03	62
				682	1	00	05	97
				682	3	00	04	08
				1404	1	00	11	61
				749		00	01	18
				1403		00	29	30
				1401	1	00	06	08
				1401	2	00	00	86
				1402	1	00	02	08
				1402	2	00	01	09
		तामरा	वीर्य-आह	133	1	00	07	71
				133	2	00	02	37
				136	A	00	30	06
				136	B	00	07	72
				142		00	35	57
				114		00	36	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			वीछीआड	92	A/1-1	00	07	77
			(जारी)	92	A/2-P3	00	35	84
				92	B-P3	00	29	34
				93		00	25	06
				81	1	00	59	18
			सावण	121		00	14	19
				120	A	00	41	76
				120	B	00	42	50
				145	1	00	28	35
				145	2	00	72	83
				135		00	16	92
				150		00	10	75
				163		00	32	50
				166		00	17	17
				169	P1	00	02	10
				169	P2	00	12	56
				167		00	10	05
				185		00	23	35
				189		00	01	78
				181		00	51	25
				180		00	11	51
				211		00	24	26
				210	1	00	11	69
				212	P1	00	11	36
				212	P2	00	10	35
				214		00	03	49
				213	P1	00	21	45
				213	P2	00	30	89
				225	3	00	00	97
			बागरा	682		00	12	42
				683		00	20	62
				728	A	00	00	05
				727		00	16	99
				724		00	01	15
				723		00	08	56
				709		00	01	83
				722		00	05	98
				711		00	05	41
				713		00	08	00
				714		00	03	42
				720		00	12	82
				719		00	15	87
				718		00	06	48
				746	1	00	27	83
				752	1	00	04	68
				752	2	00	02	55
				752	3	00	27	10
				762		00	24	41
				764		00	11	12
				765		00	31	56
				795		00	14	44
				796		00	00	90
			पीसाद	66		00	81	34
				67		00	16	20
				71		00	00	74
				70	P1	00	28	22
				70	P2	00	09	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सांख्यिक	410	1	00	20	92
			(जारी)	410	2	00	01	59
				295		00	30	36
				308		00	15	32
				293		00	29	70
				310		00	29	51
		अक्षर	अक्षर	1012		00	09	23
				1013		00	14	78
				1014		00	56	56
				1031		00	50	29
				1032		00	22	37
				1038		00	07	35
				1042		00	81	67
				1039		00	00	20
				1046		00	00	14
				1046		00	24	90
				951		00	09	87
				952		00	07	28
				941		00	13	78
				950	P	00	06	38
				942		00	07	28
				944		00	08	29
				946		00	06	05
				340		00	02	51
				945		00	06	29
				868		00	32	04
				891		00	32	47
				877		00	58	77
				878	A	00	02	45
				875		00	18	47
				872		00	09	15
				867		00	15	21
				861		00	27	04
				865		00	13	16
				864		00	23	61
				778		00	09	55
				779		00	03	45
			संख्या	28		00	48	92
				40		00	12	35
				41		00	33	68
				42		00	01	22
				72		00	04	78
				71		00	18	09
				88	P2	00	23	78
				70		00	10	63
				89		00	07	22
				86	P1	00	40	29
				92		00	05	14
			नवका	110		00	09	84
				111		00	01	72
				112		00	20	38
				134		00	05	15
				136		00	19	67
				135		00	10	46
				139		00	01	00
				146		00	13	90
				148		00	16	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			सूचक।	149		00	19	07
			(जारी)	150		00	07	79
				128	B	00	00	25
				150	P	00	09	19
				180		00	19	52
				192		00	23	25
				192	P	00	20	69
				217		00	18	98
				216		00	12	85
				214		00	15	87
				312		00	16	52
				311		00	14	82
				313		00	01	74
				310		00	29	55
				309		00	03	13
				270		00	14	00
				324		00	17	60
				274		00	29	00
				277		00	04	42
			सूचक।	277	P1	00	04	29
			(माइयुत)	188		00	29	75
				185		00	10	23
				187		00	15	40
				195		00	25	04
				199		00	20	46
				180		00	37	02
				178		00	17	90
				200		00	16	76
				201	P1	00	15	38
				202		00	13	94
				179		00	10	22
				252	P1	00	05	67
				248	P1	00	55	81
				249		00	01	54
				246	P1	00	00	15
				313		00	23	69
				318		00	21	51
				317		00	13	98
				316		00	01	67
				339	P1	00	27	85
				340		00	07	83
				341		00	00	16
				337	P1	00	19	10
				344		00	19	95
				376		00	19	78
				359		00	45	24
				375		00	00	42
				370		00	05	64
				371		00	06	98
				437		00	30	53
				458		00	03	28
				455		00	14	16
	अजलेकर	माइयुत		301		00	52	36
				753		00	12	09
				381		00	08	99
				372		00	11	82
				312		00	15	20
				337		00	15	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			घंघुरीया	338		00	08	38
			(जारी)	314	1	00	11	29
				330		00	25	98
				317	1	00	00	88
				317	2	00	11	76
				318		00	32	18
				316	3	00	00	07
				318		00	23	34
				297	A	00	12	57
				298	2A	00	13	21
				296	2B	00	04	90
				278		00	08	45
				280	B	00	05	95
				281	1	00	12	98
				281	2A	00	01	18
				282		00	00	66
				283		00	26	88
				284		00	13	98
				240		00	11	25
				175	2	00	07	47
				176		00	25	48
				177	1	00	12	47
				177	2	00	03	14
				178		00	04	87
				179	2	00	12	43
				180		00	06	10
				133	A	00	06	67
				92	A	00	06	25
				92	B1	00	11	85
				91	B	00	17	63
				90	B	00	17	45
				62		00	07	67
				63		00	10	14
				60	1	00	07	15
				55		00	18	47
				54		00	09	59
				18	1	00	14	62
				44		00	12	94
				43	1	00	05	70
				43	2	00	00	06
				42	1	00	11	75
				42	2	00	26	65
				42	3	00	18	50
				23	2	00	12	12
				24		00	02	84
				25	1	00	15	32
				28		00	00	36
				26	1	00	00	76
				27		00	23	76
				29	1	00	00	46
				29	2	00	09	12
			माटीखेड	509	1	00	18	74
				509	2	00	22	36
				509	3	00	34	00
				510	3	00	18	91
				510	2	00	70	28
				507	3	00	06	90
				550		00	24	99
				549		00	13	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			गार्डोलेट (जारी)	642		00	12	66
				636		00	04	67
				639		00	04	19
				635		00	26	61
				639		00	15	36
				640		00	13	29
				642		00	14	62
				657		00	13	50
				656		00	23	69
				660		00	00	06
				661		00	18	91
				662		00	19	20
				669		00	01	02
				667		00	16	07
				666		00	15	90
				223		00	16	39
				219		00	33	74
				218		00	21	17
				217		00	26	47
				214		00	08	30
				209		00	17	12
				160		00	12	93
				190		00	10	07
				186		00	02	40
				179		00	18	57
				180		00	14	10
				181		00	01	99
				171		00	25	34
				170		00	19	65
				165		00	09	65
				164		00	09	97
				163		00	28	77
				130		00	19	45
	हॉसोट	मोडिया		33		00	02	05
				57		00	15	42
				56		00	18	87
				59		00	09	80
				60		00	07	24
				61		00	15	64
				62		00	08	79
				82		00	19	92
				82	A	00	18	26
				219		00	02	53
	दीगस			583		00	05	31
				586		00	37	46
				609		00	21	77
				608	A	00	03	22
				608	B	00	18	18
				314	B	00	00	78
				615		00	25	92
				643		00	27	08
				616		00	00	72
				617		00	01	61
				642		00	07	50
				618		00	01	95
				619		00	02	01
				624		00	08	60
				526		00	33	65

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			दीगस	527		00	10	23
			(जारी)	532		00	07	86
				529		00	05	30
				531		00	32	81
				505		00	03	21
				503	A	00	11	63
				503	B	00	16	04
				492		00	25	51
				473		00	18	50
				470		00	16	64
				464		00	25	83
				450		00	23	58
				451		00	16	58
				452		00	03	60
				453		00	08	70
				454	A	00	05	42
				454	B	00	10	31
				442		00	00	81
				440		00	20	41
				436		00	11	49
				437		00	15	78
				416	A	00	27	64
				416	B	00	07	99
				404		00	54	02
				403		00	12	18
				401		00	09	27
				402	B	00	06	05
				383		00	14	28
				316		00	18	58
				317		00	44	68
				347		00	13	06
				352		00	14	90
				354		00	18	83
				361		00	17	24
				360		00	01	79
				338	A	00	11	28
				338	B	00	11	98
				362		00	05	10
		अंकलेख्यर	मोतवाण	172		00	03	70
				173		00	17	32
				191		00	10	42
		हॉसोट	कलम	28	F1	00	14	39
				57		00	05	51
				58		00	04	90
				69		00	16	54
				60		00	15	74
				5		00	10	67
				61		00	19	86
				67	A/2	00	08	28
				67	B/1	00	03	23
				68	B	00	10	07
				69	A/2	00	06	95
				74		00	06	58
				75	A	00	15	03
				75	B	00	03	98
				76	A+B	00	04	87
				78		00	31	07
				77		00	02	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		हासोट	कलम	54	A	00	37	42
			(जारी)	28	G	00	01	16
		रोहीद		525	A	00	00	47
				523		00	13	62
				494		00	08	99
				495		00	07	43
				496		00	06	40
				521		00	14	55
				520		00	12	36
				519		00	12	77
				478	B	00	16	44
				476	A	00	06	03
				474		00	08	06
				500	A	00	00	05
				501	A	00	31	47
				502		00	15	47
				503	A	00	03	69
				393		00	12	52
				363		00	09	86
				364		00	02	76
				365		00	04	89
				366		00	14	82
				367		00	05	32
				368		00	06	27
				360		00	20	41
				264	B	00	06	73
				281		00	03	41
				220		00	04	08
				278	A	00	15	93
				279	B	00	23	47
				265		00	00	06
				277	A	00	13	39
				266		00	14	70
				269	A	00	06	73
				269	B	00	01	34
				271		00	00	08
				270		00	10	93
				256	B	00	13	17
				255		00	09	59
		कुटावट		135	B	00	09	57
				153		00	00	05
				152		00	13	64
				145		00	16	12
				144		00	17	77
				143	A	00	17	28
				143	B	00	06	56
				139		00	08	44
				138		00	09	44
				137		00	07	92
				133		00	02	60
				82		00	13	57
				81		00	04	61
				86		00	09	11
				87		00	27	33
				88		00	23	86
				77		00	11	30
				75		00	09	53
				89	A	00	29	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			कुबादरा	89	P2	00	26	71
			(जारी)	92		00	00	34
				91		00	08	34
			परवट	418	B	00	21	86
				417		00	11	89
				415	1	00	38	84
				415	2	00	18	01
				413		00	05	09
				414		00	01	88
				288		00	29	54
				286		00	01	08
				287		00	21	72
				285		00	00	15
				319		00	08	70
				320		00	18	45
				325		00	00	23
				324		00	21	09
				327		00	03	46
				328		00	69	80
				333		00	03	21
				370		00	08	40
				368		00	21	49
				364		00	33	84
				363		00	22	33
				341		00	35	98
				342		00	05	13
				340		00	03	21
				189		00	05	98
				188		00	03	64
				190		00	33	67
				188		00	04	84
				197		00	05	43
				198		00	15	13
				199		00	06	58
				200		00	15	77
				202		00	12	86
				203		00	01	87
				212		00	35	31
				211		00	00	65
				210		00	43	19
				152		00	08	48
				150		00	15	88
				148		00	05	07
				149		00	12	22
				135		00	37	23
				133	A	00	01	38
				133	B	00	32	42
			ओभा	183		00	13	22
				184		00	35	67
				185		00	03	07
				199		00	00	93
				171		00	21	84
				169		00	09	23
				168		00	19	32
				167		00	17	47
				217		00	08	15
				218		00	26	99
				219		00	01	34

2	3	4	5	6	7	8	9
		94.0	225		00	03	62
		(1975)	161		05	22	01
			160		03	15	88
			144		01	09	47
			139		10	06	65
			148		10	02	39
			147		00	08	44
			158		00	02	94
			141	2	00	06	93
			156		00	21	95
			158	B	00	01	16
			126		00	00	94
			117		00	15	81
			124		00	06	86
			119		00	02	00
			118		00	29	07
			115		00	16	42
			115		00	05	85
			455		01	04	33
			50		01	23	97
			20		01	17	58
			11		01	05	62
			70		00	01	07
			10		00	00	10
			09		01	22	57
			41		00	23	16
			02		00	04	45
			23		00	04	66
			46		01	04	05
			54		00	07	49
			08		00	00	24
			1018		00	00	01
			1060		00	01	37
			1140		00	09	57
			1213		00	04	49
			1248		01	09	90
			1204	d	00	05	93
			1201		00	01	02
			1208		00	12	00
			1211		00	07	14
			1212		00	02	36
			1215		00	26	41
			1216		01	00	05
			1243		00	02	34
			1242	A	01	04	41
			1242	B	00	04	52
			1261		00	03	71
			1216		00	00	07
			1203		00	00	05
			1230		00	00	05
			1211		00	06	61
			1237		00	17	40
			1223		01	00	01

New Delhi, the 20th November, 2008

S. O. 3136.—Whereas by a notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas Number S.O. 893 dated 26-04-2008 under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the schedule annexed to that notification for the purpose of laying a branch pipeline from existing Koyali – Dahej pipeline for the transportation of Petroleum Product from Amod to Hazira in the State of Gujarat by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas, the copies of the said gazette notification were made available to the general public on the 1st May, 2008;

And whereas, the Competent Authority has submitted report to the Central Government;

And whereas, the Central Government has after considering the report and on being satisfied that said land is required for laying pipeline has decided to acquire the right of user their in;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule annexed to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government vest on this date of publication of this declaration in the Indian Oil Corporation Limited free from all encumbrances.

SCHEDULE

State	District	Taluka	Village	Survey / Block No.	Sub-Division No.	Area		
						Hect.	Are	Sq.mt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gujarat	Bharuch	Amod	Intola	210	P1	00	13	71
				211		00	13	22
				212		00	12	10
				226		00	05	06
				290		00	35	80
				269		00	09	20
				281		00	14	45
				282		00	22	71
				283		00	00	51
				385		00	22	42
				386		00	00	32
				384		00	00	45
				382		00	16	13
				376		00	05	30
				375		00	04	62
				374		00	12	77
				360		00	05	54
				369		00	26	26
				451		00	04	25
				462		00	16	13
				460		00	08	41
				461		00	12	15
				459	1	00	04	52
				489		00	08	95
				488		00	06	53
				490	1	00	00	05
				491		00	14	51
				493		00	17	52
			Kolwara	782	1	00	00	90
				782	2	00	04	51
				782	3	00	14	03
				781	1	00	15	77
				754		00	02	21
				780		00	06	09
				772	3	00	00	70
				779		00	09	10
				785		00	19	81
				776	A	00	21	04
				791		00	00	05
				773		00	01	44
				792	B	00	19	07
				793		00	25	06
				827		00	00	58
				827	B	00	10	87
				828		00	00	45
				826		00	18	32
				852	A	00	05	71
				851		00	23	76
				860		00	10	31
				853	B	00	00	08
				1026		00	09	23
				1016		00	00	36
				1017	B	00	01	44
				1018		00	02	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Kohwana	1019		00	01	87
			(Contd.)	1025		00	05	64
				1024		00	01	59
				1020		00	09	95
				1023		00	02	18
				1021		00	16	08
				1022		00	00	09
				1011		00	17	64
				1010		00	10	58
				1089		00	00	05
				1114		00	12	09
				1128		00	03	98
				1115		00	00	67
				1116		00	07	64
				1117		00	34	97
				1118	P2	00	07	41
				1123		00	23	48
				1207		00	07	50
				1208		00	33	55
				1223		00	07	91
				1224		00	09	44
				1225		00	08	00
				1251		00	14	74
				1252		00	05	40
				1253		00	05	22
				1256		00	05	43
				1250		00	03	67
				1287		00	00	82
				1286		00	13	20
				1327		00	16	23
				1329		00	01	22
				666		00	05	45
				667		00	13	62
				1376		00	12	62
				1377		00	00	70
				1380		00	15	05
				1379		00	01	24
				1381		00	28	31
				1391		00	05	02
				648		00	21	71
				1409		00	06	43
				1408	3	00	02	61
				652	3	00	02	06
				654	3	00	03	62
				682	1	00	05	97
				682	3	00	04	08
				1404	1	00	11	61
				749		00	01	18
				1403		00	28	30
				1401	1	00	06	08
				1401	2	00	00	86
				1402	1	00	02	08
				1402	2	00	01	09
		Vagra	Vichhiad	133	1	00	07	71
				133	2	00	02	37
				136	A	00	30	06
				136	B	00	07	72
				142		00	35	57
				114		00	36	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Vichhiad (Contd.)	92	A/1-1	00	07	77
				92	A/2-P3	00	35	64
				92	B-P3	00	29	34
				93		00	25	06
				81	1	00	59	18
			Sachan	121		00	14	18
				120	A	00	41	76
				120	B	00	42	50
				145	1	00	28	35
				146	2	00	72	83
				135		00	16	92
				150		00	10	75
				163		00	32	50
				168		00	17	17
				169	P1	00	02	10
				169	P2	00	12	56
				167		00	10	05
				185		00	23	35
				189		00	01	78
				181		00	51	25
				180		00	11	51
				211		00	24	20
				210	1	00	11	69
				212	P1	00	11	35
				212	P2	00	10	35
				214		00	03	49
				213	P1	00	21	45
				213	P2	00	30	69
				225	3	00	00	97
			Vagra	682		00	12	42
				683		00	20	52
				728	A	00	00	05
				727		00	16	95
				724		00	01	15
				723		00	08	58
				709		00	01	83
				722		00	05	98
				711		00	05	41
				713		00	08	00
				714		00	03	42
				720		00	12	82
				719		00	15	67
				718		00	06	48
				746	1	00	27	03
				752	1	00	04	68
				752	2	00	02	55
				752	3	00	27	10
				762		00	24	41
				764		00	11	12
				765		00	31	56
				795		00	14	44
				796		00	00	90
			Prasad	66		00	61	34
				67		00	16	20
				71		00	00	74
				70	P1	00	28	22
				70	P2	00	09	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Pisad (Contd.)	78		00	25	71
			Saran	39		00	03	82
				40		00	14	81
				38		00	07	26
				41		00	12	02
				37		00	30	49
				51		00	16	80
				22		00	21	86
				20		00	19	78
				12		00	37	37
				17		00	21	38
				93		00	04	35
				92		00	25	72
				91		00	07	04
				109		00	09	01
				108		00	12	92
				110		00	00	33
				117		00	19	78
				150		00	00	05
				149		00	21	14
				166		00	16	55
				147		00	01	44
				167		00	24	28
				168		00	13	69
				169		00	51	50
				195		00	32	16
				190		00	51	86
				188		00	45	87
				240	P1	00	02	77
			Sayakha	113	2	00	12	68
				114		00	06	94
				115		00	12	17
				116		00	10	04
				140		00	19	97
				141		00	86	31
				152		00	08	52
				154		00	07	87
				153		00	23	92
				166		00	18	39
				167		00	55	09
				170	1	00	41	50
				223	1	00	19	10
				409	3	00	13	88
				227	1	00	06	36
				228	1	00	06	94
				229	1	00	22	56
				232		00	25	69
				255	P2	00	37	50
				256	1	00	24	09
				257		00	36	54
				270		00	33	05
				269		00	42	91
				276		00	16	67
				275		00	10	26
				277		00	21	81
				283		00	21	59
				285		00	16	49
				284		00	17	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Sayakha	410	1	00	20	62
			(Contd.)	410	2	00	01	59
				295		00	30	36
				308		00	19	32
				293		00	29	70
				310		00	29	51
	Bharuch	Amleshwar		1012		00	09	23
				1013		00	14	78
				1014		00	56	58
				1031		00	50	29
				1032		00	22	37
				1038		00	07	35
				1042		00	81	67
				1039		00	00	20
				1046		00	00	14
				1045		00	24	96
				951		00	09	87
				952		00	07	28
				941		00	13	78
				950	P	00	06	38
				942		00	07	28
				944		00	08	28
				946		00	00	05
				940		00	02	51
				945		00	06	19
				888		00	32	04
				891		00	32	47
				877		00	56	77
				876	A	00	02	45
				875		00	18	47
				872		00	09	15
				867		00	15	21
				861		00	27	04
				865		00	13	16
				864		00	23	61
				778		00	09	55
				779		00	03	45
		Shankhwad		28		00	48	92
				40		00	12	35
				41		00	33	68
				42		00	01	22
				72		00	04	78
				71		00	18	09
				88	P2	00	23	78
				70		00	10	63
				89		00	07	22
				88	P1	00	40	29
				92		00	05	14
		Navetha		110		00	09	84
				111		00	01	12
				112		00	20	38
				134		00	05	15
				136		00	19	67
				135		00	10	48
				139		00	01	00
				146		00	13	90
				148		00	16	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Naveha	149		00	19	07
			(Contd)	150		00	07	79
				128	B	00	00	25
				150	P	00	09	19
				180		00	19	52
				192		00	23	25
				192	P	00	20	89
				217		00	19	96
				218		00	12	86
				214		00	15	87
				312		00	18	52
				311		00	14	82
				313		00	01	74
				310		00	29	55
				309		00	03	13
				270		00	14	00
				324		00	17	60
				274		00	29	06
				277		00	04	42
			Mustfabad	277	P1	00	04	29
			(Bhedbhut)	188		00	29	75
				186		00	10	23
				187		00	15	40
				195		00	25	04
				199		00	20	46
				180		00	07	02
				178		00	17	90
				200		00	06	78
				201	P1	00	15	38
				202		00	13	94
				179		00	10	22
				252	P1	00	05	67
				248	P1	00	55	81
				249		00	01	54
				246	P1	00	00	15
				313		00	23	69
				318		00	21	51
				317		00	13	98
				316		00	01	87
				339	P1	00	27	85
				340		00	07	83
				341		00	00	18
				337	P1	00	19	10
				344		00	19	95
				376		00	19	78
				369		00	45	24
				375		00	00	42
				370		00	05	64
				371		00	06	98
				437		00	30	53
				436		00	03	28
				445		00	14	16
	Ankleshwar	Dhanturia		351		01	52	36
				383		00	12	09
				381		00	08	99
				373		00	11	82
				372		00	15	20
				337		00	15	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Chantun	338		00	08	03
			(Contd.)	314		00	11	21
				330		00	25	04
				317		00	00	88
				317	2	00	11	76
				318		00	32	6
				316	3	00	03	07
				319		00	23	24
				297	A	00	12	57
				296	2A	00	15	21
				296	2B	00	04	00
				279		00	06	46
				280	1A	00	05	33
				281	1	00	12	98
				281	2A	00	01	18
				282		00	00	06
				283		00	26	86
				284		00	13	75
				240		00	11	23
				175	C	00	07	47
				176		00	25	06
				177		00	12	47
				177		00	03	14
				178		00	04	87
				179	1	00	12	43
				180		00	06	10
				133	A	00	00	87
				92	2	00	06	35
				92	8A	00	11	03
				31	5	00	17	06
				90	3	00	17	85
				62		00	07	43
				63		00	10	4
				60	1	00	07	10
				65		00	13	41
				54		00	09	20
				43	1	00	14	92
				44		00	12	94
				43	2	00	07	30
				42	2	00	04	03
				42	3	00	13	10
				42	4	00	25	05
				42	5	00	18	60
				23	2	00	12	12
				24		00	02	87
				25	1	00	15	30
				28		00	00	36
				26	1	00	30	30
				27		00	13	76
				29	1	00	00	40
				29	2	00	03	12
			Mahan	509	1	00	18	14
				509	2	00	27	34
				509	3	00	34	00
				510	3	00	18	91
				510	4	00	70	21
				507	3	00	06	10
				550		00	24	46
				549		00	13	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Maliad (Contd.)	548		00	12	88
				636		00	04	87
				638		00	04	19
				635		00	26	61
				639		00	15	36
				640		00	13	29
				642		00	14	62
				657		00	13	50
				658		00	23	59
				660		00	00	05
				661		00	18	91
				662		00	19	20
				669		00	01	02
				667		00	18	07
				666		00	15	90
				220		00	16	38
				219		00	33	74
				218		00	21	17
				217		00	26	47
				214		00	09	30
				209		00	17	12
				189		00	12	93
				180		00	10	07
				186		00	02	40
				179		00	18	57
				180		00	14	10
				181		00	01	99
				171		00	25	34
				170		00	19	85
				165		00	09	65
				164		00	09	97
				163		00	28	77
				130		00	19	45
		Hansot	Mothia	33		00	02	05
				57		00	15	42
				56		00	18	87
				59		00	09	63
				60		00	07	24
				61		00	15	84
				62		00	08	79
				82		00	19	92
				83	A	00	18	28
				219		00	02	53
			Digas	583		00	05	31
				586		00	37	45
				609		00	21	77
				608	A	00	03	22
				608	B	00	18	18
				614	B	00	00	78
				615		00	25	92
				643		00	22	08
				616		00	00	72
				617		00	01	61
				642		00	07	50
				618		00	01	95
				619		00	02	01
				624		00	08	60
				526		00	33	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Digas (Contd.)	527		09	10	23
				532		10	07	36
				529		00	05	30
				531		00	32	81
				505		00	03	21
				505	A	00	11	63
				503	B	00	16	04
				492		00	25	51
				473		00	18	50
				470		00	16	64
				464		00	25	63
				450		00	23	56
				451		00	16	66
				452		00	03	60
				453		00	03	70
				464	A	00	03	42
				454	B	00	10	51
				447		00	00	01
				440		00	20	41
				436		00	11	49
				437		00	10	75
				416	A	00	27	04
				416	B	00	07	59
				404		00	34	00
				403		00	10	18
				401		00	00	27
				402	B	00	06	05
				393		00	14	29
				316		00	16	58
				317		00	44	62
				347		00	13	06
				352		00	14	90
				354		00	16	83
				361		00	17	24
				380		00	31	79
				338	A	00	11	20
				338	B	00	11	98
				362		00	05	10
		Ankleshwar	Matwan	172		00	03	70
				173		00	17	32
				191		00	10	42
		Hansot	Kalam	39	F1	00	14	39
				57		00	05	51
				58		00	04	50
				50		00	16	54
				60		00	16	74
				6		00	10	67
				61		00	16	86
				67	A/2	00	06	26
				67	B/1	00	03	23
				68	B	00	10	07
				69	A/2	00	06	55
				74		00	06	58
				75	A	00	15	03
				75	B	00	03	96
				76	A+B	00	04	87
				78		00	11	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Obha (Contd.)	220		00	03	62
				161		00	22	01
				160		00	18	88
				144		00	00	47
				159		00	06	65
				146		00	02	39
				147		00	08	44
				158		00	02	94
				141	2	00	08	93
				156		00	21	95
				155	B	00	01	16
				126		00	00	94
				127		00	19	81
				128		00	08	86
				119		00	02	00
				118		00	20	07
				117		00	16	42
				112		00	08	85
				455		00	04	33
				456		00	23	97
				458		00	17	58
				73		00	08	62
				72		00	01	07
				70		00	20	79
				69		00	22	97
				47		00	23	59
				22		00	04	48
				23		00	04	50
				46		00	04	05
				24		00	07	49
				25		00	09	24
				1249		00	03	51
				1203		00	01	37
				1248		00	09	57
				1247		00	04	49
				1246		00	09	90
				1204	B	00	05	93
				1207		00	07	02
				1208		00	13	93
				1211		00	07	14
				1212		00	02	68
				1215		00	26	41
				1216		00	00	05
				1143		00	02	34
				1142	A	00	04	41
				1142	B	00	04	52
				1141		00	03	71
				1129		00	05	07
				1133		00	00	05
				1130		00	00	05
				1131		00	06	61
				1132		00	17	43
				1123		00	06	01

अम एवं रोजगार मन्त्रालय
नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

क्र.आ. 3137 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) का अनुसूची 12 के अनुसार के, क.प्र. 1948,
सिंडिकेट बैंक के प्रबंधन के संयुक्त नियंत्रकों और अन्य के बीच
को बीच, अनुसूची 3, विवाद औद्योगिक विवाद से संबंधित विवाद
औद्योगिक अधिनियम अम न्यायलय लखनऊ के फ.प्र. (सं.सं.)
सं. 20/2005) की परामर्श कार्य है, जो कोर्टो. न्याय को
31-10-2008 का पाल दूआ है :

[सं. प्र.सं. 2011, 22005-अर्ध 2011, 1-11]
मन्त्र कुमर उपाध्याय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 2523. In pursuance of Section 17 of the
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Government of
Government hereby publishes the Award (F. No. 3137/2005)
of the Central Government Industrial Tribunal (Central
Labour Court) Lucknow as shown in the Annexure to the
Industrial Dispute between the management of the State
Bank and the workmen, received by the Central
Government on 11.10.2008.

[F. No. 3137/2005 (Part III)]
RAMESH KUMAR, Dy. Commr.
ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL LABOUR COURT) LUCKNOW

PRESENT : N.K. PURCHHI

F. No. 20/2005

Ref. No. 1-1911/2005 (P.B-H), dated 28-10-2008

BETWEEN

The Secretary, Syndicate Bank Employees Union
U.P. State Government, 94, Halwai-in-Nagar,
Lucknow-226001

(In the name of Sh. Ram Lal)

AND

The Dy. General Manager, Syndicate Bank
Zonal Office, 187, All University Road
Bhawaniganj, Meerut-205001

(VS)

Lucknow, the 21st October, 2008

1. By Order No. 1-1911/2-2005 (P.B-H) dated
6-6-2005 the Central Government in the Ministry of Labour,
New Delhi in exercise of powers conferred by section 17 of the
sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 17 of the
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) referred this
Industrial dispute between the Secretary, Syndicate Bank

Employees Union, Lucknow and the Dy. General Manager,
Syndicate Bank, Meerut to this Tribunal.

2. Whether the action of the Management of
Syndicate Bank in not regularizing the Services of Sh.
Ram Lal, part time sweeper, is just and justified? If not, what
relief of the concerned workman is entitled?

2. In brief, the case of the workman is that he was
appointed as part time sweeper in Extension number of
Syndicate Bank in 1973 on a consolidated salary of
Rs. 440 per month. He has not given any appointment
letter and the workman has given five drawings of Rs. 440
per month which was not regularly enhanced to 11th of
the scale wages in 2005. He said he is working as such
since then without any break. He is entitled to be treated as
appointed on permanent basis against a permanent post.
The workman has prayed to direct the Bank to regularize
him as permanent employee of the Bank.

3. The management has denied the claim of the
workman for regularization in his service. It is recorded
in the written statement that the workman was not
appointed in accordance with any rules against any
permanent vacancy. It was argued on the basis of nature
of the work as part time sweeper. The management was
purely temporary in nature. It further contended that the
workman was never asked for regular appointment in the
service of the Bank. Its appointment letter was issued in
the workman while engaging him so he cannot be treated
as permanent employee. The claim of the workman for his
regularization as part time sweeper cannot be considered
as per guidelines issued by the Govt. of India with regard
to the filling of vacancies. The management has not adopted
any unfair labour practices. Therefore, the claim of the
workman is not tenable.

4. On 21-10-2008 at this stage of worker's evidence an
application has been filed by the labour representative
of the workman for regularization of the workman
along with an affidavit in the witness of Sh. Ram Lal and
copy of the letter dated 11-10-2007 regarding order of
appointment to him to the management of the Bank. The
workman has stated in a affidavit that present dispute is
regarding regularization in his service and he has been
offered regular appointment in the Bank as stated after
dated 29-11-2007. There is no labour dispute exists between
the parties.

5. Since the claim for regularization of the
management is not coming in the dates of hearing in
the case. The present case has been raised on behalf of
the workman Sh. Ram Lal by the Secretary, Syndicate Bank
Employees Union and the application to withdraw the case
has been moved by the labour representative of the
said union. Therefore, no labour dispute exists between
to withdraw the case.

6. In the above circumstances it is held that there is no need to decide and reply the reference on merit and the same is disposed off as there is no grievance left with the workman after withdrawal of his case. The matter is resolved as above and the reference is answered accordingly.

N. K. PUROHIT, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

का.आ. 3138—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंधन के संबद्ध नियोक्ताओं और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक अधिकरण/श्रम मंत्रालय कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 28/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/163/2001-आई आर (बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 3138.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 28/2001) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab and Sind Bank and their workmen, which was received by the Central Government on 31-10-2008.

[No. L-12011/163/2001-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI R. G. SHUKLA PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

I. D. No. 28 of 2001

BETWEEN

Sri Hari Prasad son of L. Laxaman Singh
1217/1550 Ratanpur Colony
Panki, Kanpur.

AND

The Senior Manager,
Punjab and Sindh Bank,
Branch Office,
Gadarian Purwa K-622, Kanpur.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide notification No. L-12012/163/2001 IR-B-II dated 29-11-2001 has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.

2. Whether the action of the management of Punjab & Sindh Bank Gadarian Purwa, Kanpur, in terminating the services of Sri Hari Prasad son of late Laxaman Singh w.o.f. 5-10-99 is legal and justified? If not to what relief is the concerned workman entitled to?

3. It is the own case of the workman that he was engaged as a daily wager by the opposite party bank on 01-01-91 and worked as such till 4-10-99 and when he reported for his duty on 5-10-99 he was not allowed to work by the opposite party in this way his services have been removed by the opposite party bank in breach of the provisions of Industrial Disputes Act, 1947, inasmuch as at the time of his termination neither he was given notice nor notice pay the retrenchment compensation by the opposite party bank. Therefore, his termination falls within the term of retrenchment which is bad in law and he is liable to be reinstated in the services of the bank.

4. A Part from above it has also been pleaded by the workman that beside performing daily work he was also doing the regular and permanent work entrusted upon him by the bank and he orally as well as in writing requested the bank to absorb him in the service of the bank which annoyed the authorities of the bank as a result of which he was removed from the service in an illegal and arbitrary manner which is against the rules and against the provision of the Industrial Disputes Act, 1947, which is liable to be set aside by this tribunal and he be directed to be reinstated in the service of the bank with full back wages and all consequential benefits.

5. On the other hand the claim of the workman have been vehemently denied by the opposite party bank on a number of grounds, *inter-alia*, that no officer of the opposite banks is empowered to appoint any employee in the bank unless he has been subjected to selection process framed under recruitment rules; that the workman has never been subjected to any such process, no appointment letter or termination letter has been issued to him, workman has never been given regular wages from the approved budget of the bank, mere by way of working on the basis of daily rated workman he cannot lay his claim towards his reinstatement in the service of the bank, the disengagement of the workman cannot amount to retrenchment and being so he cannot be protected under the provisions of I.D. Act. On the basis of above pleadings it has been prayed that the claim of the workman is devoid of merit as the opposite party never breached any of the provisions of the Act, therefore, the claim of the workman is liable to be rejected.

6. After exchange of pleadings between the parties both contesting parties have led oral as well as documentary evidence in support of their respective claims.

7. I have heard the arguments of the parties at Kanpur and have also perused the evidence and documents available on record carefully.

8. It is pertinent to mention here that the instant case can be decided only on the basis of admission of facts

ignoring the claim and evidence of the opposite party bank in view of settled legal position that the labour courts/Industrial Tribunals are not supposed to be used as a means for providing appointment against public employment without following the recruitment rules in view of the case *Smt. Chaudhary* decided by the Hon'ble Supreme Court of India in which it has been held by the Hon'ble Court that a public sector employee, casual or temporary employee or even *ad hoc* employee is not entitled to claim reinstatement against any particular post when he has completed 180 days of continuous service, even without undergoing through recruitment process. The Hon'ble Supreme Court of India in its decision has also deprecated the practice of providing such employment. In view of this settled legal position, it emerges from the own pleadings of the workman that he was employed on daily rate basis by an officer of the branch of the bank. The opposite party bank in its reply has clearly averred that no officer of the bank is empowered to appoint any person in the bank and all appointments are confined to supervision and control of the Head Office of the bank, and only such persons are offered regular and permanent employment in the bank who are found eligible for selection and interview.

9. In view of above and also in view of the fact that the workman has not whispered even a single word in his pleadings or in his evidence about the violation of the provisions in the service condition, therefore, there remains hardly any need to discuss further evidence of the contesting parties in the instant case as it would be a futile exercise on the part of the labour court. Moreover, the provisions of the Act cannot be read in isolation in the absence of pleading regarding breach of the provisions of service rules as the provisions of the Act cannot be termed to be provisions governing the service conditions of the workman. Therefore, in view of above, it is clear that the provisions of the Ind. Act are not applicable in the case of the workman and the workman even though entitled for promotion as mentioned under the Ind. Act, these are applicable only to such workman who are appointed while observing recruitment rules. Therefore, in view of the facts and law that the workman is not entitled to the relief claimed by him.

10. Lastly, it is reiterated that the workman cannot be held entitled for any relief as claimed by him in view of above observations. Therefore, the reference cannot be decided against the workman and in favour of the management and it is held accordingly.

11. Reference is therefore answered accordingly.

R. G. SHUKLA, President of the

दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

का.आ. 3139 : औद्योगिक विवाद, अर्थशास्त्र : 1947 का 11 : औद्योगिक विवाद अधिनियम में केंद्रीय सरकार (संदर्भ सं. 15/2006) को प्रस्तुत करने के, जो केंद्रीय सरकार को 31-10-2008 को प्रस्तुत किया गया।

के बीच, अनुबन्ध में विहित औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-अम. नवम्बर कानपुर के पंचद (संदर्भ सं. 15/2006) को प्रस्तुत करने के, जो केंद्रीय सरकार को 31-10-2008 को प्रस्तुत किया गया।

[सं. ए. 12012 5 2005 आई आर (बी-11)]

राजेंद्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi the 31st October, 2008

S.O. 3139 : In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref No. 15/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-com-I labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Punjab and Sindh Bank and their workman received by the Central Government on 31-10-2008.

[No. I-12012 5 2005-IR(B-11)]

RAJENDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE PRESIDING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, THIRUAM BHAWAN A.T.I. CAMPUS, UDYOG NAGAR KANPUR

Present Sri R.G. SHUKLA, I.J.S.

Industrial Dispute No. 15/2005

BETWEEN

Sri Vishal Kumar Alias Vishnu Kumar

S/o Ghanshyam Das

R/o 37/87, Nagla Path, Nagla Bugh Road, Agra

AND

The Zonal Manger

Punjab And Sindh Bank

8, Jwala Building, Lal Bahar, Lucknow

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide notification No. I-12012 5 2005 IR(B-11) dated 25-5-2005, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal for adjudication.

2. Whether the action of the management of Punjab & Sindh Bank in terminating the services of Sri Vishal Kumar alias Vishnu Kumar water boy peon with effect from 27-2-2007 is justified and legal? If not to what relief is the concerned workman is entitled?

3. In short the case of the workman is that he was appointed in the month of July, 1990 by the opposite party without any appointment letter against 4th class vacancy. He performed the work of that post regularly for 8 hours in the bank and that he also performed the work of peon which was of a regular and permanent nature still principles of equal pay for equal work was not followed by the opposite party. After taking work from the workman at the branch where he was appointed the opposite party transferred his services from that branch at their extension

counter branch at Guru ka Tal Gurdwara Mathura Road Agra, in the year 1996. At that extension branch the workman apart from the work of peon had also performed the work of clerk and when he claimed in this regard he was told by the officers of the branch that when he is discharging the work of clerk he would automatically be deemed to be a clerk of the bank but despite repeated request made by the workman in this regard he was not issued any appointment letter in this respect by the opposite party bank. The opposite party denied the workman in marking his attendance at the attendance register but he was assured from time to time by the officers of the opposite party that he will be issued regular and permanent employment by issuing appointment letter. The workman has further pleaded that he made repeated request before the officers of the opposite party to declare him a clerk of the branch but they did not pay any heed in this regard. It has also been pleaded by the workman that at the time of termination of his services on 27-2-2002, the workman was neither paid any notice, notice pay or retrenchment compensation by the opposite party therefore, the action of the opposite party bank is in gross violation of the provisions of section 25 F, 25 G and 25 H of the Industrial Disputes Act, 1947, and lastly that it has been prayed by him that he be reinstated in the service of the opposite party with full back wages, continuity of service and with all consequential benefits.

4. The claim of the workman has been refuted by the opposite party on a variety of grounds. It has been pleaded that the applicant has never been appointed by the opposite party bank in any capacity whatsoever. Rather he was a casual employee for undertaking casual job on day to day basis as per requirement and exigencies of work accordingly such casual employment does not create any or vest any right in him to claim any regular tenure in the bank. In view of above question of termination of his services does not arise at all. It is also denied by the opposite party bank that the workman had ever worked about 8 hours on any day. It has also been denied by the opposite party that they ever transferred the workman to its any of the branch. It has also been denied by the opposite party bank that they ever utilized the workman for taking clerical work at the branch or at their extension counter. Lastly the management has denied any relationship of employer and employee between them and the workman and on the above basis it is pleaded that the claim of the workman is devoid of merit and is liable to be rejected as the provisions of Industrial Disputes Act, 1947, are not applicable in the case of the workman.

5. The workman has also filed his rejoinder statement in the case but a perusal of the same would reveal that nothing new has been pleaded in it than what has been pleaded in his statement of claim.

6. Both contesting parties have led oral as well as

documentary evidence in support of their respective cases. There is also joint inspection report filed by the parties.

7. I have heard the contesting parties at length and have also perused the relevant records of the case carefully.

8. It has been argued by the authorized representative for the workman that the workman had worked under the opposite party continuously for years together and has also performed the work of clerical nature apart from performing the job of peon cum water boy and that he was repeatedly given assurance by the concerned officers of the opposite party that he will be soon given appointment order but by way of adopting unfair labour practice he was removed from the service of the bank even without following the provisions of the Industrial Disputes Act. As against it, it has been argued by the representative for the opposite party that the workman was never appointed by the opposite party and that there never existed any relationship of employer and employee and that the workman was engaged by them as a casual employee as per exigency of work and he was paid accordingly on day to day basis and also that they never taken the work of clerical nature from the workman.

9. In view above it has become desirable to examine the fact as to what legal right could be derived in favour of the workman in view of his statement of claim and evidence led by him. In his cross examination the workman has categorically admitted the fact that the post against which he was engaged was never advertised by the bank in the newspapers and on the notice board the manager of the branch had informed to that effect. He further stated that on coming about the vacancy through neither notice board he visited at the branch and that no written examination was ever held in this regard, nor any call letter was issued to him by any of the officer of the branch. He categorically admitted the fact that he was never issued any appointment letter or any transfer letter from New Agra Branch to Guru Ka Tal Gurdwara branch of the bank. Workman has also admitted in his evidence having taken loan for opening shop for Parchoon and has also admitted the documents executed by him in this regard.

10. The attention of the tribunal was also drawn to the joint inspection report dated 13-2-2007 document no. 18/1 available on the record of the case. A perusal of the same would go to reveal the fact that there are certain entries found mentioned in the hand writing of the workman on certain documents of the bank. But that will not entitle him to be declared as a clerk as possibilities cannot be ruled out that the workman might have performed that job in his own hand writing of his own without orders of the seniors in this regard with a view to improve his claim in future. It is settled legal position that if any work is performed without the orders of the competent authority by any person under service rules that will not entitle him for any kind of service benefits. In the joint inspection

report it has also been found that entries on the book of date 3-1-01, 9-1-01, 15-1-01, 18-01-01, 19-01-01, 27-01-01, 09-02-01, 16-02-01 and 17-02-01 are in the hand writing of the workman and it is also clear from the joint inspection report that the record for the period 18-01-02 to 28-02-02 was not made available as the same was not traceable. Certain vouchers have also been inspected for certain period to find out as to whether the workman has completed 240 days of continuous service or not. The vouchers which have been inspected are for the period January 01 to 26-02-02 which certainly goes to prove the fact that the workman has worked for more than 240 days of continuous service under the opposite party bank.

11. The tribunal after giving anxious consideration to the arguments of the workman in the light of his evidence and the joint inspection report is of the confirmed opinion that even if it is proved that the workman has completed for more than 240 days of continuous services as has been established by the joint inspection even then he cannot be given any benefit of the same as first of all it will have to be considered as to whether the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, are applicable in his case and as to whether his case falls within the definition of retrenchment as has been defined under Section 2(s) of the Industrial Disputes Act, 1947, or not.

12. To appreciate the point merely pleadings, evidence and arguments led by the workman is not sufficient without appreciation of the pleadings, evidence and arguments of the opposite party. The crux of the arguments of the management is that the appointment/engagement of the workman is *prima facie* illegal as no officer of the bank is entitled to appoint any person in the bank without following regular selection process. When this argument is viewed in the light of the senior level position under service jurisprudence, the tribunal finds force in the arguments of the opposite party bank. Therefore, when the appointment or the engagement as the case may be, is not in accordance with the service rules, working days of the workman even for even more 240 days may be cannot help to him for the purposes of invoking the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947. Also more to say that it is the specific case of the opposite party bank that there never existed any relationship of master and servant between the parties the workman concerned cannot be covered under the definition of workman as defined under Section 2(s) of the Act. Therefore, in this view of and it is held by the tribunal that the provisions of Industrial Disputes Act are not applicable in the case of the workman, therefore, he cannot be held entitled for any relief whatsoever.

13. The representative for the management has entered certain things in support of their case but all that all are irrelevant to the findings expressed above hence there is no need to take any notice in the present case. The case is decided on the basis of the pleadings and evidence.

240 days of continuous employment and if it is found that his initial engagement or employment is void *ab-initio* he cannot be held entitled for the relief claimed by him.

14. Pin point attention of the tribunal was drawn towards settlement dated 16-10-92, document nos. 143 to 145 available on the record of the case, arrived at between the management of Punjab & Sindh Bank and their workman, by the authorized representative for the workman and it has been argued by him that the case of the workman clearly falls within the ambit of the settlement hence he should be granted relief of reinstatement for the grounds mentioned in his statement of claim. Of course, there is neither any pleadings nor any evidence on behalf of the workman nor there is any rebuttal by the opposite party bank yet the tribunal after going through the provisions of the settlement finds that according to clause of the settlement it is provided, that those employees who have completed 240 days in the preceding 12 months to be reckoned from the date of lost served or in any other block of 12 consecutive months commencing from 15-04-80. Their inter-se seniority would be determined, on the basis of day on which they worked first as temporary employee as per banks available record. The settlement further provides that other employees not falling in the above category but have at least worked for 90 days from 01-01-82. The arguments advanced by the representative cannot be given any favour according to the own claim of the workman when it is the specific case of the workman that he entered in the services of the bank for the first time in the year 1990. There is clear cut mention of cut of date 15-04-80, upon whom the provisions of the above settlement are applicable and also it has been provided that persons at least have worked for 90 days from 01-01-82 only their cases the provisions of settlement are applicable and not otherwise.

15. When the case is examined in the light of the above provisions it is quite obvious that he for the first time entered in the services of the bank as claimed by him without any appointment letter or without exercise of selection process in the year 1990. It is true that the candidates falling under the settlement, in their case, the point whether they have been appointed after selection process or not has become redundant. What was required was that they should satisfy the condition laid down in the above settlement. As it is the own case of the workman that he entered in the services of the opposite party bank in the year 1990, therefore, the provisions of the said settlement is not applicable in his case and therefore, he cannot be allowed any benefit of the same. From this point of view the workman is not entitled for any relief on account of the settlement dated 16-10-92.

16. Be that as it may it is settled provision of law that pleading not pleaded in the plaint or statement of claim and no evidence on the point has been given by any party cannot be argued at stage of arguments and courts are not

bound to consider those arguments considering the same outside the scope of the case file. In the instant case no such pleadings or evidence on the point of settlement have been raised by the workman in his support, therefore, he cannot be held entitled for any kind of benefit out of settlement dated 16-10-92.

17. Accordingly for the discussions recorded above, it is held that the workman is not entitled for any relief as claimed by him as he has palpably failed to establish the fact that his employment was in accordance with the prescribed recruitments rules, therefore, his working more than 240 days cannot improve his case at all and that the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, are not applicable in his case.

18. Lastly the reference is bound to be answered in favour of the opposite party and against the workman. Ordered accordingly.

R. G. SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

क्र.आ. 3140.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम मंत्रालय, कानपुर के पंचाट (संदर्भ सं. 33/2003 एवं 13/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 31-10-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/122/2003-आई आर (बी-II)] और

[सं. एल-12011/163/2004-आई आर (बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 3140.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 33/2003 and 13/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Bank of Baroda and their workmen, received by the Central Government on 31-10-2008.

[No. L-12011/122/2003-IR(B-I)] and

[No. L-12011/163/2004-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI R.G. SHUKLA, PRESIDING OFFICER,
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, KANPUR

Industrial Dispute No. 13 of 2005 and 33 of 2003

In the matter of dispute between—

The Deputy General Secretary
U.P. Bank of Baroda Empls. Union
C/o Bank of Baroda Block
Kidwai Nagar, Kanpur

AND

The General Manager
Bank of Baroda
Baroda Corporate Centre
C-26, G Block, Bandra Kurla Complex Bandra (E)
Mumbai.

AWARD

1. Central Government, Ministry of Labour, New Delhi vide notification No. L-12011/163/2004-IR(B-II) dated 21-04-2005 (in I.D. No. 13 of 2005) and also vide notification No. L-12011/122/2003-IR(B-II) dated 23-09-2003 has referred the following dispute to this tribunal for its adjudication—

2. In I.D. No. 13 of 2005 schedule of reference is to the effect that whether the action of the management of Bank of Baroda in not regularizing the services of 41 workers mentioned in the Annexure A enclosed by union vide representation dated 01-09-2003 and not allowing them facilities/benefits as per Bipartite Settlement, is justified and legal? If not to what relief the workmen concerned are entitled to?

3. In I.D. No. 33 of 2003 schedule of reference is to the effect whether the action of the management of Bank of Baroda in not regularizing the services of S/Sh. Ramveer Singh, Raj Mohan Bajpai, Awadhesh Kumar, Hari Kishan, Preadeep Kumar Singh, Prabhakar Tripathi, Ajai Pal Singh, Ram Parkash, Surya Prakash Tiwari, Sinil Kumar Samant, Daya Ram Verma and Ravi Shanker Verma from the date of their appointment is legal and justified? If not what relief the concerned workmen are entitled to?

4. As common question of law and facts are involved in the above industrial dispute cases, therefore, it is proposed to dispose of them by means of this common award.

5. It is not necessary to give full details of the case as after the exchange of pleadings between the contesting parties when the case was taken up for hearing 19-08-2008 at camp Lucknow, the representative for the union moved an application to the effect that the union do not want to press the above cases as a settlement on absorption of temporary employees has been arrived at between the union and the management of Bank of Baroda. The representative for the union has also filed copy of the settlement before the tribunal. The representative for the management has not objected to it.

6. Therefore, both the I.D. Cases are being disposed off as withdrawn having regard to the request of the representative for the union and in terms of settlement, a copy of which shall form part of this award.

R.G. SHUKLA, Presiding Officer

बैंक ऑफ बड़ोदा Bank of Baroda

BCC/HR/100/76

24th March, 2008

**CIRCULAR LETTER TO ALL BRANCHES OFFICES
IN INDIA**

Issued By

Baroda Corporate Centre, HRM Dept., Mumbai

Dear Sir,

Re: Tripartite settlement dated 18-03-2008 under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the management of Bank of Baroda and All India Bank of Baroda Employees' Federation (Recognised Union) before the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai in the matter of absorption of casual temporary Peons Sweepers.

We are pleased to inform you that the issue relating to absorption of casual temporary Peons Sweepers has been resolved by signing a Tripartite Settlement with the All India Bank of Baroda Employees' Federation (recognized union) in presence of Dy. Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai under Section 12(3) of Industrial Disputes Act, 1947. A copy of the said Tripartite Settlement dated 18-03-2008 is enclosed for your information, record and reference.

Detailed operative guidelines on the modalities of absorption, wherever applicable, would be communicated through concerned Regional Head.

Yours faithfully,

(DIPANKAR MOOKERJEE),
General Manager (HR & Marketing)

Enclata.

plgn-br circular- to settlement(mar08)ja

Case No. 7(1)2008.H.1

Memorandum of settlement arrived at between the management of Bank of Baroda and their workmen represented by All India Bank of Baroda Employees' Federation (Recognised Union) under, Section 12 (3) of the Industrial Disputes Act, 1947 during the course of conciliation proceedings held on 18th March, 2008 before the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai.

SHORT RECAPITULATION OF THE CASE

The All India Bank of Baroda Employees' Federation, Mumbai, (hereinafter referred to as "the Federation") vide its letter dated 28th January, 2008, raised an Industrial Dispute against the Management of Bank of Baroda, Mumbai, over the issue of absorption of casual temporary persons working as Peons Sweepers and requested the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai, to intervene in the matter for resolution of the dispute. The matter was seized in conciliation by the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai and conciliation

proceedings were held on 30th January, 2008 and onwards on different dates.

In course of the discussions/conciliation proceedings, it transpired that:

- (a) The branches offices engaged temporary/casual persons during the leave absence vacancies of permanent Peon Sweeper without following prescribed rules/guidelines of the Bank. Over a period of time such temporary/casual engagement of persons continued for longer duration giving rise to demand by the Federation for their absorption. As it was an industry-wide phenomenon, the Government of India, after examination, came out with an "Approach Paper" for absorption of such temporary/casual persons. In terms of the said "Approach Paper", 647 temporary Peons Sweepers who had worked for 90 or more days between 01-01-1982 and 31-12-1989 were absorbed in Bank's service in the year 1995.
- (b) Even after absorption of such casual/temporary persons, engagement of casual temporary persons as Peon Sweeper at various branches/offices of the Bank had continued necessitating the Bank to review the matter for resolving the issue.
- (c) The Bank has signed a Tripartite Settlement on 20-02-2008 under Section 12(3) of the Industrial Disputes Act, 1947 before the Assistant Labour Commissioner (Central), Kolkata with Bank of Baroda Karmachari Samity, Paschim Banga (affiliated to recognized AIBOBEF), Eastern Regional Council of Bank of Baroda Employees' Association (BEF) and Bank of Baroda Eastern States Employees' Association (AIBEA), in the matter of abolition of Canteen Boy System and absorption of temporary/casual persons who are sponsored by Employment Exchange engaged as Full Time/Part time Canteen Boy/Sweeper.
- (d) The All India Bank of Baroda Employees' Federation is the recognized majority Union and sole collective bargaining agent for workmen in the Bank. Further, the Tripartite Settlement dated 1st September, 1973 provides that agreement on all India issues, except the wages and service conditions, which are settled at industry level, are to be reached with the All India Bank of Baroda Employees' Federation.
- (e) The issue was discussed threadbare, both bilaterally between the Federation and the Management of the Bank and also in course of the conciliation proceedings held on several dates and after protracted discussions held on 18-03-2008 before the undersigned, both the parties agree to settle the dispute on the following terms of Settlement.

Now, it is hereby agreed and declared by and between the parties hereto as under :-

TERMS OF THE SETTLEMENT:

This Settlement will be applicable to all branches/offices of the Bank in India and shall come into force immediately subject to the terms and conditions mentioned hereunder :

1. The Canteen boy system, wherever in existence in the Bank, is abolished and henceforth, no Canteen Boy will be recruited/engaged either on permanent basis or on casual/temporary basis.

2. Subject to Clause 3, Casual/temporary Peons/Sweepers shall be absorbed in Bank's service in phased manner as under :

Phase - I :

The following category of casual/temporary Peons/Sweepers will be absorbed in Phase-I before 30th June, 2008.

- (a) Casual/temporary Peons/Sweepers who had worked for 90 or more days between 1-1-1982 and 31-12-1989 and are still working.
- (b) Casual/temporary Peons/Sweepers who had worked for 90 or more days between 1-1-1990 and 31-12-1990 and are still working.

Phase-II :

Casual/temporary Peons/Sweepers who have worked for 240 days or more in consecutive-12-months between 1-1-1991 and 29-2-1996 and are still working will be absorbed in Phase-II during the financial year 2008-09.

Phase-III :

Casual/temporary Peons/Sweepers who have worked for 240 days or more in consecutive-12-months between 1-3-1996 and 28-07-2007 and are still working will be absorbed in Phase-III during the financial year 2009-10.

3. Absorption of casual/temporary Peons/Sweepers will be in phases, as above and will be subject to the following conditions :

- (a) Casual/temporary Peons/Sweepers should fulfill the eligibility criteria viz. age and qualification as on the first date of engagement in the Bank.
- (b) Found medically fit for recruitment in Bank's service.
- (c) Absorption shall be with prospective effect i.e. from the date mentioned in the letter of absorption to be issued by the Competent Authority.
- (d) Such casual/temporary Peons/Sweepers will be

absorbed in their respective wage scale and on their absorption shall be fitted in the first stage of full time/part-time scale wages, as the case may be, viz. casual/temporary persons working as 1/3rd, 1/2, 3/4th and Full-time Sweepers shall be absorbed as 1/3rd, 1/2, 3/4th and full-time Sweepers, respectively. However, the casual/temporary persons who are presently being engaged as Peon but had earlier worked as Full-time/Part-time Sweepers will be absorbed as "Sweeper-cum-Peon" as per requirement and at the sole discretion of the Bank.

- (e) No arrears of wages salary, seniority or any other benefit shall accrue to such casual persons on their absorption and such casual/temporary persons shall not claim any such benefits for their past service/engagement with the Bank as casual/temporary person.
 - (f) Deployment/placement of such casual/temporary Peons/Sweepers on their absorption in Bank's service shall be at the sole discretion of the Management depending upon its requirement, within the State. However, Bank will endeavour to keep such displacement to the minimum as per requirement.
 - (g) Seniority of such casual/temporary Peons/Sweepers, on absorption, shall be reckoned in their respective cadre/scale wage from the date of their absorption in Bank's service.
 - (h) Absorption is subject to their good conduct and verification of their antecedents.
 - (i) The concerned casual/temporary persons and/or concerned employee's Organizations/Unions/Association shall withdraw all cases pending before the Conciliation Officer/Labour Court/Central Government Industrial Tribunal/High Court/Supreme Court or any other Judicial authority.
4. Both the parties agreed that :
- (a) The Government guidelines with regard to reservation of posts for SC, ST, OBC, etc. shall be applicable for absorption of casual persons.
 - (b) It is specifically agreed that all casual/temporary Peons/Sweepers, who are covered under this Settlement for absorption shall submit individual undertaking as per Annexure 'A' to this Settlement agreeing to the terms and conditions stipulated in Clause 3 above, before consideration of their

request for absorption. Any conditional undertaking or undertaking in any other format and/or refusal to the order of placement/deployment shall be deemed as refusal to absorption by such concerned casual/temporary person and in such an event their claim for absorption shall not be considered, thereafter.

- (c) Casual/Temporary Peons/Sweepers who are absorbed in Bank's service under this Settlement will be liable to be terminated from Bank's service in case it is found at any time that he made false declaration in the undertaking as per Annexure "A" or he submitted false fake document support of his educational qualification, age, caste, etc.
- (d) It is clearly understood that this Settlement will not be applicable to the persons engaged on casual/temporary basis after 28-07-2007 or who has not completed 240 days in a period of consecutive 12 months preceding 28-07-2007. Also, the Unions will not claim or file cases in respect of casual/temporary persons who are not working engaged at present and/or not absorbed under Clause 2 above of this Settlement.
- (e) The Bank may extend/defer the process of absorption of casual/temporary persons beyond the time limit stipulated under Clause 2 above for a maximum period of 90 days for cogent reasons and in such event the Federation will be consulted.
- (f) Casual temporary persons who will be absorbed under this Settlement will not be eligible for promotion to Clerical cadre for a period of 5 years from the date of absorption.

5. All past and present claims/cases of casual temporary persons and/or Employees' Organizations are hereby resolved.

6. Save and except tripartite Settlement dated 20-02-2008, this Settlement supersedes all previous understandings/agreements/settlements/practices, local, regional, zonal or otherwise and the Unions will not raise any issue/demand in respect of matters covered under this settlement.

Both the parties shall submit implementation report within 30 days of the phase-wise time limit stipulated in Clause 2 of the Settlement with objection thereto, if any, failing which it will be construed that the terms of this Settlement have been fully implemented.

SIGNATORIES TO THE SETTLEMENT

Representatives of Management of Bank of Baroda.

Shri Dipankar Mookerjee
General Manager (HR
& Marketing)

Shri J.D. Khanna
Dy. General Manager
(HRM & Admn.)

Shri C.V. Chandrashekhar
Dy. General Manager
(HRnes, HRD & IL)

Shri Mukesh Garg
Asstt. General Manager
(HRM)

Shri K.C. Pati
Asstt. General Manager
(HRM & IL)

Shri Pradeep K.G. Niyogi
Senior Manager (HRM)

Representatives of All India Bank of Baroda Employees' Federation.

Shri A.K. Jain
President

Shri Milind Nadkarni
General Secretary

Shri Vinod Saxena
Deputy General Secretary

Shri V.P. Mahajan
Deputy General Secretary

Shri K.J. Ramanathan
Deputy General Secretary

Shri R.G. Raut
Deputy General Secretary

Shri Karimesh Shukla
Joint Secretary

BEFORE ME,

(B.S. Pawar)

Conciliation Officer under

Industrial Disputes Act, 1947 &

Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Mumbai

WITNESSES:

1. Shri V.M. Sawant
Asstt. Labour Commissioner (Central)

2. Shri Ganapati Bhan
Asstt. Labour Commissioner (Central)

The following Office Bearers of the All India Bank of Baroda Employees' Federation (Recognised Union) are signatory of this settlement.

Shri N. B. Dandiwala
Treasurer

Shri M. J. Shah
General Secretary, Anand Unit

Shri Shri Dilip Brahmabhai
General Secretary, Ahmedabad Unit

Shri V. Ramakrishna,
General Secretary, A. P. Unit

Shri K. K. Verma
General Secretary, Bihar & Jharkhand Unit

Shri Magan Patel,
General Secretary, Baroda Unit

Shri Naresh Chaddha,
President, Delhi Unit

Shri R. V. Keni,
President, Goa Unit

Shri K. J. Yunga,
General Secretary, Karnataka

Shri Suresh Pai,
General Secretary, Kerala Unit

Shri R. M. Kudale,
Secretary, Maharashtra Unit

Shri P. G. M. Panicker,
General Secretary, MP & C G Unit

Shri Sudip Sen,
General Secretary, Nagaland Unit

Shri Raj Sharma,
General Secretary, Punjab Unit

Shri Subir Chatterjee,
General Secretary, West Bengal Unit

Shri P. L. Biswal,
General Secretary, Orissa Unit

Shri A. R. Suryanarayanan,
General Secretary, T. N. I. Unit

Shri John Peter,
General Secretary, T. N. II Unit

Shri Subir Chatterjee,
General Secretary, West Bengal Unit

Shri Ashok Varma,
Jt. Secretary

Shri K. K. Kotian,
Jt. Secretary

Shri N. Venugopal,
Jt. Secretary

ANNEXURE—"A"

The Competent Authority,
Bank of Baroda,

Dear Sir,

Re: Undertaking in terms of Clause 4(b) of the Settlement dated 18th March, 2008 on Absorption of Casual/temporary persons engaged as Peon/Full-time/Part-time Sweeper

I have read and clearly understood the provision of the Settlement dated 18th March, 2008 and do hereby

accept the terms and conditions mentioned therein.

I am covered under the said Settlement dated 18th March, 2008 for absorption in Bank's service as Peon/..... Scale Wage Sweeper.

I am working as Casual Peon/full-time/part-time Sweeper in the Bank since Details of my casual/temporary engagement is as under :

Sl. No.	Branch/Office	From	To	Total no. of days	As Peon/PTS/FTS
1.					
2.					
3.					
4.					

I am enclosing herewith the following documents, in original, along with 2 attested copies of the same in support of my age, educational qualification, caste, etc. :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

I hereby submit undertaking that :

- (a) I shall not claim/demand any benefit whether monetary or otherwise from 'the Bank' relating to my casual/temporary engagement in the Bank for the period prior to the date of my absorption in Bank's service before any Authority/Court, in future.
- (b) I shall not raise any dispute before any Authority/Court relating to my placement/deployment on absorption in Bank's service.
- (c) In case subsequent to my absorption in Bank's service, if it is found that declaration made with regard to period of engagement is found to be false or any of the documents submitted by me in support of age, qualification, caste, etc., is false/fake/forged, I will be liable to be terminated from Bank's service.

I am submitting this irrevocable undertaking after fully understanding the provisions of the aforesaid Settlement dated 18th March, 2008, and implication thereof.

Yours faithfully,

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2008

का. आ. 3141.-औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार पंजाब एण्ड सिंध बैंक के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कार्यकारों के बीच, अनुबन्ध में निहित औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/थर्म न्यायालय कानपुर को वरत (संदर्भ सं. 91/2000) को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 31-10-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल. 12012/88/2000-आई 357 (खो-11)]

राजिन्द्र कुमार, डी. ज. अधिकारी

New Delhi, the 31st October, 2008

S.O. 3141.-In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 91/2000) of the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, Kanpur as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Punjab & Sindh Bank and their workman, which was received by the Central Government on 31-10-2008.

[No. T-12012/88/2000 IR (B-11)]

RAJINDER KUMAR, D.J. Officer

ANNEXURE

BEFORE : SRI R.G. SHUKLA, PRESIDENT JUDGE
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL
TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT, SARAN
BILAVANATI CAMPUS UDYOG NAGAR, KANPUR
I.D. No. 91/2000

Sri Rajendra Prasad Mishra Son of Sri Sora; Prasad Mishra
Through Lalsi Ram 116/14, Rawapur Village, Haryenda

And

The Senior Manager Punjab & Sindh Bank Limited, Office
Haryenda Nagar, Kanpur

AWARD

1. Central Government M.O., New Delhi are then notification No. T-12012/88/2000 IR (B-11) dated 17.10.2000, has referred the following dispute for adjudication to this tribunal.

2. Whether the action of the management of Punjab & Sindh Bank in terminating the services of Sri Rajendra Prasad Mishra w.e.f. 28-9-99, is legal and justified? What is what relief the concerned workman is entitled to?

3. The case in short as set up by the workman in his claim statement is that he was engaged on the basis of oral instructions of the opposite party no. 2 at the post of peon in the year 1998 at the rate of Rs. 1200 per month and that having regard to the work and conduct of the workman the opposite party enhanced the rate of his wages to Rs. 1350 per month. It is further alleged by the applicant that he

reported at the place of duty on 28-09-99 but the then branch manager did not permit him to discharge his duties and at verbal instructions of the said manager that he was sacked. It was determined with notice from 28-09-99. It has also been alleged by the applicant that at the time of the termination of his services he was not given any notice pay nor the retrenchment compensation. Therefore, the dispensation of his service by the opposite party is nothing but an illegal retrenchment in violation of the provisions of Industrial Disputes Act, 1947 and therefore it has been prayed that he be reinstated with continuation of the appropriate wages with full back wages for the period of service and all other consequential benefits.

4. On the contrary the claim of the workman has been vehemently refuted by the opposite party by filing detailed reply wherein it has been pleaded by them that the cause of action of the claim is alleged that the workman has been retrenched upon termination of his employment is incorrect, that the termination of his employment by the opposite party on 28-09-99, terminating his service and dispensation of his service from the date of termination date of his service is not correct and the relationship of employer and employee between the opposite party and the claimant has never been terminated. It is further alleged by the opposite party in any point of time it has ever terminated the service of the alleged claimant, that the applicant was not engaged by the opposite party as peon as claimed by him and in fact the applicant was engaged as a casual labour w.e.f. 5-4-99 by the opposite party at their Haryenda Nagar Branch at Kanpur and the applicant was paid wages on the basis of day to day work; that it is denied by the opposite party that he was ever denied to work on 28-09-99 by the opposite party; it is also denied by the opposite party that the applicant was returned from his home by the branch manager of the opposite party on the ground that his services have been terminated; that the opposite party and regulations for providing regular employment to applicant in the service of the opposite party and the applicant had never subjected through any selection process therefore he has no legal right to claim employment in the services of the opposite party on the basis of the same it has been claimed that the claimant's petition is rejected as there is no merit in the claim of the workman being a casual and daily rated employee.

5. The statement of the dispute in which nothing new has been brought in except reiterating the facts already pleaded by the parties in their pleadings.

6. After examining the pleadings between the parties both parties have filed documentary evidence in support of their respective claims as well as they have also adduced oral evidence.

7. I have heard the arguments of both contesting parties at length and have gone through the records of the case carefully.

8. Now first of all it will be seen as how far the workman has been able to establish his claim for his reinstatement. The workman in his evidence has categorically admitted the fact that he was neither issued any appointment letter nor any written order by means of which his services stands terminated. It has also come in evidence that he was never paid his wages as was being given by the opposite party to their regular and permanent employee. It has also come in the evidence of the workman that an application was invited from through the branch manager of the branch but at this stage it may be point out that no officer of the bank is empowered to engage any employee without undergoing through regular and permanent selection process and any appointment made by any officer of the bank it can safely be held that such appointments are by way of back door entry.

9. Workman has also filed certain documents in support of his claim but a perusal of the same would go to indicate that they are not sufficient to improve the claim of the workman in any manner or to prove that the workman had ever completed 240 days of continuous service within the meaning of Section 25B of the Act. Even the workman in his pleading or in his evidence has not stated anything regarding breach of any of the provisions governing the service conditions of the employees of the bank, therefore, the provisions of the act cannot be applied as a straight jacket formula for claiming relief under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947, by simply stating that the provisions of the Act have been breached in the case of the workman.

10. The position that no one can claim appointment in public employment on the strength that he had rendered certain days of service either on casual basis, temporary basis or ad-hoc basis has finally been set at naught in the leading case of Smt. Uma Devi by the Hon'ble Supreme Court of India, wherein it has clearly held that a casually, daily rated employee, temporary employee or even an ad-hoc employee has not right to claim employment or absorption in service unless he has been selected through regular selection process under recruitment rules.

11. In view of above position when the claim of the workman has not been found within the purview of the provisions of Industrial Disputes Act, it cannot be held that the services of the workman had been terminated by the opposite party bank at any point of time and being so when the claim of the workman fails from his own pleadings, evidence there remains hardly any need to discuss the pleadings and of the opposite party bank.

12. Thus from the discussions made above, it is held that the provisions of ID Act are not at all applicable in the case of the workman and if it is so it cannot be held that the opposite party have flouted any of the provisions of the Act and being so the workman cannot be held entitled for grant of relief as claimed by him.

R.G SHUKLA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2008

का. आ. 3142.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार आपी स्कूल के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-2, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 1256/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/12/2005-आई आर (डीयू)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd November, 2008

S.O. 3142.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1256/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. II Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Army School and their workman, which was received by the Central Government on 3-11-2008.

[No. L-14012/12/2005-IR(DU)]
AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-II, SECTOR 18- A, CHANDIGARH.

PRESIDING OFFICER: SHRI KULDIP SINGH

Case I. D. No. 1256//2K6

Registered on : 16-2-2006

Date of Decision : 16-10-2008

Shri Sita Ram Son of Shri Chait Singh r/o House No. 344,
Dhiru ki Majri, Patiala. ...Petitioner

Versus

The Principal, Army School, 40, Baradari, Patiala.

...Respondent

APPEARANCE

For the Workman : Messrs K. L. Behl and Gurdip
Singh, Advocates

For the Management : Mr. M. R. Dhiman, A. R.

AWARD

The workman is not present. Mr. Gurdip Singh representative of the management is present. He states that the parties have compromised in the case as well as in all matters pending between them at different forums. He has placed on record certified true copies of the application of the workman, his statement and that of the order of Presiding Officer, Labour Court Patiala. The combined reading of these documents show that the parties had litigation in different courts; and that the workman has received Rupees 25,000 compensation as full and final settlement of all his claims against the management. The

workman is not present to deny this fact. It is to be presumed that the workman is absent as his claim has been settled.

Government of India, Ministry of Labour vide their Order No. L-14012/12/2005-IR (DU) dated the 26th December, 2005 referred the following dispute for the adjudication of this Tribunal:

Whether the action of the management of the Army School, Patiala in terminating the services of Shri Sita Ram, Ex-Mali w.e.f. 14-9-2004 without complying with the provisions of Sections 25-F, G, and H of the I. D. Act, 1947 is legal and justified? If not, what relief the workman is entitled to and from which date?

On a notice of reference, the parties appeared and filed their pleadings and supported the same with the affidavit of workman and of Gurdeep Singh I.D. of the management. They also placed on record photo copies of a number of documents, some at their own and some on the application of the workman. The matter was to be listed for the evidence of the workman when the process development has taken place. So far there has come no evidence on record to support the claim of the workman which has been denied by the management. Since the workman has chosen not to appear in the case and there is nothing to doubt the claim of the management that the parties have settled the disputes at their own, I find no evidence on record to support the claim of the workman. Therefore, there is nothing to show that the management had terminated the services of the workman in violation of provisions of Section 25-F, G and H of the I. D. Act, 1947 as he is not entitled to any relief. The award is passed against him in these terms.

Let the copy of the award be sent to the Appropriate government for necessary action and the file be consigned to records after due completion.

KULDIP SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2008

का. आ. 3143.- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसारण में केन्द्रीय सरकार, भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन और संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकाधिक, चण्डीगढ़ के पंचायत (संदर्भ सं. 163/2K5) को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 3-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/304/1997-आई आर (सी)-1, 1]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd November, 2008

S.O. 3143.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 163/2K5) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Chandigarh, as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of FCI and their workman, which was received by the Central Government on 3-11-2008

[No. L-22012/304/1997-IR(C-1)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

नई दिल्ली

CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-
CUM-LABOUR COURT, SECTOR 38-A,
CHANDIGARH

PRESIDING OFFICER: ANKUL DIPSINGH

Case I. D. No. 163/2K5

Registered on : 1-8-2006

Date of Decision : 16-10-2008

Shri Jatinder S/o of Nola Singh s/o Hari Gaur Dist. Ind.
...Petitioner

...Respondent

District Manager, FCI, Patiala

...Respondent

APPEAL SETT

For the Workman : Mr. Anil Parkash Sharda, Advocate

For the Management : Mr. Anand Kumar Jain, Advocate

The Ministry of Labour, Government of India, referred the following dispute for the adjudication of this Tribunal vide their No. L-22012/304/1997-IR(C-1) dated 27th of Feb., 1998.

Notice Ref.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India, Rohtak in dispensing the services of Shri Jatinder, workman w.e.f. 1-5-1997 is just and legal? If not, what relief the workman entitled to?"

The notice of the reference was given to the parties who appeared through their counsel and filed their respective claims in the claim of statement of claim and reply of the management. The management placed on photo copies of a number of documents in support of their claim. The parties also tendered affidavits of persons they desired to produce in the case in support of their respective claims.

The case was being adjudged on the evidence of the workman and the records of the file shows that the workman did not appear for his statement right from the day he was given chance to produce the evidence. Even before that he did not attend the case personally on any day right from 11-10-2007. Ultimately a registered notice was sent to him vide postal receipt No. 2821 w.e.f. 1-8-2008. So far neither the notice sent has been received back unserved nor the workman has appeared to prosecute his case. This shows that he has lost interest in the prosecution of his case. In support of his claim the management had dispensed with his services w.e.f. 1-5-1997 and their action was unjust and illegal. The workman has not produced any evidence. The management has denied its claim in toto, duly supported by the affidavits of its witnesses. Therefore, the workman is not entitled to any relief. The reference is answered against him and the award is passed.

Let the copy of the award be sent to the Appropriate government for necessary action and the file be consigned to records after due completion.

KULDIP SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3144.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नाजिम दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर के प्रबंधन के संबद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय अजमेर के पंचाट (संदर्भ सं.) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 3-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/35/99-आई.आर. (डी.यू.)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 3rd November, 2008

S.O. 3144.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award of the Industrial Tribunal/Labour Court, Ajmer as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Najim Dargah Khawja Sahab, Ajmer and their workman, which was received by the Central Government on 3-11-2008.

[No. L-42012/35/99-IR (DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

अनुबंध

न्यायालय श्रम एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण, अजमेर(राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री मिथिलेश कुमार शर्मा,

आरएचजेएस

प्रकरण संख्या-सोआईटीआर 08/01

[रिफरेंस नं. एल-42012/35/99-आईआर (डी यू.)]

दिनांक 22-5-01]

कैप्टन मो.कालू खां भट्टार टेकरी, कुंदननगर, अजमेर(राज.)

...प्राथी

बनाम

नाजिम, दी नाजिम दरगाह ख्वाजा साहिब, अजमेर

...अप्राथी

उपस्थित: श्री पी.डी.खन्ना, अधिवक्ता, प्राथी।

श्री वी.डी.भारगव, अधिवक्ता, अप्राथी।

दिनांक : 23-9-08

अवार्ड

1. केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित विवाद निम्न प्रकार है:-

Whether the management of Najim Dargah Khawja Sahab is an Industry under sec 2 (j) of the I.D. Act, 1947 If so whether the action of Najim Dargah Khawja Sahab Ajmer in terminating the Services of Capt Mohd Kalu Khan (Retd) Ex receptionist Guest House and security Incharge without payment of

retrenchment Compensation is just and valid? if not what relief the workman is entitled to?

2-प्राथी पक्ष ने अपने क्लेम के विवरण में अंकित किया है कि उसका सेवा समाप्ति आदेश दि. 24-4-95 को निरस्त किया जाकर उसी दिनांक से निरंतर स्थाई कर्मचारी के वतनमान के पद पर नियमित मानते हुए वेतनमान व पिछले वेतन सहित सभी भत्तों तथा कॉंसीक्यूशनल लाभ के साथ 8 प्रतिशत ब्याज सहित रॉस्टेट करने के आदेश को मांग की है। साथ ही समय-समय पर स्थायी वेतनमान में की गयी बढ़ोतरी का एरियर सहित तथा ब्याज, मुकदमों का खर्चा व अन्य शहस को उचित हो भी दिलावने की मांग की है। क्लेम में संशोधन व परिवर्तन के अधिकार को भी सुरक्षित रखने का निवेदन किया है क्योंकि प्राथी की नियुक्ति अप्राथी के अधीन जमादार के पद पर दि.10-7-93 को जरिये नियुक्ति पत्र हुई थी जिसमें उस स्थाई वेतन 240 रु. प्रतिमाह देना अंकित किया है। आगे अंकित किया है कि उसने इमानदारी से लगभग 24-4-95 तक इचूरी दी जब दिनांक 21-2-94 को उसका स्थानांतरण रिसेप्शनिस्ट गैस्ट हाऊस के पद पर का दिया। आगे अंकित किया है कि अप्राथी ने अचानक दि.24-4-95 को बिना किसी कारण बिना किसी जांच के अर्द्ध रूप से सेवार्थे समाप्त कर दी और बताया कि 1775 रु. का चेक प्राथी को दे दिया। आगे अंकित किया है कि उसने सेवा समाप्ति को अपील अध्यक्ष को भी की किंतु आश्वासन देते रहे और अपील पर आज तक आदेश नहीं करना भी बताया है। आगे अंकित किया है कि प्राथी ने अप्राथी की पोल खेल रखी थी जो अप्राथी को बर्दाश्त नहीं रही थी इस कारण से उसे सेवा से बर्खास्त करना बताया है। अंत में प्राथी ने स्वयं को सेवा-मुक्ति आदेश को आई.डी.एक्ट की धारा 25एफ, जी, का उल्लंघन बताया हुए, कोई वरिष्ठता सूची नहीं निकालने, व बारह माह में 240 दिन तक कार्य करने के कारण चुनौती देना अंकित किया है। अंत में प्राथी ने स्वयं को सेवा समाप्ति से बेरोजगार होना भी बताया है।

3. अप्राथी पक्ष ने अपने जवाब में प्राथी पक्ष द्वारा क्लेम में उल्लिखित तथ्यों का खंडन करते हुए प्राथी के क्लेम को खारिज कर अवाई अप्राथी के पक्ष में पारित करने का निवेदन किया है क्योंकि प्राथी की नियुक्ति बतौर जमादार निश्चित वेतन पर पूर्णतया अस्थायी रूप से की गयी थी, प्राथी के खिलाफ कई शिकायतें रिश्तत लेने, काउंटर पर रिफंड नहीं लौटाने आदि की थी। आगे अंकित किया है कि प्राथी की सेवायुक्ति विधि अनुसार जरिये चेक 1775 रु. भुगतान करके दि.24-4-95 को करना बताया गया है। आगे अंकित किया है कि प्राथी के खिलाफ कई शिकायतों के कारण अप्राथी संस्थान की बदनामी हो रही थी। आगे अंकित किया है कि आई.डी. एक्ट के प्रावधान प्राथी के मामले में लागू नहीं होते। विरोध कथन में अंकित किया है कि अप्राथी संस्थान धार्मिक/चौरटवल है जो बिना लाभ के कार्य करती है इसलिए वाणिज्यिक श्रेणी में नहीं आने से आई.डी. एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होने से स्वयं को इंडस्ट्री की परिभाषा में नहीं आने के कारण, प्राथी के क्लेम को मय खर्चे निरस्त करने को अंत में प्रार्थना की है।

4.उपरोक्त क्लेम तथा जवाब पर दोनों पक्षों को सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अभिभावक प्राथी को

1. ए.आई.आर. 1956 (एस.सी.) पेज नं. 231 जे.के. आयरन और स्टील कं. लि. कानपुर बनाम आयरन एंड स्टील मजदूर यूनियन, कानपुर

2. 1974 लैब आई.सी. 166 ग्लैक्सो लेबोरेटरीज इंडिया लि. अलीगढ़ बनाम ग्लैक्सो स्टाफ एसोसिएशन व अन्य

- जिनमें यह स्पष्ट किया गया है कि श्रम न्यायालयों पर दीवानी न्यायालयों संबंधी तकनीकियां लागू नहीं होती हैं लेकिन फिर भी सामान्य सिद्धांतों को लागू करना चाहिए।

3. 2004 (4) डब्ल्यू. एल.सी. पेज नं. 357 श्रीमति कृष्णा खंडेलवाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

4. 2004 (4) डब्ल्यू. एल.सी. 241 ए. भंवरलाल बनाम गोखाराम व अन्य

- जिनमें जो तथ्य अभिवचनों में नहीं हैं उसके संबंध में पेश की गयी साक्ष्य पर विचार नहीं करना चाहिए और न ही उस बिंदु पर बहस की अनुमति देने के संबंध में।

5. ए.आई.आर. 1966 पेज 1861 भगतसिंह व अन्य बनाम जसवंत सिंह।

- जो तथ्य बचाव में नहीं उठाया गया है, उस बिंदु पर पेश की गयी साक्ष्य निरर्थक माने जाने के संबंध में तथा राज. इंडस्ट्रियल रूल्स 1956 के नियम 10(बी) का भी हवाला दिया है।

10. जबावी बहस में विद्वान अभिभावक प्राथी की यह भी दलील है कि जो तथ्य वैधानिक है उनकी अभिवचनों में वर्णित करने की आवश्यकता नहीं होती है और तथ्यात्मक बिंदुओं पर ही अभिवचन न्यायालय में प्रस्तुत किये जाते हैं, इस कारण अप्राथी उद्योग होने के संबंध में अभिवचनों में प्राथी द्वारा वर्णित नहीं किया जाना और इस संबंध में उठायी गयी आपत्ति असंगत माने जाने की दलील दी है।

11. उपरोक्त दलीलों के संदर्भ में मैंने पत्रावली का अध्ययन किया तो पाया कि सर्वप्रथम इस न्यायालय द्वारा तय किया जाने वाला बिंदु यह है कि क्या मैनेजमेंट नाजिम ख्वाजा दरगाह सहिब धारा 2 (जे) आई.डी. एक्ट के अंतर्गत उद्योग की श्रेणी में आता है?

12. इस संदर्भ में प्राथी की ओर से जो तथ्य अपने वलम में वर्णित किये हैं, उनमें ऐसा कोई भी तथ्य वर्णित नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट होता हो कि किन आधारों पर यह उद्योग की श्रेणी में आता है और इस संबंध में अप्राथी की ओर से जो आपत्ति उठायी गयी है उसमें मुख्य आधार भी यह लिया गया है कि जो तथ्य प्राथी ने अपने क्लेम में वर्णित नहीं किया है, उस तथ्य की वैधानिकता का परीक्षण साक्ष्य के आधार पर नहीं किया जावे।

13. मैंने इस संदर्भ में अप्राथी की ओर से प्रस्तुत की गयी नजीर का अध्ययन किया तो यह प्रकट हुआ कि विचाराधीन प्रकरण में मुख्य बिंदु जो इस न्यायालय के द्वारा तय किये जाने के लिए रफ्तार किया गया है, वह अप्राथी संस्थान उद्योग है या नहीं, ही मुख्य बिंदु है और उसी बिंदु के संबंध में प्राथी के द्वारा अपने आधार क्लेम के रूप में दर्शाये हैं तथा जो जवाब अप्राथी द्वारा पेश किया गया है, वह भी उसी संदर्भ में पेश किया गया है। रफरेंस में जो बिंदु महत्वपूर्ण है, वह

अभिवचनों का अंग है और उसी के संबंध में तथ्य व साक्ष्य उभयपक्षों की ओर से पत्रावली पर पेश किये गये हैं। अतः मात्र क्लेम में अप्राथी संस्था उद्योग होंगे बाबत तथ्य वर्णित नहीं किये होने से प्राथी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य को निरर्थक मानना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी नजीर का अध्ययन किया तो पाया कि ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 548 की नजीर में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:-

Industry "as defined in S.2(3) has a wide Import

Where there is (i) Systematic activity (ii) organized by Co-operation between employer and employee (the direct and substantial element is chimerical) (iii) for the production and/or distribution of goods and services calculated so satisfy human wanting and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss e.g. making on a large scale prasad or food) prima facie there is an Industry in that enterprise.

Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant to the venture in the public, joint private or other sector.

The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity.

14. इस बिंदु के संबंध में जो साक्ष्य पत्रावली पर आयी है, उस बाबत अध्ययन से प्रकट होता है कि प्राथी कालू खां ने जो अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया है उसमें यह वर्णित है कि उसने अप्राथी के जवाब का जवाब जवाब प्रस्तुत किया जो प्रदर्श डब. 3 है। संयुक्त श्रम आयुक्त केंद्रीय ने दोनों पक्षों की वर्गीकृत करवायी जो दि. 27-11-98 को असफल हुई जो प्रदर्श डब. 2 है और उसके आधार पर अधिमूर्चन प्रदर्श डब. 1 इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई। मैंने इस संदर्भ में प्रदर्श डब. 2 का अध्ययन किया तो पाया कि उक्त पत्र दि. 27-11-98 में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं उसमें प्राथी को श्रमिक दर्शाया गया है और उसकी सेवा समाप्ति तथ्यों का विवेचन किया गया है और उक्त पत्र में अप्राथी की ओर से जो जवाब में तथ्य वर्णित किये गये थे, उनका विस्तृत विवेचन भी है। यह पत्र रफरेंस प्रस्तुत करने में एक महत्वपूर्ण आंच का ही आधार है। इसके अलावा जो प्राथी की ओर से प्रदर्श डब. 3 प्राथी पत्र सहायक श्रम आयुक्त केंद्रीय, सिविल लाईन्स, अजमेर को भेजा गया है उसमें भी इन्हीं तथ्यों का विवेचन है और उक्त पत्र में प्रस्तुत तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्राथी के द्वारा जो तथ्य महाप्रक श्रम अधिनियम के अंतर्गत उद्योग के रूप में वर्णित किये गये, वह उसकी सेवा शर्तों के संबंध में थे और अन्तर्गत प्रतिष्ठान के कार्य की प्रकृति के संबंध में थे।

15. इसी संदर्भ में मैंने उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का अध्ययन किया तो पाया कि अप्राथी की ओर से जो महाप्रक पेश किये गये हैं उनमें एनाइडब्ल्यू-1 और गौहम्मद ने अपने शपथ पत्र में यह कहा है कि दि. 30-7-94 को वह दरगाह गैस्ट हाऊस में केयर-टेकर व रिसीपिनिस्ट के पद पर कार्यरत था और शेख अहमद निवासी मुंबई ने कमरा परिवर्तन के संबंध में प्राथी के विरुद्ध शिकायत की गयी थी उस समय इयूटी पर तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने जायसीन का नाम लेकर कहा कि पचास रुपये की रिश्वत लेकर

[illegible]

किसिम	आयु	वर्ग	वर्ग
उच्चतर	उच्चतर	उच्चतर	उच्चतर
प्रकार	प्रकार	प्रकार	प्रकार

[illegible]

$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$

[illegible]

है कि वह इसका प्रयोग करेगा। यदि वह ऐसा करता है तो वह अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा।

[illegible][illegible]

१. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 २. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ३. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ४. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ५. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ६. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ७. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ८. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 ९. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।
 १०. **विद्यार्थी** : विद्यार्थी का अर्थ है कि वह पढ़ाई करने वाला है।

कि यह बात सही है कि श्री मोहम्मद ने जो मेरे खिलाफ 30-7-94 को शिकायत की थी, जो झूठी है जिसका मैंने जवाब दे दिया। यह सही है कि राधनपुर निवासी जैड. ए. चौहान ने मेरे खिलाफ रिश्वत लेने की शिकायत की थी जिस पर जवाब मैंने लिखित रूप में नाजिम को दे दिया था। यह बात सही है कि रिश्वत लेने, पैसा हड़पने से संस्थान की बदनामी होती है। बलेम के पैरा नं. 10 में ए से बी भाग मैंने सही लिखाया है।

21. इसी संदर्भ में पैरा नं. 10 के ए से बी भाग का अवलोकन किया तो उक्त भाग में :-

"बल्कि प्रार्थी ने तो अप्रार्थी के सानिध्य में ही रहो धांधलियों का पर्दाफाश किया था तथा अध्यक्ष, दरगाह कमेटी, अजमेर को लिखित में इनका हवाला दिया। अप्रार्थी ने प्रार्थी की शराफत का नतीजा उसको सेवा से मुक्त करके दिया। क्योंकि प्रार्थी ने अप्रार्थी की पोल खोल रखी थी जो अप्रार्थी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसी कारण से अप्रार्थी ने प्रार्थी को सेवा से बर्खास्त किया।"

22. इसी संदर्भ में एनएडब्ल्यू 3 मोहम्मद सिद्दीकी का शपथ-पत्र पेश हुआ है जिसने अपने शपथ-पत्र के मद नं. 2 में यह वर्णित किया है कि मेरे प्रचारी अतिथिगृह होने के समय प्रार्थी के संबंध में मेस्ट हाऊस में ठहरने वाले जायरीनों द्वारा उनके दुर्व्यवहार के संबंध में श्री शेर मोहम्मद जो मेस्ट हाऊस में स्वागतकर्ता के पद पर कार्यरत था ने भी नाजिम, दरगाह कमेटी, अजमेर को शिकायत की थी जिनके विषय में मेरे से भी पूछताछ की गयी थी। प्रार्थी के विरुद्ध श्री इब्राहिम खान, चपरासी ने भी शिकायत मुझे की थी। मैंने सभी शिकायतें नाजिम साहब के पास भेज दी थीं और जब इस गवाह से जिरह की गयी तो जिरह में यह कहता है कि प्रार्थी जमादार के पद पर अस्थायी रूप से नियुक्त हुआ था जहाँ से उसका स्थानांतरण स्वागतकर्ता के पद पर हुआ था और उस अवधि में वह इंचार्ज के पद पर कार्यरत था। जिरह में यह भी कहा है कि शेर मोहम्मद ने नाजिम को शिकायत किस तारीख को करी, उसकी तारीख तो मुझे याद नहीं है व अन्य शिकायतकर्ता के बारे में भी यह गवाह कहता है।

23. इसी संदर्भ में मैंने संदर्भित शिकायतों का अध्ययन किया तो पाया कि प्रदर्श एम-5 जो प्रार्थी को जारी किया गया उसमें वर्णित है कि राधनपुर निवासी जैड. ए. चौहान ने दिनांक 13-4-95 को यह शिकायत की कि उनके नाम से आरक्षित कमरे प्रार्थी ने उनको नहीं सँभलाये। इसी संदर्भ में प्रदर्श एम-7 रजिस्ट्रेशन रजिस्टर दिनांक 13-4-95 की प्रतिलिपि है जिसमें जैड. ए. चौहान के नाम कमरा नं. 41, 42, 43 दर्शाये गये हैं।

24. मैंने इस संदर्भ में विद्वान अभिभावक प्रार्थी की इस आपत्ति पर भी विचार किया कि आरक्षण निरस्त हो चुका था लेकिन न तो इस संबंध में कोई जवाबुल जवाब पेश किया गया है और न ही अप्रार्थी के गवाहान से ऐसा कोई सवाल जिरह में पूछा गया है, अतः प्रार्थी के अभिभावक की यह दलील मानने योग्य नहीं है। अन्य शिकायत प्रदर्श एम-9 भी प्रार्थी के विरुद्ध शिकायत है और उस पर नोटिस प्रदर्श एम-10 भी प्रार्थी को जारी किया गया है और जांच कार्यवाही प्रदर्श

एम-12 मुस्ताक अहमद हाऊस का हस्ताक्षरमुक्त बयान है जिसमें यह वर्णित है कि श्री मुस्ताक अहमद हाऊस बराबर दरगाह शरीफ की जियारत करने अजमेर आया करते हैं और इसी मेस्ट हाऊस में क्याम करते हैं। इस इल्जाम से पहले कभी भी हाऊस हमाल ने दरगाह अमले पर किसी तरह का इल्जाम आइद नहीं किया। मैंने जो रिपोर्ट की है वह बिल्कुल सही है किसी से अलन या बदले की भावना से प्रेरित होकर नहीं की गयी है व इसी तथ्य के समर्थन में मुस्ताक इब्राहिम-11 शेख मुकीम, समीर अहमद, अब्दुल गफ्फार व मोहम्मद नवाज के बयान दर्ज किये गये हैं व एक अन्य शिकायत प्रदर्श एम-17 भी प्रार्थी के द्वारा की गयी अनियमितताओं के संबंध में है, जिस पर कार्यवाही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा लेखबंद की गयी है।

25. उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के विरुद्ध जो शिकायत थी वह भ्रष्टाचार, कार्य के प्रति उदासीनता व अनियमितताओं के संबंध में थी, उसके संबंध में नोटिस भी जारी किये गये तथा उसका जवाब भी अप्रार्थी की ओर से दिया गया लेकिन जो तथ्य जिरह में उसने स्वीकार किये हैं, उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें थी और यह तथ्य भी स्वीकृत तथ्य है कि वह एक सेवानिवृत्त सैनिक है, जिसे नियमित पेंशन मिलती है, उसे नियत राशि पर कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था और उसके विरुद्ध की गयी शिकायतों के आधार पर जो उसे सेवा से पृथक् किया गया है, उस संबंध में उसे एक माह का अग्रिम वेतन भी भुगतान किया गया है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध आई भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायतों को दुर्घटित रखते हुए व इसके लिए उसे नोटिस भी जारी किये गये व उपरोक्त तथ्यों के विवेचन के आधार पर उसके सेवा पृथक्करण के आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं पायी जाती है।

26. जहाँ तक धारा 25-जी का प्रश्न है, प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई स्पष्ट तथ्य प्रमाणित नहीं कराया गया है जिससे यह प्रकट होता हो कि किसी कर्मचारी को उसके सेवा पृथक्करण के बाद लगाया गया हो या जिससे यह स्पष्ट होता हो कि किस कर्मचारी को कब सेवा में लगाया गया, कौन प्रार्थी से कनिष्ठ था तथा कौन वरिष्ठ है, किसकी नियुक्ति कब की गयी। अतः साक्ष्य के अभाव में धारा 25-जी औद्योगिक विवाद अधिनियम का उल्लंघन भी प्रार्थी पक्ष प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः प्रार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

आदेश

27. फलतः प्रस्तुत विवाद का उत्तर इस प्रकार से दिया जाता है कि प्रबंधन नाजिम दरगाह खाना साहिब धारा 2(जे) आई. डी. एक्ट, 1947 के अनुसार उद्योग की श्रेणी में आता है।

28. नाजिम दरगाह खाना साहिब, अजमेर द्वारा कंपन मोहम्मद कालू खां (सेवानिवृत्त) पूर्व-स्वागतकर्ता, मेस्ट हाऊस एवं सिक्कुरिटी इंचार्ज को पूर्ण वेतन मय एक माह के अग्रिम वेतन के भुगतान सहित सेवा पृथक् करना उचित एवं वैध है। अतः प्रार्थी/श्रमिक कोई राहत पाने का अधिकारी नहीं है।

दिनांक 23-9-2008

ह/-

मिथिलेख कुमार शर्मा, न्यायाधीश

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

APPEARANCES : Workman in person,
Shri Anil Kumar U.D.C. A/R
for the management

AWARD

The Central Government Ministry of Labour *vide* Order No. L-42012/230/2004-IR (CM-II) dated 9-8-2005 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the demand of the Worker’s Union for regularization of workman Shri Omkar Singh S/o Shri Bragi Singh in the establishment of CPWD is legal and justified? If yes, to what relief the workman is entitled and from which date?”

2. Today during the course of proceedings the workman moved an application praying for closure of his case. According to him he does not want to continue with this case in view of the writ petition filed in the Hon’ble High Court of Delhi. He further says that he has nothing to do with any workers’ Union who may have espoused his case. Heard. In view of the prayer made by the workman in the application. No Dispute Award is passed in this case. File be consigned to record room.

SATNAM SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का. आ. 3146.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस.सी. सो.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 94/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/158/2006-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3146.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 94/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workman, received by the Central Government on: 04-11-2008.

[No. I-22012/158/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

का.आ. 3145.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ सं. 88/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/230/2004-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3145.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 88/2005) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 2, New Delhi as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. CPWD, Central Public Works Department, and their workmen, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No. L-42012/230/2004-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
NO. 2 RAJENDRA BHAWAN, RAJENDRA PLACE
NEW DELHI**

I.D.No. 88/05

DATE : 23-10-2008

In the matter of dispute between :—

Shri Omkar Singh S/o Shri Bragi Singh,
Through Shri Ravi Shankar,
General Secretary Workers Union,
167, Panchkuan Road,
New Delhi-110001.

...Workman

Versus

The Director General,
M/s. C.P.W.D. Niman Bhawan,
New Delhi-110001.

2. Executive Engineer (Elect)
Elect. Constn. Divn. II,
Central Public Works Department,
A.C.D., II, U.P.S.C.
Dholpur House,
New Delhi

...Management

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD****PRESENT : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer**

Dated the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 94/2006**BETWEEN:**

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries
Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavarikhani, Karimnagar
(Andhra Pradesh)-505209.

...Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri.

...Respondents

APPEARANCES:

For the Petitioner : Nil

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Sectarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-42012/158/2006-IR (CM-II) dated 6-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in dismissing the services of Sri Boggula Chinnaiah w.e.f. 18-8-1999 is legal and justified? If not, what relief is the workman entitled to?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 94/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman.

The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer**Appendix of evidence**

Witnesses examined for the
Petitioner

NIL

Witnesses examined
for the Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

क्र. आ. 3147.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी.सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 93/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04.11.2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/159/2006-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3147.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.93/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No. L-22012/159/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

PRESENT : Shri VED PRAKASH GAUR,
Presiding Officer

Hyderabad the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 93/2006

BETWEEN

The General Secretary, (Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony, Godavari Khani,
Karimnagar (Andhra Pradesh) — 505209 Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri Division, Mandamarri, Respondents

APPEARANCES:

For the Petitioner : NIL
For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao
& K. Sectarana Rao,
Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/159/2006 (IR CM-II) dated 6-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in dismissing the services of Sri Md. Mohammed Ali w.e.f. 4-5-1999 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 93/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor

filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Prant Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL.	NIL.

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL.

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का. आ. 3148.- भारतीय विचार अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्वये में, केन्द्रीय सरकार एल. सी.सी.एल. के प्रबंधन को भ्रष्ट नियंत्रण और उनके कर्मचारियों के बीच, अन्वये में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के संकाय (एल.सी.सी.सी. 92/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का L-22012/159/2006 को प्राप्त हुआ था

[सं. एल-22012/159/2006 आई आर (सी एम-11)]

अजय कुमार गोड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3148.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No 92/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-11-2008.

[No. L-22012/159/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD****Present :** **Shri VED PRAKASH GAUR,**
Presiding Officer**Hyderabad the 24th day of September, 2008****Industrial Dispute No. 92/2006****Between :**

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries
Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavari Khani, Karimnagar
(Andhra Pradesh)-505209. : Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri. : Respondents

APPEARANCES:

For the Petitioner : Nil
For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Seetarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/160/2006 (IR CM-II) dated 6-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Durgam Thirupathi w.e.f. 28-2-1998 is legal and justified? If not, what relief is the workman entitled to?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No.

92/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer**Appendix of evidence**

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL.	NIL.

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

क्रा. आ. 3149.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 91/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-2008 को प्राप्त हुआ था

[सं. एल-22012/156/2006-आई आर (सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3149.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.91/2006)

of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No. 1-22012/156/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

PRESENT : SHRI VED PRAKASH
GAUR

PRESIDING OFFICER

Hyderabad the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 91/2006

BETWEEN

The General Secretary, (Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony, Godavari Khani,
Kariannagar (Andhra Pradesh)- 505209Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri Division, Mandamarri,Respondents

APPEARANCES :

For the Petitioner : Nil

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao
& K. Sectarana Rao,
Advocates

AWARD

The Government of India Ministry of Labour by its Order No. L-22012/156/2006 IR (CM-II) dated 6-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in dismissing Sri Keesaroina Gattaiah w.e.f. 10-2-1998 is legal and

justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 91/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

NIL,	NIL,
------	------

Documents marked for the Petitioner

NIL,

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का. आ. 3150.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में केन्द्रीय सरकार एस.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबंध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं.90/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/157/2006-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3150.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.90/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No.L-22012/157/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

PRESENT : Shri VED PRAKASH GAUR,
Presiding Officer

Hyderabad the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 90/2006

BETWEEN:

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries
Employees Council,
H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony,
Godavarikhani, Karimnagar
(Andhra Pradesh)-505209.

..... Petitioner

AND

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries
Company Limited,
Mandamarri Division,
Mandamarri.

..... Respondents

APPEARANCES:

For the Petitioner : Nil

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Sectarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its
Order No. L-22012/157/2006 (RI CM-II) dated 6-11-2006

referred the following dispute under section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is;

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in dismissing Si Janagam Ramakrishna w.e.f. 26-9-2001 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 90/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has not other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the
Petitioner

NIL

Witnesses examined
for the Respondent

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

AWARD

का.आ. 3151.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एम.सी. सी.एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ सं. 89/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/93/2006-आई आर (सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3151.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 89/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the Management of M/s. Singareni Collieries Limited, and their workmen, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No. L-22012/93/2006-IR(CM-11)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT
AT HYDERABAD**

Present : Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 89/2006

Between :

The General Secretary,

(Sri Bandari Saryanarayana),

Singareni Collieries

Employees Council,

H.No. 18-3-90/3, Ganesh Nagar,

Markandeya Colony,

Godavarikhani, Karimnagar

(Andhra Pradesh)-505209.

..... Petitioner

And

The General Manager,

M/s. Singareni Collieries

Company Limited,

Mandamari Division,

Mandamari.

..... Respondents

APPEARANCES

For the Petitioner : Nil

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Seetarama Rao,
Advocates

The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-22012/93/2006 RI (CM-II) dated 1-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is:

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Nakka Durga Swamy w.e.f. 24-3-2000 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 89/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has not other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appellate of evidence

Witnesses examined for the

Petitioner

for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3152.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 88/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/91/2006-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3152.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 88/2006) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workman, received by the Central Government on 04-11-2008.

[No. L-22012/91/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD**

Present: Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 88/2006

Between :

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony, Godavarikhani,
Karimnagar (Andhra Pradesh) - 505209 ...Petitioner

And

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri Division, Mandamarri, ...Respondents

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Seetarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/91/2006-IR (CM,II) dated 1-11-2006 referred the following dispute under Section 10(1)(d) of

the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is,

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Dhara Prabhakar w.e.f. 6-11-2001 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 88/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL.

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3153.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. सी. एल. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 87/2006) को

प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-2006 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-22012/92-2006-अईआर (सी.एम. 11)]

अजय कुमार गौड़, हेडक ऑफिसरी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3154, in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 87 of 2006) of the Central Government Industrial Tribunal-1, Hyderabad Court, Hyderabad as shown in the margin of this Award, Industrial Dispute between the management of Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-11-2006.

[No. L-25012-92-2006-410-1000-1]

AJAY KUMAR GAUR, Dy. Secy. (Adm.)

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-1, HYDRABAD COURT, HYDRABAD
(HYDRABAD)

Present: Shri V. V. Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the thirty-first of September, 2008.

Industrial Dispute No. 87/2006.

Between :

The General Secretary
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-5-90/3, Ganga Nagar,
Mankundya Colony, C. C. Searikhan,
Karimnagar (Andhra Pradesh) - 505209. (Petitioner)

And

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamari Office, Singareni,
Karimnagar (Andhra Pradesh) - 505209. (Respondent)

FOR THE PETITIONER:

For the Petitioner: Mr. J. B.

For the Respondent: M/s. M.V. Ramanaiah (S.O. 3154)
K. Seetarama Rao, Dy. Secy. (Adm.)

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour, by order No. L-22012-92-2006-410-1000-1, dated 1-11-2006, referred the following dispute under Section 10(1) of the I.D. Act, 1947 to adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workmen. The matter is as follows:

SCHEDULE

1. When in pursuance of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in accordance with the provisions of S.O. 3154, the Central

14-12-2000 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 87/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman and management. Notice was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash never appeared before this court nor filed the claim statement on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option but to pass a 'Nil' Award in this case. Transmitted.

Dictated to Shri V. Prakash Gaur, Personal Assistant transcribed by her, corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of Evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
NIL	NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नोट लिखा, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 3154,-- प्रमाणिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के प्रावधानों के अन्वये, केन्द्रीय सरकार (एम. सी. सी. एल. के. प्रमाणिक के संघट्ट नियंत्रकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुच्छेद 10(1) अधिनियम के अन्वये, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के अन्वये (संदर्भ संख्या: 85/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-2006 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-22012/92-2006-अईआर (सी.एम. 11)]

अजय कुमार गौड़, हेडक ऑफिसरी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3154, in pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 85/2006) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-11-2008

[No. L-22012/50/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT HYDERABAD

Present: Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Dated the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 85/2006

Between :

The General Secretary,
(Sri Bandari Satyanarayana),
Singareni Collieries Employees Council,
H.No.18-3-90/3, Ganesh Nagar,
Markandeya Colony, Godavarikhani,
Karimnagar (Andhra Pradesh) - 505209 ...Petitioner

And

The General Manager,
M/s. Singareni Collieries Company Limited,
Mandamarri Division, Mandamarri. ...Respondents

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Sektarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. L-22012/50/2006-IR (CM-II) dated 30-10-2006 referred the following dispute under section 10(1) (d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is :—

SCHEDULE

“Whether the action of the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Ellala Laxminarayana w.e.f. 12-2-1998 is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?”

2. This reference was received in this office on 4-12-2006 and registered in this Tribunal as I.D. No. 85/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman/union and management. Notice

was given from this court to both the parties by hand. From the Petitioner side, representative of the union filed an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and any further action in this case. As such the opportunity to file claim petition was closed by this court on 24-9-2008. The Respondent side has filed vakalatnama as back as in March, 2007 and they were coming to the court. As such in the absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a ‘Nil’ Award in this case. Transmit.

Dictated to Smt. P. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her, corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner	Witnesses examined for the Respondent
--	--

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 3155.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एस. सी. एल. के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के पंचाट (संदर्भ संख्या 86/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/51/2006-आईआर (सी एम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3155.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 86/2006) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court Hyderabad as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of M/s. Singareni Collieries Company Limited, and their workmen, received by the Central Government on 4-11-2008.

[No. L-22012/51/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT AT
HYDERABAD

Present: Shri Ved Prakash Gaur, Presiding Officer

Date of the 24th day of September, 2008

Industrial Dispute No. 86/2006

Between :

The General Secretary,
(Sri Bandaru Hanumanth Rao),
Singareni Collieries Employees Union,
H.No.18-5-9, Gopesh Nagar,
Markandeya, Gopalpet, Godavari Khani,
Karimnagar District, Andhra Pradesh- 505209. ...Petitioner

And

The General Manager,
M/s Singareni Collieries Company Limited,
Mandamari Division, Mandamari, ...Respondents

APPEARANCES

For the Petitioner : NIL

For the Respondent : M/s. M.V. Hanumanth Rao &
K. Sektarama Rao, Advocates

AWARD

The Government of India, Ministry of Labour by its order No. 1-2/2012-51/2006-IR (C.M.II) dated 30.10.2006 referred the following dispute under section 10(1)(d) of the I.D. Act, 1947 for adjudication to this Tribunal, between the management of Singareni Collieries Company Limited and their workman. The reference is,

SCHEDULE

"Whether the action of the management of M/s Singareni Collieries Company Limited in terminating the services of Sri Nagayathulla on 24.9.1998 is lawful and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The reference was received in this office on 4-12-2006 and referred to this Tribunal as I.D. No. 86/2006 and a copy of the reference order was served to the concerned workman, union and management. Notice was given from this court to both the parties by hand to the Petitioner side representative of the union, but an application authorizing Mr. V. Prakash to receive notice, but Mr. V. Prakash neither appeared before this court nor filed the Claim petition on behalf of the concerned workman. The case is pending for the last two years and no action has been taken either by the workman himself or the union of the workman. As such it appears that neither the concerned workman nor the union to which he is associated is interested in filing the claim statement and app. further action in this case. As such there is no opportunity to file claim statement or app. in this case. 24-9-2008. The Respondent side representative appears on 24-9-2008. The Respondent side representative appears on 24-9-2008.

absence of any claim statement or any adjournment application from the side of workman, this court has no other option, but to pass a NIL Award in this case. Transmit

Dictated to Smt. J. Phani Gowri, Personal Assistant transcribed by her corrected by me on this the 24th day of September, 2008.

VED PRAKASH GAUR, Presiding Officer

Appendix of evidence

Witnesses examined for the Petitioner
Witnesses examined for the Respondent

NIL

NIL

Documents marked for the Petitioner

NIL

Documents marked for the Respondent

NIL

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 3156.— औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में, केन्द्रीय सरकार मिलिट्री फॉर्म के प्रबंधन के संदर्भ निम्नार्थों और उनके कर्मचारों के बीच अनुबंध में निश्चित औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नं. 1, धर्मपुरी के पंचाट (संदर्भ संख्या 1,3,5,7/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 04-11-2008 को प्रेषित हुआ था।

[सं. एल-14012-25, 24, 22, 20-98-आईआर : ई.यू. 8]
अनुरा कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3156. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 1,3,5,7/99) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh, as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Military Form and their workman, which was received by the Central Government on 4-11-2008.

[No. 1- 14012-25, 24, 22, 20-98-IR (C.M.II)]

ANURAG KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH.**

Case No LDs. 1/99, 3/99, 5/99, 7/99 of 1999,

ID. No. 1/99 of Sh. Pancha Satnam

ID.No. 3/99 of Sh. Gaur Singh

ID. No. 5/99 of Sh. K. S. Kumar

ID. No. 7/99 of Sh. S. S. Singh

....Applicants

Versus

The Officer Incharge, Military Farm, Pathankot-145001.

.....Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Sh. Anandeshwar Gautam.

For the Management: Sh. K.K. Thakur.

AWARD**Passed on:-21-10-08**

Government of India referred the following industrial disputes for judicial adjudication to this Tribunal namely, ID 1/99 regarding Sh. Pankaj Salaria, Ref. No. L-14012/25/98/IR (DU) dated 13-11-98, ID 3/99 regarding Sh. Jaswant Singh, Ref. No. L-14012/24/98/IR (DU) dated 13-11-1998, ID 5/99 regarding Sh. Rajesh Kumar, Ref. No. L-14012/22/98/IR (DU) dated 13-11-1998, and ID, 7/99 regarding Sh. Somraj, Ref. No. L-14012/20/98/IR (DU) dated 13-11-1998. The common question of law and facts are involved in all these references. Hence, for convenience and for ends of justice all the references are hereby adjudicated by a common award. I.D. No. 1/99 will be the leading file.

The main question before this Tribunal for judicial adjudication is whether the action of officer in charge Military farm, Pathankot in terminating the services of all the 4 workmen mentioned above whose references are in question are legal and justified? If not, to what relief all the workmen are entitled?

All the 4 workmen have filed similar statement of claim that they joined the Military farm Pathankot as a labourer on different dates in the year 1999 as follows;

Sh. Pankaj Salaria joined, on 7-8-94, Sh. Jaswant Singh joined on 1-6-94, Sh. Rajesh Kumar joined on 6-1-94 and Sh. Somraj joined on 6-5-94. Their services were terminated on 1-12-97 by the management of respondent. It is alleged by the workmen that they, all have completed 240 days of work in the preceding year from the date of their termination. Their services were terminated without the notice or retrenchment compensation against the provision of Industrial Disputes Act. On the basis of these averments, the workmen have requested the Tribunal for an order reinstating them in the services along with back wages. Management of respondent appeared in all the cases and raised preliminary objections that this Tribunal has no jurisdiction to dispose of these reference on two counts.

(A) That the respondent is not an industry and the relationship between respondent and workmen are not that of employer employee relationship.

(B) The Central Administrative Tribunal constituted under the Central Administrative Tribunals Act, 1985 has the jurisdiction to redress the grievances of the workmen.

It has also been stated by the respondent that all the workmen along with few others opted to file a petition No.625/PB/96 against the notice of termination before the Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench which was decided vide order dated 20-12-96. After the termination of the services of the workmen, all the workmen along with others again filed NDA No.589/PB/97 before the Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench which was dismissed by the Tribunal vide judgement dated 26-3-97. Thereafter, a contempt petition was also moved before the Central Administrative Tribunal Chandigarh Bench which was dismissed by the Tribunal with the remarks that the applicants should avoid in filing such frivolous petitions in future.

On merits, it has been stated by the management of respondent that all the workmen were engaged as labourer from the date mentioned in their statement of claim. As per the policy of the Government of India all the labourers working on temporary basis were to be regularized as per the terms and conditions of the policy. One of the conditions was that workman should be enrolled in the office of employment officer and his name should be sponsored by the employment officer. Names of women were not sponsored by the employment officer, hence, they could not be regularized and as there was no work for the casual labourers, their services were no more required and were accordingly terminated. It has also been alleged by management of respondent that none of the workman has completed 240 days of work in the proceeding year from the date of their termination.

Parties were afforded the opportunity for adducing evidence oral and documentary. An officer of MES filed the affidavit and he was subjected to cross-examination by learned counsel for the workmen. Every workman was cross-examined in respective references. Parties also preferred to file the documentary evidence. Ex.M/x is experience certificate given by Sh. R.C. Sonkar, Farm Officer regarding the work of Sh. Pankaj Salaria. Same certificates have been provided by the respondent of management to rest of the workmen. R1 is the copy of the order dated 20-12-1996 passed by Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench in OA No.625-P8 of 1996. R2 is also the copy of the order passed by Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench dated 26-5-97 passed in OA No.589-IB of 1997. R3 is also an order dated 20-11-97 passed by Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench in COCP No. 49/97 in OA No.625/PB/96. R4 is the Circular Letter regarding the terms and conditions of service of casual industrial and non-industrial employees. R5 is the minutes of the 4th meeting (10 term) of Army HO JCH counsel dated 10-5-96. R6 is notice dated 17, January, 1996 given to all the workmen.

Heard learned counsels for the parties. Perused the materials on record. Learned counsels for the workman have argued that all the workman have worked for more

than 240 days in the calendar year proceeding to the date of their termination. As their services were terminated without any notice or retrenchment compensation, they are entitled to the relief as prayed in compliance of the provisions of Industrial Disputes Act.

Learned counsel for the management has alleged that respondent is not an industry and the dispute between the workmen and respondent is not an industrial dispute. There is no relationship of a nature which can be termed as employee-employer relationship and, accordingly, this Tribunal has no jurisdiction to dispose of these references. Learned counsel for the management of respondent has also argued that Central Administrative Tribunal constituted under the Central Administrative Tribunal Act, has got jurisdiction to redress the grievances of the workmen and the same has redressed the grievances in finality and the judgement of Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench will operate as res judicata in these references.

Learned Counsel for the management of respondent has further argued that as there was no work available for the workmen, their services were rightly terminated as per the policy of Central Government because their names were not sponsored by the Employment Office as desired by the Central Government policy.

The main issues before this Tribunal for adjudication of these references are :-

1. Whether the respondent is an industry? If yes, its affects?
2. Whether this Tribunal has got no jurisdiction for disposal of these references?
3. Whether the orders passed by the Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench, dated 26-3-1997, will operate as res judicata in all these references?
4. To what relief, if any, the workmen are entitled?

I am adjudicating all these issues one by one

The term Industry has been defined in section 2(j) of the Industrial Disputes Act, 1947, to mean any business, trade undertaking, manufacturing or calling upon employers and includes any calling, services, employment, handicraft or industrial occupation or avocation of workmen. In Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A. Rajappa and others AIR, 1978 Supreme Court 548, 7 Judges Bench of Hon'ble the Apex Court has defined the word 'Industry'. As per the above mentioned law laid down by the Apex Court, industry has defined in Sub-section 2(j) as a wide term and import as:-

- (a) Where there is (i) systematic activity, (ii) organized by co-operation between employer and employee (the direct and substantial element is chimerical), and (iii) for the production and/or

distribution of goods and services calculated to satisfy human wants and wishes (not spiritual or religious but inclusive of material things or services geared to celestial bliss), prima facie, there is an industry in the enterprise.

- (b) Absence of profit motive or gainful objective is irrelevant, be the venture in the public, joint, private or other sector.
- (c) The true focus is functional and the decisive test is the nature of the activity with special emphasis on the employer-employee relations.
- (d) If the organization is a trade or business it does not cease to be one because of philanthropy animating the undertaking.

Thus, the test (specially triple test) referred by Hon'ble the Apex Court in Bangalore Water Supply case (Supra) are necessary to qualify any institution to be an industry.

Regarding the sovereign functions, Hon'ble the Apex Court in Bangalore Water Supply Case (supra) has held that sovereign functions strictly understood cannot alone qualify the exemption, nor the welfare activities or economic advantage undertaken by Government or statutory bodies. Even in departments discharging sovereign functions, if there are units which qualified to be the industry and they are substantially sevegral then, they can be considered to come within Section 2(j) in the definitions of Industry.

Thus, the decision whether the particular organization is industry or not has to be taken by the work done and business carried on by it, which absolutely depends on the facts and circumstances of each Case. I have gone through the evidence of the management. The officer of military farm, Pathankot in all the references has stated in his affidavit that the main function of the military are to supply milk and milk products to the armed forces of the union and also to supply Hay of the animals to the armed forces of union. Big farms are maintained by military farm, Pathankot and milk and milk products are produced. Thus the function of maintaining the farms and producing the milk and milk products and the services rendered for the maintenance of above mentioned working, it cannot be said that the military farm qualified for the sovereign functions. Without disputing the fact that most of the functions of the organization, whose unit is military farm, may be the sovereign functions but the unit military farm on the basis of work done and service rendered is an industry as held by Hon'ble the Apex Court in Bangalore Water supply Case (supra) that even in departments discharging sovereign functions, if there are units which are industries and they are substantially sevegral then they can be considered to come within Section 2(j) in the definition of Industry. Thus, on the basis of above

mentioned observation, I am of the view that respondent is an industry. Paper No. 3 which is a circular letter of the respondent containing terms and conditions of service of casual industrial and non industrial employees also support the above contention that certain groups which are working with the Military farm are considered as industrial groups and it cannot be said that respondent is not an industry. It is undoubtedly an industry and the dispute in between the workmen and the management of respondent is the industrial dispute. Moreover, in cross-examination, MWI, the witness of management has also stated that retrenchment compensation shall not be given because none of the workman has completed 240 days of work in the calendar year proceeding to their termination. This also provide the reason to believe that respondent Military farm was adopting the procedure laid down in Industrial Disputes Act, 1947, considering the applicants as workmen and itself as industry.

Now the question before this Tribunal is what will be the effect of the orders passed by the Central Administrative Tribunal, Chandigarh Bench on applications moved by the workmen and whether these orders will operate as res judicata while answering these references.

A notice R-6 dated 17-1-96 was given to all the workmen with the following language :

"Your services are hereby terminated after one month of issue of this notice as you were not sponsored by Employment Exchange and not completed 240 days of service each in two calendar years".

After receiving this notice all the workmen along with others filed the petition before the Central Administrative Tribunal which was decided on 20-11-96. While deciding the application Central Administrative Tribunal passed the following order:-

"We have heard both the parties and it seems that only fair solution to the problem would be that the applicants should get themselves registered with the Employment Exchange, if they have not done so far. The respondents shall place a requisition with the Employment Exchange as and when they have work and shall also issue to the applicants experience certificate of having worked with term for the period in each case before their termination orders are to be passed for getting weight age if permissible under the rules to get their names sponsored by the Employment Exchange. The interim order, passed earlier is vacated. The original applications stands disposed of with these directions. No costs."

There is no material on record that names of the workmen, as directed by Central Administrative Tribunal in above mentioned order, were sponsored by the Employment Exchange resulting in the termination of services of the workmen. Thereafter, all the workmen filed

another application before Central Administrative Tribunal and the Central Administrative Tribunal dismissed the application in limine being not maintainable. While dismissing the application, Central Administrative Tribunal discussed all the facts and the law laid down by Hon'ble the Apex Court in Raj Kumar and others vs. Shakti Raj and others, 1972(2) SLR Page 130. The cause for dismissing the applications of workmen which is apparent from the order of Central Administrative Tribunal dated 26-5-97 is that temporary status cannot be given to the workmen in view of the policy of the Government. The Tribunal has also held that their reinstatement is not possible because their names were not sponsored by Employment Exchange as required by the policy of the Central Government.

The question before this Tribunal is altogether different. The question before this Tribunal is not whether the temporary status can be given to the workmen or whether order for regularization of the services of the workmen can be passed by this Tribunal ? The question before this Tribunal is whether the workmen are entitled for the relief on the ground of illegal termination?

As stated earlier that respondent is an industry. So, the dispute between the workmen and the respondent is an industrial dispute. There exists an employer and employee relationship between the workmen and the respondent. It is not the case of the management that the initial appointment of the workmen was illegal. If the workmen have completed 240 days of work in the calendar year proceeding to the date of their termination, they have a legal right protected by the Industrial Disputes Act, 1947 that their services cannot be terminated without notice and retrenchment compensation in compliance of the provisions of the Act. The question before the Central Administrative Tribunal was altogether different and that was legality of the notice given to the workmen regarding their termination of services and temporary status/regularization of their services.

At the cost of repetition, this Tribunal has got the jurisdiction to adjudicate these references. The notice R-5 which was given to the workmen clearly shows that it was the notice given under the provisions of Industrial Disputes Act and it was not expected from the workmen to approach the Central Administrative Tribunal but to approach the right forum mentioned under the Industrial Disputes Act. Accordingly, the orders passed by the Central Administrative Tribunal on 20-12-96 and 26-3-97 will not be having any effect while adjudicating these references because this Tribunal has got jurisdiction to adjudicate these references as stated earlier.

It is true that the doctrine of estoppel, res judicata etc. are applicable in the proceedings before the Industrial Tribunal and Labour Courts. But in these references

position is altogether different. Any order can operate as res judicata when it is passed by the Court of competent jurisdiction and the question before the court in the previous petition and before this Tribunal are same. The question before this Tribunal is different. The adjudication by the Central Administrative Tribunal, which has taken a view how to give the temporary status/regularization the services of the workmen, and while taking this view the Central Administrative Tribunal has suggested mechanism as well that if the names of the workmen are sponsored by the employment exchange, they will be considered for regularization. Under the Industrial Disputes Act, as a Presiding Officer I have no jurisdiction to discuss the granting of the temporary status or regularization of the services of these workmen, I have to confine myself whether their termination was in terms of the provisions of Industrial Disputes Act. There is no bar for termination of the services of the workmen who have completed 240 days of work in a calendar year preceding to the date of termination. Thus termination should have been strictly as per the provisions contained in the Industrial Disputes Act. Meaning thereby, before terminating the services of the workmen who have completed the 240 days of work in the calendar year preceding to the date of termination a notice and retrenchment compensation is mandatory requirement which was not done by the management of military farm. Being different issues for adjudication, orders dated 20-12-96 and 26-3-97 will not operate as res judicata while answering these references.

Now, I have to discuss whether the workmen have completed 240 days of work in a calendar year preceding to date of their termination. It is true that in the notice R-6, it is mentioned that the workman has not completed 240 days of service. But R-1 which is the certificate given by the respondents provides that all workmen have worked from the date of their appointments till 10-2-1997 as casual labour. All the relevant documents which are relating to the work of workmen are lying with the management of respondent. It is true that the workmen have to prove that they have worked for more than 240 days in a calendar year preceding to the date of their termination by some cogent evidence. Merely mentioning these facts in affidavit and statement of claim will not be sufficient. The workmen have filed the experience certificate which undoubtedly proved that every workman has worked for more than 240 days in a calendar year preceding to the date of their termination. It is the certificate provided by the respondent and all other document regarding working days of every workman are lying with the respondent which failed to file the same before this Tribunal. Thus, on the basis of this certificate, I am accepting the contention of every workman that they have worked for more than 240 days in a calendar year preceding to the date of their termination. Needless to say that Central Administrative Tribunal in both of these orders

has also held that every workman has worked for more than 240 days in the preceding year from the date of their termination. I am not taking notice of this finding but holding on the basis of the evidence oral and documentary that every workman has worked more than 240 days in the calendar year preceding to the date of their termination and they were entitled for the benefit of law contained in Industrial Disputes Act, that their services should not have been terminated without notice or retrenchment compensation which was illegally done by the management. At the cost of repetition, the question before this Tribunal is not granting of temporary status or regularization of their services which can only be done subjected to the policy of the Central Government. I am confining myself only to the procedure of termination adopted by the respondent which are against the provisions of Industrial Disputes Act and the termination of workmen are illegal. Their termination being illegal, they are entitled for the relief.

Now, the question before this Tribunal is what remedy should be provided to the workmen? Whenever the termination of any workman is illegal, there are two possible remedies available namely :-

1. Reinstatement of the workmen on the post they were holding and on which they were working at the time of the termination and
2. A reasonable compensation.

In the cases like these where the respondent in compliance of the policy of the Central Government has regularized all the casual labourers or granted the temporary status to them and no work for the casual labourers is left, their reinstatement into the Services will not be the proper remedy and they should be compensated reasonable in terms of money. What should be a reasonable compensation is to be decided on the basis of facts and circumstances of the each case. Factors like amount of retrenchment compensation to be given to the workmen at the time of their termination, depreciation for the value of money and the cost of litigation which the workmen were forced to incur on account of their illegal termination are to be considered while awarding the compensation. Considering all these facts, I am of the view that Rs.20,000 to each of the workman will be reasonable compensation to be provided to redress their grievances and to adjudicate all these references. Accordingly, management of respondent is directed to provide Rs. 20,000 as compensation to each of the workman (total Rs. 80,000) within a month from the date of publication of this award. All these references are disposed of accordingly. ID 1-99 is the leading file in which award is passed. Let a copy of this award be kept in files of all other references namely ID3-99, ID5-99 and ID7-99. Central Government be informed. File be consigned.

C. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2008

का.आ. 3157.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार दूर-संचार विभाग के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 103/94) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 4-11-08 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/115/93-आईआर(डी.यू.)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 4th November, 2008

S.O. 3157.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 103/94) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 4-11-2008.

[No. L-40012/115/93-IR (DU)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 103/94

Sh. Habib Mohamad, H. No. 1251, Gandhi Nagar, Ropar
(Pb.) ...Applicant

Versus

(1) Divisional Engineer, Phones-E (I.O.B.), Telephone
Bhawan, Sector-17, Chandigarh-160017.

(2) The General Manager, Telecom, Chandigarh Telecom
District, Chandigarh. ...Respondent

APPEARANCES

For the workman : Shri N.P. Mittal

For the Management : Shri G.C. Babbar

AWARD

Passed on 17-10-2008

Central Government vide notification No. L-40012/115/93-IR (DU), dated 24-8-94 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Chandigarh Telecom District in terminating the services of Shri Habib Mohd., S/o Mohd. Saddique, ex-daily wage Driver in the office of DEP (E-IOB),

Chandigarh, w.e.f. 1-8-90 is justified? If not, what relief he is entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 17-10-08 for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The prescribed authority of the management made a statement that the management has agreed to provide job to Mrs. Salma widow of Habib Mohammad through contractor as per policy of the Government. On this assurance the widow of the workman withdraw reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

17-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3158.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार जम्मु एवं कश्मीर बैंक लि. के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण चण्डीगढ़ नं.-1 के पंचाट (संदर्भ संख्या 17/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/305/2002-आईआर(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3158.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 17/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of J & K Bank Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-12012/305/2002-IR (B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 293/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/200/2000-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3160.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.293/2000) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of J&K Bank Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-12012/200/2000-IR (B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 293/2000

Shri Navin Chopra C/o Tek Chand Sharma, 25 Sant
Nagar, Civil Lines, Ludhiana

...Applicant

Versus

The Chief Manager, Personnel, J&K Bank Ltd., Central
Office, Srinagar. ...Respondent

APPEARANCES

For the workman : None

For the Management : Shri Ashutosh Vajpayee.

AWARD

Passed on 8-10-2008

Central Govt. vide notification No. L-12012/200/2000-IR (B-1), dated 16-8-2000, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of J&K Bank Ltd. in terminating the services of Shri Navin Chopra S/o Shri Rajinder Chopra without issuing him any notice/Charge sheet is legal and just? If not, to what relief the concerned workman is entitled?"

2. None is present on behalf of the workman. Learned counsel for the management is present. The reference was referred by the Central Government in the year 2000. Case called several times. It is already 4.15 pm. At this stage, I have no option otherwise then to dismiss the claim of workman in reference for non-prosecution and return the reference to the Central Govt. as such. Accordingly, the

reference is returned as such. Let the Central Government be informed. File be consigned.

Chandigarh.

8-10-08

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3161.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध में मिलेजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 72/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 05-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/200/2006-आईआर(सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3161.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No.72/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 05-11-2008.

[No. L-22012/200/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 72/2007

Sh. Mitha Singh son of Shri Chand Singh, V&PO : Dugat
Kalan, Patiala. ... Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India,
Patiala (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region 31-A, Chandigarh

... Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/200/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Mitta Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Honble High Court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdrew his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdrew the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

Chandigarh

18-10-2008 Camp, Patiala.

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3162. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूचन में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संघर्ष नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुसूचन में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक श्रमिकों के संघर्ष के संदर्भ में संघर्ष संख्या 54/2007 का प्रकीर्ण करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 5-11-2008 प्राप्त हुआ था।

[सं. एड-22012/191/2006- नई दिल्ली एम-11]

अजय कुमार सिंह, डी.एम. अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3162. —In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 54/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-

cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman, referred by the Central Government on 5-11-2008.

[No. 1-22012/191/2006-IR (CM-11)]

AJAY KUMAR GAUR, D.M. Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH.

Case I.D. No. 54/2007

Sh. Bhinder Singh, Son of Shri Gurnial Singh, V&PO,
Burada, Patiala, (Punjab) ... Applicant

versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, Sector 31-A, Chandigarh ... Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the Management : Smt. Parninder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. 1-22012/191/2006-IR (CM-11), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:-

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Bhinder Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when

available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraws, the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3163.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 76/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/196/2006-आई.आर.(सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3163.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 76/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/196/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 76/2007

Sh. Pargat Singh son of Shri Chota Singh, V&PO:Shadi
Hari Thana, Tehsil Dirba, Sangrur Applicant
Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, Sector 31-A, Chandigarh
... Respondents

APPEARANCES

For the workman : None

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

The Central Government vide notification No. L-22012/197/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Pargat Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under LPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Case repeatedly called. Workman is not present. Representative of the management is present. It is informed by representative of the workman that workman has expired. No application has been filed on behalf of the workman for LRs. No claim statement has been filed. Therefore, I have no option but to return the reference as such to the Central Government because the claim, if any has been abated. Central Government be informed. File be consigned to record.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3164.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 75/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/197/2006-आई.आर.(सी.एम.-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S. O. 3164.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 75/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/197/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 75/2007

Sh. Amrik Singh, Son of Shri Modan Singh, V&PO, Bhodhar
Thana, Tehsil Dirba, Sangrur Applicant
Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India,
Patiala (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, Sector 31-A, Chandigarh
..... Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/191/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Amrik Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre-Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraws the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the

reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

ई दिवसी, 5 अक्टूबर, 2008

का.आ. 3165, - औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अन्तर्गत में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संलग्न विवादकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट अर्थात् प्राप्ति के बाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1, नारायण क पन्थ (मदन संख्या 70/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार की 5.11.2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/176/2006-आईआर (सी एस-1)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S. O. 3165. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 70/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workman, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/176/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 70/2007

Sh. Amrika Singh son of Shri Chanan Singh, V&PO, Shadi
Hari Thana, Tehsil Dirba, Sangrur Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India,
Patiala (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, Sector 31-A, Chandigarh
..... Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L-22012/176/2006-IR

(CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Amrika Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed, File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. अ. 3166.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधक के संबद्ध निवासियों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1, चण्डीगढ़ को पंचाट (संदर्भ संख्या 59/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/163/2006-आईआर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S. O. 3166.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 59/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/163/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 59/2007

Sh. Sattu Singh Son of Shri Hari Singh, V&PO: Data Singhwala, Jind. Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, Sector 31-A, Chandigarh ... Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L-22012/163/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Sattu Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department

the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.अ. 3167, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 17 के अनुसूच में केंद्रीय सरकार द्वारा खाद्य निगम के पत्रबन्ध के संबंध में श्रमिकों और उनके कामकाजों के बीच, अनुबंध में निर्देश औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम सं.-1 चण्डीगढ़ के भंडार (संदर्भ संख्या 63/2007) को प्रकाशित कर दी है, जो केंद्रीय सरकार को 05-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-22012/131/2006-आई.आर. (सी.एन. 1)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क ऑफिसर

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3167. -In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 63/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 05-11-2008.

[No. L-22012/131/2006-IR (CM-1)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 63/2007

Sh. Balwant Singh Son of Shri Jaginder Singh, V&P,
Gurbani, Jind. ... Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India,
Patiala (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region 71-2, Chandigarh

... Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.
For the Management : Shri Parminder Singh,
Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide no. L-22012/131/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Balwant Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter covered in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and oppose this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-08 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-06. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. आ. 3168.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 41/2007) को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/129/2006-आईआर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3168.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 41/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/129/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 41/2007

Sh. Janta Singh Son of Shri Jaggar Singh V & PO: Khadial
Thana, Sunam, Sangrur.

..... Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

..... Respondents

APPEARANCES

- For the workman : Workman in person.
For the management : Shri Parminder Singh,
Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/129/2006 (IR) (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri

Janta Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. आ. 3169.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 66/2007) को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/134/2006-आईआर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3169.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

51.90/19585

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 66/2007) of the Central Government Industrial Tribunal (Labour Court No. 1, Chandigarh) as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/1347006 (Ref. No. 66)]
AJAY KUMAR GAUR, Dy. Secy.

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SINGH, J.,
PRESIDENT OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, CHANDIGARH**

Case I.D. No. 66/2007

Sh. Janta Singh son of Shri Mohar Singh & Poo. P. Singh, s/o,
Chandigarh

Versus

(1) The Manager, Food Corporation of India, Region,
(Patiala)

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, North Region, 31-A, Chandigarh

and 100 workmen

APPEARANCES

For the workman : Workman in person

For the management : Shri Parminder Singh
Advocate

AWARD

Passed on 28th of October, 2006 & Reconsidered on 28th

The award of settlement vide notification No. L-22012/1347006 (Ref. No. 66) dated 23-11-2007 has been received by the Central Government from this Tribunal for registration.

With reference to the action of the management in not allowing the workman of India in denying engagement of the workman as a contract worker under DPS in the management of the workman with the other 100 workmen of the management engaged under DPS is legal and valid and the management is entitled to the relief is the workman entitled to the relief.

The present reference was made by the management on the basis of the failure of conciliation proceedings in the management of the matter referred in the schedule of the management. The workman prayed for declaration that the management action is legal and valid.

The management turned up and opposed the reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre-Lok Adalat meeting on 16-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will follow the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdrew his reference in Lok Adalat. This statement and agreement was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdrew the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be assigned to record.

Chandigarh,

16-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

सं. दि. 3170, 5 नवम्बर, 2008

का. भा. 3170, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) को धारा 10 का अनुसूची में कोटीय सरकार प्रादेश स्तर नियम के संबंध में लोक अदालत और उनके कार्यवाही के बीच, अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में कोटीय सरकार कोटीय अधिनियम, 1947 का प्रादेश संदर्भ सं. 68/2007 को कोटीय प्रादेश है, जो कोटीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/1347006-30/2007 (का. भा. 3170)]

अजय कुमार गौर, सहायक सचिव

New Delhi, the 30th November, 2008

सं. भा. 3170.—In pursuance of section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 66/2007) of the Central Government Industrial Tribunal (Labour Court, No. 1, Chandigarh) as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/1347006 (Ref. No. 66)]

AJAY KUMAR GAUR, Dy. Secy.

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 65/2007

Sh. Balbir Singh son of Shri Pal Singh V & PO: Khongarh
Gharachon, Teh. Samana, Patiala.

..... Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala,
(Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

..... Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the management : Shri Parminder Singh
Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/
187/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the
following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food
Corporation of India in denying engagement of Shri
Balbir Singh, contract worker under Direct Payment
System at par with the other 105 contract workers
already engaged under DPS is legal and justified? If
not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central
Government on the failure of conciliation proceedings for
adjudication of the matter referred in the schedule referred
above and the workman prayed for declaring the action of
the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this
reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this
case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008
held in the office premises of Food Corporation of India,
Patiala for its disposal by adopting the mediation and
conciliation mechanism. The workman and the prescribed
authority of the management made a joint statement that
the management has agreed that as per policy of the
department the workman will be provided with the work as
and when available out of the list of the present workman
on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New

Delhi order dated 15-2-2006. The management has also
agreed that while adjusting the workman, it will honour the
seniority list maintained by the department itself. On this
assurance the workman withdraw his reference in Lok
Adalat. This statement above was read over and explained
to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw
his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman
withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly,
the reference is returned to the Central Government as
settled in Lok Adalat. Central Government be informed.
File be consigned to record.

Chandigarh

18/10/2008

Camp Patiala.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. आ. 3171.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय
खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध नियोजकों और उनके कर्मचारों के
बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
अधिकरण नं. 1, चंडीगढ़ के पंचर (संदर्भ सं. 48/2007) को प्रकाशित
करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/175/2006-आईआर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3171.—In pursuance of Section 17 of the
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the Award (Ref. No: 48/
2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-
Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure,
in the Industrial Dispute between the management of Food
Corporation of India, and their workman, which was
received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/175/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 48/2007

Sh. Birbal Singh son of Shri Chanan Singh V & P.O.: Jhaloor,
Thana Sangrur.

... Applicant

Versus

- (1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh

.....Respondents

APPEARANCES

- For the workman : Workman in person.
- For the management : Shri Parminder Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government *vide* notification No. L-22012/175/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Birbal Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdrew his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdrew the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as

settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18/10/2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. आ. 3172. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध निगमों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चंडीगढ़ की पंचाट (संदर्भ सं. 73/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/175/2006-आईआर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3172.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 73/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman, which was received by the Central Government on 5-11-2008

[No. L-22012/175/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I.D. No. 73/2007

Sh. Balvinder Singh son of Shri Harjeet Singh V & P.O.
Badalgarh, Sangrur

... Applicant

Versus

- (1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

...Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the management : Shri Parminder Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/199/2006 (IR) (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Balwinder Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. According the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be enforced. File be consigned to record.

Chandigarh G. K. SHARMA, Presiding Officer
18-10-2008
Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. आ. 3173.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चंडीगढ़ को पंखाट (संदर्भ सं. 40/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/128/2006-आईआर (सोएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3173.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 40/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/128/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 40/2007

Sh. Harbilash Singh son of Shri Harnek Singh V & P O :
Badalgarh Sangrur

... Applicant

Versus

- (1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab),
- (2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

.....Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the management : Shri Parminder Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/128/2006 (IR) (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Harbilash Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the order 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposed the reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 the case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3174, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार मैं, केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रधान के संबद्ध विशेषज्ञों और उनके कामेकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में हेतु सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, संदीयक के ज्वाह (संदर्भ क्र. 38/2007) को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार की 5-12-2006 को प्राप्त हुआ था :

[सं. एल-22012/126/2006 आईआर (सीएम-11)]

शय्य कुमार गौड़, इनक आधिकार

New Delhi, 30th November, 2008

S.O. 3174--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 38/2007) of the Central Government Industrial Tribunal in a Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and the workman, received by the Central Government on 5-9-2008.

(S.O. 3174/126/2006-IR (CM-11);
A.J.R. No. 126/126/2006-IR (CM-11))

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDAS KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. LD 38/2007

Sh. Desa Singh son of Shri Bana Singh M & P.O., Jhaagor
Thana Dirba, Sangrur

Applicant

Respondent

- (1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab), Patiala (Punjab)
- (2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh

Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person

For the management : Shri Harbilash Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government's notification No. L-22012/126/2006 (IR) (CM-11), dated 29-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Desa Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the order 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3175.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण में 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 51/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/190/2006-आईआर (सीएस-1)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3175.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 51/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workman received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/190/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH

Case No. I.D. 51/2007

Sh. Raja Singh son of Shri Maru Singh V & P O : Dugal
Kalan, Patiala

.. Applicant

Versus

- (1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

... Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person.

For the management : Shri Parminder Singh Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/190/2006 (IR) (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Raja Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the

seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.अ. 3176, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संवद्ध नियोक्तों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अभिकरण नं. 1, चंडीगढ़ के संघर्ष (अंदरूनी सं. 44/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन 72012/171/2006 आरआर (सोफ 11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क ऑफिसरी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3176.--(In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 44/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008

[No. 1-22012/171-2006-IR(CM-11)]

MAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 44/2007

Sh. Ajai Singh son of Shri Bhagwan Singh & Smt. Smt. Jhaloor Thana, Sangrur

Respondent

Versus

(1) The District Manager,
Food Corporation of India,
Patiala, (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

Respondents

APPEARANCES

For the workman : Workman in person

For the management : Shri Parminder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. 1-22012/171/2006-IR (CM-11), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication.

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Ajai Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008 this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3177.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार शुगरकेन ब्रीडिंग इन्स्टीट्यूट के प्रबंधन के संबद्ध नियोज्जकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 135/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/46/2003-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3177.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 135/2004) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the the management of Sugarcane Breeding Institute, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-42012/46/2003-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 135/2004

Shri Jaimal, Son of Shri Dharam Singh Village-Samora, Po-Kheri Man Singh, Distt. Karnal.Applicant

Versus

The Head, Sugarcane Breeding Institute, Regional Centre, Agarsain Marg, Karnal 132001.Respondent

APPEARANCES

For the Workman : None

For the Management : Shri Amit Sharma, Advocate

AWARD

Passed on 21-10-2008

Central Government vide notification No. L-42012/46/2003-IR (CM-II), dated 4-03-2004, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Sugarcane Breeding Institute in not granting temporary status and also non-regularising of service of Sh. Jaimal S/o. Sh. Dharam Singh w.e.f. 4-7-1981 is legal and justified? If not, to what relief the workman entitled to?"

2. None is present on behalf of the workman. Learned counsel for the management is present. The reference was

referred by the Central Government on the year 2004. Case called several times. It is already 1.15 p.m. At this stage, I have no option otherwise then to dismiss the claim of workman in reference for non-prosecution and return the reference to the Central Government as such. Accordingly, the reference is returned as such. Let the Central Government be informed. File be consigned.

Chandigarh

21-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3178.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोज्जकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 60/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/162/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3178.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 60/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/162/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 60/2007

Shri Jaimail Singh, Son of Shri Pilla Singh V & PO: Jhallor, The Dirba, Sangrur.Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala. (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh.Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 8th of October 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/162/2006-IR (CM-II), dated 23-04-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Jarnail Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief the workman entitled to?

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 8-9-2008, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliatory mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as sent in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

18-11-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

आई एलसी, 5 नवम्बर, 2008

कारण 3179.—औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (1947 का 17) के अनुसूची में केंद्रीय सरकार यात्री-समाप्तियों के संबंध में नियोजकों और उनका कार्यकर्ता के बीच अनुसूची में औद्योगिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिनियम नं. 1, मद्रास के चर्चा (नवम्बर 8, 1947) को 1 अंतर्गत है, जो केंद्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त 2008 का 1

[नं. एल-22012/189/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3179.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 69/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh has shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/189/2006-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH.

Case No. I. D. No. 69/2007

Shri Soma Singh, Son of Mukhtiar Singh V & PO:
Kahangarh Gharachen Patiala, (Punjab) Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala,
(Punjab), Patiala

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A Chandigarh Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Panninder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/189/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Soma Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 8-9-08, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for

its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

G.K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3180.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 45/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/172/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3180.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 45/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh has shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/172/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 45/2007

Shri Parkash Singh, Son of Nek Singh V & PO: Karnail,
Sangrur.Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala,
(Punjab), Patiala (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A Chandigarh ...Respondent

APPEARANCES

For the Workman: Workman in person.

For the Management: Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/172/2006 (IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to his Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Parkash Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

G.K. SHARMA, Presiding Officer

बुध दिवसी, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3181.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उसके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट आध्यात्मिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के संवत् (संदर्भ सं. 52/2007) को प्रकाशित करती है, जो कर्मचारी सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/193/2006-अर्द्ध और / संख्या 11.]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3181.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 52/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh has shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[सं. ए-22012/193/2006-IR(CM-II);
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SRI RAVANENDRA KUMAR SHARMA, C. PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case No. I. D. No. 52/2007

Shri Bala Singh, Son of Shri Karan Chand V & P.O. 11 Adhail, Sangrur. ... Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala (Punjab)

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh ... Respondent

APPEARANCES

For the Workman: Workman in person

For the Management: Shri Parminder Singh Arora

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala (Punjab)

Central Government vide notification No. 1-22017/193/2006-IR (CM-II), dated 25-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action on the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Bala Singh, Central worker under Direct Payroll

System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

The management turned up and opposes this reference

As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

बुध दिवसी, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3182.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केंद्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध निर्यातकों और उसके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट आध्यात्मिक विवाद में केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के संवत् (संदर्भ सं. 46/2007) को प्रकाशित करती है, जो केंद्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/193/2006-अर्द्ध और / संख्या 11.]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3182.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 46/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh has shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food

Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/173/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer
ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 46/2007

Shri Dharma Singh, Son of Shri Baldev Singh, V & PO;
Jhaloor Thana, Tehsil Dirba, Sangrur.Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala,
(Punjab),

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A Chandigarh ...Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L- 22012/173/
2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following
dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food
Corporation of India in denying engagement of Shri
Dharma Singh, Contract worker under Direct
Payment System at par with the other 105 contract
workers already engaged under DPS is legal and
justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central
Govt. on the failure of conciliation proceedings for
adjudication of the matter referred in the schedule referred
above and the workman prayed for declaring the action of
the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this
reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case
was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in
the office premises of Food Corporation of India Patiala for
its disposal by adopting the mediation and conciliation
mechanism. The workman and the prescribed authority of
the management made a joint statement that the
management has agreed that as per policy of the department
the workman will be provided with the work as and when
available out of the list of the present workmen on priority
in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order
dated 15-2-2006. The management has also agreed that
while adjusting the workman it will honour the seniority

list maintained by the department itself. On this assurance
the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This
statement above was read over and explained to workman
individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in
Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw
the present reference in Lok Adalat. Accordingly the
reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok
Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to
record.

Chandigarh.

18-10-2008

G.K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3183.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
(1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय
खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध में निर्योजकों और उनके कर्मचारियों के
बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक
अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 67/2007) को
प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त
हुआ था।

[सं. एल-22012/186/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3183.—In pursuance of Section 17 of the
Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central
Government hereby publishes the award (Ref. No. 67/2007)
of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour
Court No. I, Chandigarh has shown in the Annexure, in
the Industrial Dispute between the management of Food
Corporation of India, and their workmen, received by the
Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/186/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 67/2007

Shri Lachman Singh, Son of Shri Maghar Singh, V & PO;
Shadi Hari Thana, Sangrur.Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala,
(Punjab),

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of
India, Punjab Region, 31-A Chandigarh ...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L- 22012/186/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Lachhman Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

Camp Patiala

G.K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3184.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पेंटा (संदर्भ सं. 77/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/194/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौर, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3184.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 77/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No L-22012/194/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case I. D. No. 77/2007

Shri Lal Singh, Son of Shri Ajai Singh, v & PO: Kahangarh, Gharachon, PO: Patran, Teh. Samana, Patiala, Punjab.
...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh. ...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management: Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L- 22012/194/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to his Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Lal Singh, Contract Worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in

the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008.

Camp Patiala

G.K. SHARMA, Presiding Officer

आई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3185.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुच्छेद में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ग्राम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 37/2007) को प्रकटित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/125/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3185.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 37/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/125/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH.

Case I. B. No. 37/2007

Shri Hans Lal, Son of
Shri Jangir Singh, V & PO: Khadial,
The Sunam, Sangrur.

...Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A, Chandigarh.

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/125/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Hans Lal, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

Camp Patiala

G.K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3186.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय परकल भण्डार खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध निगोजका और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचायत (संदर्भ सं. 56-2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को ग्रहण हुआ था।

[सं. एल-22012/165/2006-आई अण्ड (सीएस 11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3186. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 56-2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008

[No. L-22012/165/2006-IR(CM-1)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 56/2007

Shri Binder Singh, Son of
Shri Chanan Singh, V & PO: Jhalour,
Thana, Sangrur

...Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh.

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/165/2006-IR (CM-1), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Binder Singh, a contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman, it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3187.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध निगोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचायत (संदर्भ सं. 50-2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को ग्रहण हुआ था।

[सं. एल-22012/169/2006-आई अण्ड (सीएस 11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3187. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 50-2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour

Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/169/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH.**

Case No. I. D. No. 50/2007

Shri Bhola Singh,
Son of Shri Narata Singh
V & PO: Data,
Singhwala, Jind.

...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food
Corporation of India, Patiala,
(Punjab), Patiala.

(2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A
Chandigarh.

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide notification No. L-22012/169/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Bhola Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in Pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India, Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation

mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman. It will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraws the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3188.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध निर्योजकों और उनके कार्यकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, खण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 49/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/168/2006-आई आर (सीएम-11)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3188.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 49/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/168/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH.**

Case No. I. D. No. 49/2007

Shri Panna Singh,
Son of Shri Lai Singh,
V & PO: Karnail,
Sangrur.

...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab), Patiala

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh

...Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

The Central Government vide notification No. L-22012/168/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Gurmail Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. Case repeatedly called. Workman is not present. Representative of the management is present. It is informed by the rep. of the workman that the workman has expired. No application has been filed on behalf of the workman for LRs. No claim statement has been filed. Therefore, I have no option but to return the reference as such to the Central Government because the claim, if any has been abated. Central Govt. be informed. File be consigned to rest etc.

Chandigarh, 18-10-2008 G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3189.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूची में केन्द्रीय सरकार द्वारा खाना निगम के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुसूची में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 43/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/170/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3189. In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 43/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court No. 1, Chandigarh has shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/170/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. 43/2007

Shri Gurmail Singh, Son of
Shri Moden Singh V & PO: Jhaloor,
Thana, Sangrur.

...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab)

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A, Chandigarh

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

The Central Govt. vide notification No. L-22012/170/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Gurmail Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of

the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh. G. K. SHARMA, Presiding Officer
18-10-2008

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3190.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 58/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/164/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3190.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/164/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH

Case No. I.D. 58/2007

Shri Raj Singh, Son of
Shri Bachan Singh V & PO: Data,
Singhwala, Jind.

...Applicant

Versus

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab), Patiala
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

The Central Govt. vide notification No. L-22012/164/2006/IR (CM-II), dated 23-4-2007 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Raj Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled

in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh. G. K. SHARMA, Presiding Officer
18-10-2008
Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का. अ. 3191, - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 14 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार (1) में खाद्य निगम के प्रबंधन के संघर्ष नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ नं. 51/2008) को प्रकाशित करती है, जो औद्योगिक सरकार को 5-11-2008 को उत्तर हुआ है।

[स. एन. 11/912/133/2006-005 अथवा (सं. 11/133)
प्रधान कृषि मंत्री, नई दिल्ली]

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3191.- In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 51/2008) of the Central Government Industrial Tribunal (Labour Court No. 1, Chandigarh) as shown in the Annexure to the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-23012/133/2006-180/51-133]
G. K. SHARMA, Presiding Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI LAXMANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CFM LABOUR COURT),
CHANDIGARH**

Case No. L.D. No. 51/2008

Shri Piar Singh, Son of
Shri Mohar Singh & P.O., Patiala, Patiala,
District,

Applicant

Versus

The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Review Office,
Chandigarh

Respondent

APPEALANCES

For the Workman : Workman in person

For the Management : Shri Panninder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October 2008 at Patiala Camp.

Central Govt. vide application No. L-23012/133/2006-18 (CM-II), dated 23-4-2006, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Piar Singh, Contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Govt. on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred to the schedule referred above and the workman proposed declaring the action of the management as illegal and voided.

3. The management turned up opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-08, this case was fixed in pre lok adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the department workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read out and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Govt. as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh. G. K. SHARMA, Presiding Officer
18-10-2008
Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.अ. 3192, - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 14 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संघर्ष नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुवन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ नं. 51/2008) को

प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/192/2006-आई आर (सीएम-1)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3192.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 53/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/192/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 53/2007

Shri Gurjant Singh, Son of
Shri Chanan Singh V & PO: Jhaloor,
Thana, Tehsil-Dibra, Sangrur.

...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food
Corporation of India, Patiala,
(Punjab), Patiala

(2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A
Chandigarh

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/192/2006-IR (CM-II), dated 23-04-2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Gurjant Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief the workman entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh. G. K. SHARMA, Presiding Officer
18-10-2008
Camp Patiala

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3193.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबंध में नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 74/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/198/2006-आई आर (सीएम-II)]
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3193.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 74/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/198/2006-IR(CM-II)]
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 74/2007

Shri Tersem, Son of
Shri Maghar Singh V. Rajdharana,
PO: Shadihari, Sangrur. ...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food
Corporation of India, Patiala,
(Punjab).

(2) The Senior Regional Manager,
Food Corporation of India,
Punjab Region, 31-A
Chandigarh ...Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-22012/198/2006-IR (CM-II), dated 23-04-2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Tersem Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman

on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3194. - औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसूच में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संरक्षित नियोजकों और उनके कर्मचारियों के बीच, अनुसूच में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधकरण नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचायत (संदर्भ सं. 71/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार का 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012-201/2006-आई आर (सीएम II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3194.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 71/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012-201/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

**BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH**

Case No. I. D. No. 71/2007

Shri Hans Raj, Son of
Shri Gurmail Singh V & PC Badalgarh,
Sangrur. ...Applicant

Versus

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh.

...Respondent

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18-10-2008 at Patiala Camp.

Central Government vide notification No. L-22012/201/2006 (IR CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Hans Raj, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

Camp Patiala

G. K. SHARMA, Presiding Officer

का.आ. 3195.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय खाद्य निगम के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं. 1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ सं. 64/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-22012/188/2006-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3195.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the award (Ref. No. 64/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India, and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-22012/188/2006-IR(CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL CUM LABOUR COURT-I,
CHANDIGARH

Case No. I. D. No. 64/2007

Shri Darshan Singh, Son of
Shri Budh Singh V & PO: Jhaloor
Thana, The Dirba, Sangrur.

...Applicant

Versus

(1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).

(2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, 31-A Chandigarh.

...Respondents

APPEARANCES

For the Workman : Workman in person.

For the Management : Shri Parminder Singh, Advocate.

AWARD

Passed on 18th of October at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-27/27/188/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Gulzara Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the reasons mentioned for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposed this reference.

4. As per the memorandum dated 28-9-2006, in the case was discussed in Lok Adalat meeting on 18-10-2006 held at the camp premises of Food Corporation of India, Patiala. On the day, the management adopted the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the bonus and when available one of the list of the present workman on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 1-4-2006. The management has also agreed that while allowing the workman it will follow the seniority list maintained by the department. In view of this assurance the workman withdrew his reference to Lok Adalat. This statement was read over and explained to workman in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat in view of the above, the workman withdrew the present reference in Lok Adalat. Accordingly, the reference is referred to the Central Government to be settled in Lok Adalat. Central Government has directed to file the copy of award.

Chandigarh

18-10-2007

Camp Patiala J. K. SHARMA, Presiding Officer

18 दिसम्बर, 2008

का.प्र. 3196.-औद्योगिक विवाद आयोग (1947 का 14) को श्रम वि. के अनुसूची में क्षेत्रीय मजदूर भवनों खाद्य निगम के पर्यटकों के संयुक्त निरीक्षकों और डाकू, मजदूरों के बीच, अनुसूची में निम्न औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार क्षेत्रीयक

अधिकरण नं. 1, चण्डीगढ़ के संघ (संदर्भ सं. 39/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एन-220/2-127/2006-आई आर (सीएम-II)]
अरुण कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3196.--In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 39/2007) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1. The legal facts shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between the management of Food Corporation of India and their workmen, received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-220/2-127/2006-IR(CM-II)]
ARUN KUMAR GAUR, Desk Officer
ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRAKUMAR SHARMA,
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH

Case I. D. No. 39/2007

Shri Gulzara Singh, Son of
Shri Deep Singh, V & Pw. Sanipur,
Karnalpur, Sangrur. Applicant

- (1) The District Manager, Food Corporation of India, Patiala, (Punjab).
- (2) The Senior Regional Manager, Food Corporation of India, Punjab Region, Jalandhar, Chandigarh. Respondents

APPEARANCES

For the Workman: Workman in person
For the Management: Shri Harinder Singh, Advocate

AWARD

Passed on 18th of October, 2008 at Patiala Camp

Central Government vide notification No. L-220/2/127/2006-IR (CM-II), dated 23-4-2007, has referred the following dispute to this tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Food Corporation of India in denying engagement of Shri Gulzara Singh, contract worker under Direct Payment System at par with the other 105 contract workers already engaged under DPS is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled to?"

2. The present reference was made by the Central Government on the failure of conciliation proceedings for adjudication of the matter referred in the schedule referred above and the workman prayed for declaring the action of the management as illegal and invalid.

3. The management turned up and opposes this reference.

4. As per office memorandum dated 5-9-2008, this case was fixed in pre Lok Adalat meeting on 18-10-2008 held in the office premises of Food Corporation of India Patiala for its disposal by adopting the mediation and conciliation mechanism. The workman and the prescribed authority of the management made a joint statement that the management has agreed that as per policy of the department the workman will be provided with the work as and when available out of the list of the present workmen on priority in compliance of the Hon'ble High Court, New Delhi order dated 15-2-2006. The management has also agreed that while adjusting the workman it will honour the seniority list maintained by the department itself. On this assurance the workman withdraw his reference in Lok Adalat. This statement above was read over and explained to workman individually in Hindi and he agreed to withdraw his case in Lok Adalat. In view of the above, the workman withdraw the present reference in Lok Adalat. Accordingly the reference is returned to the Central Government as settled in Lok Adalat. Central Government be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

18-10-2008

Camp Patiala G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2008

का.आ. 3197.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी.बी.एम.बी. के प्रबंधकों के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मचारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं.-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 95/1994, 97/1994, 99/1994) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 5-11-2008 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/1/1993-आई आर (डो. यू.)/(सी-II)]

[सं. एल-42012/3/1993-आई आर (डो. यू.)/(सी-II)]

[सं. एल-42012/5/1993-आई आर (डो. यू.)/(सी-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 5th November, 2008

S.O. 3197.— In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 95/1994, 97/1994, 99/1994) of the Central Government Industrial

Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BBMB and their workman, which was received by the Central Government on 5-11-2008.

[No. L-42012/1/1993-IR (DU)/(C-II)]

[No. L-42012/3/1993-IR (DU)/(C-II)]

[No. L-42012/5/1993-IR (DU)/(C-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

ANNEXURE

BEFORE SHRI GYANENDRA KUMAR, SHARMA
PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,
CHANDIGARH

Case I.D. Nos. 95/94, 97/94, 99/94

- (1) Shri Dayanand S/o Shri Guljari R/o Luhari Jattu, Tehsil Bhawanikhera, Distt.-Bhiwani
- (2) Shri Jai Bhagwan R/o Mandana, Tehsil Bhawanikhera, Distt.-Bhiwani.
- (3) Shri Suresh S/o Shri Muni Lal, H.No. 105, Labour Colony, Bhiwani, Distt. Bhiwani.

... Applicants

Versus

The Executive Engineer, Stores and Arrears Division
B.B.M.B., Bhiwani, Haryana. Respondent

APPEARANCES

For the workman: Sri. Hardayal Singh

For the management: Sri. Jyoti Kaushal

AWARD

Passed on 14-10-2008

These three references namely I.D. No. 95/94, Ref. No. L-42012/1/93-IR (DU)/(C-II), dated 24-8-94, Shri Dayanand Vs. Bias Project, I.D. No. 97/94, Ref. No. L-42012/3/93-IR(DU)/(C-II), dated 24-8-94, Shri Jai Bhagwan Vs. Bias Project and I.D. No. 99/94, Ref. No. L-42012/5/93-IR(DU)/(C-II), dated 24-8-94, Shri Suresh Vs. Bias Project are similar in nature. Common question of facts and law are involved in all these references and the question to be adjudicated is also the same whether the termination of each of the workman by the Bias Project, Bhiwani w.e.f. 28-2-90 are just, fair and legal? and whether each workmen are entitled for any relief? Accordingly, all the references are answered by single Award.

I.D. No. 95/94 will be leading file and a copy of the award will be placed in the files of I.D. No. 97/94 and I.D. No. 99/94.

1458567/08-18

I have gone through the pleadings of parties which are in form of statement of claim filed by the workman and written statement filed by/on behalf of the management of respondent. It is claimed by the workman that they were appointed on different dates in the year 1987 on the post of Mali as daily waged workers. They have completed 240 days of work preceding to the date of their termination from services without any notice or retrenchment compensation. Accordingly their termination was bad in law and illegal. As the juniors to them were retained in service and few new hands were recruited by the Bias Project, they are entitled for reinstatement into the services.

The management of respondent Bias Project denied the facts raised by the workman and alleged that on completion of the Project services of all the daily waged workers were terminated as per the provisions of Industrial Disputes Act. Notice was given to them which they refuse to receive and all the three workmen also refused to receive the retrenchment compensation. The Bias Project is not in existence. There is no work BCB nor any worker/employee physically in position under BCB. Only some notional posts are continued in BCB which are being managed by the Officers of BBMB in dual capacity. It has also been alleged by the management of respondent that none of the workmen has completed 240 days of work preceding to the date of their termination, hence, they were not entitled for any retrenchment compensation. Instead of that, they were afforded the opportunity for getting one month advance salary and the retrenchment compensation as desired by Industrial Disputes Act, which they refused. Both of the parties adduced the oral evidence and filed the documentary evidence as well.

I have heard learned counsels for the parties and pursued all the materials on record.

Learned counsel for the workmen has argued that as per evidence of management it was the part completion of the Project on which the services of the workmen were terminated which is against the provisions of Industrial Disputes Act. It has also been alleged by learned counsel for the workmen that few new hands were recruited after the termination of the services of the workmen which entitles the workmen for their reinstatement into the services. Learned counsel for the management of Bias Project has argued that as the work of the Project was over, no work was left for the workmen their services were ordered to be terminated under the provisions of Industrial Disputes Act, and no new recruitment were made after the termination of their services.

In the statement of claim, all the workmen have alleged that no notice was given nor retrenchment compensation paid, but in the cross-examination every workmen has admitted that the notice was served upon them but they refused to accept the same. It shows that intention of the management was conveyed to them that their services were

no more required. The notice dated 27-2-90 is on record which shows that services of say workmen were no more required w.e.f. 28-2-90. Vide this notice the management also asked every workmen to receive one month salary in lieu of notice and retrenchment compensation from the SDO C/W S/D II BB, Baramulla. Services of this notice is admitted by all the workmen. Order no. 293 dated 8-3-90 regarding the retrenchment of daily wagers is also on record which also shows the intention of the management to retrenched the daily waged workers including the three workmen whose claim is in question in these references. As on completion of the work the management shows its intention to give one month salary in lieu of one month notice and retrenchment compensation in compliance of the provisions of Industrial Disputes Act, the termination of the workmen cannot be said to be illegal under the provisions of Industrial Disputes Act.

Another issue to be answered by this Tribunal is whether the management has violated the policy of last come first go and appoint any new hands after the termination of the services of the workmen? The workmen have to prove before this Tribunal that new hands were recruited after the termination of their services. There is a casual statement made by all the workmen in their cross-examination that Ram Pansha had been appointed after their termination. Witness of the management in his cross-examination have denied this contention. It was a casual statement made by each workmen without narrating and disclosing the post and place of posting on which the worker so recruited was working and recording the addresses. The documents which have been filed by the management proved that there was no violation of the rule of last come first go and no new hands were recruited. As per the documents filed by the management, it is evident that all the workmen working in a particular wing were retrenched as per the provisions of Industrial Disputes Act as their services were no more required. Accordingly, all these references are answered in positive that the action of the management of Bias Project Bhiwani in terminating the services of all the three workmen were just, fair and legal?

So far as the next part of the reference is concerned which is to what relief are the workmen entitled, I am of the view that as the workmen have yet not received one month salary in lieu of the notice and retrenchment compensation, they are entitled to receive the same with 9% interest from 28-2-90 till the date of payment. The non-payment of one month salary in lieu of notice and retrenchment compensation was on ground of the conduct of the workmen, so, no other relief compensation can be awarded to any of the workman. Accordingly, the management of respondent is directed to provide to the workmen or deposited the same in the Tribunal one month salary in lieu of the notice which was due at the time of the termination of the services of the workmen and retrenchment

compensation along with 9% interest thereon from 28-2-90 till the date of payment within one month from the publication of the award. Central Government be informed. File be consigned.

G. K. SHARMA, Presiding Officer

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

क्र.आ. 3198.—केंद्रीय सरकार, लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 61) की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 2007-2008 के लिए उक्त अधिनियम के अधीन लेखाओं का विवरण और वित्त पोषित क्रियाकलापों की रिपोर्ट अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के अनुसार क्रमशः निम्न प्रकार से प्रकाशित करती है :—

वर्ष 2007-2008 के लिए लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि के लेखाओं का विवरण

अनुसूची-1

आय

01-04-2007 को आरंभिक बकाया	रु. 139.05 करोड़
वर्ष 2007-2008 के दौरान अंतरित उपकर	रु. 21.52 करोड़
कुल आय	रु. 160.57 करोड़

व्यय

मुख्य शीर्ष-2230

01.106-लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि 01.106.03 - प्रशासन

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
03.01.01	वेतन	9050
03.01.02	मजदूरी	109
03.01.03	अतिकाल भता	24
03.01.06	चिकित्सीय उपचार	289
03.01.11	घरेलू यात्रा व्यय	459
03.01.13	कार्यालय व्यय	1980
03.01.14	किराया दरें और कर	497
03.01.16	प्रकाशन	12
03.01.21	सामग्री और प्रदाय	94
03.01.26	विज्ञापन और प्रचार	21
03.01.27	लघु कार्य	67
03.01.28	वृत्तिक सेवाएं	40
03.01.50	अन्य प्रभार	6
योग		12648

01.106- लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि 01.106.04 - स्वास्थ्य

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
04.00.01	वेतन	29212
04.00.02	मजदूरी	215
04.00.03	अतिकाल भता	6
04.00.06	चिकित्सीय उपचार	259
04.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	375
04.00.13	कार्यालय व्यय	2706
04.00.14	किराया दर और कर	608
04.00.16	प्रकाशन	30
04.00.21	सामग्री और प्रदाय	4100
04.00.31	सहायता अनुदान	7357
04.00.50	अन्य प्रभार	1405
योग		46273

01.106- लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि 01.106.06 - शिक्षा

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
06.00.01	वेतन	4406
06.00.06	चिकित्सीय उपचार	53
06.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	77
06.00.13	कार्यालय व्यय	85
06.00.14	किराया, दर और कर	21
06.00.21	सामग्री और प्रदाय	119
06.00.34	छात्रवृत्ति और वृत्तिका	15706
06.00.50	अन्य प्रभार	1701
योग		22168

01.106- लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि 01.106.07 - मनोरंजन

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
07.00.01	वेतन	919
07.00.06	चिकित्सीय उपचार	45
07.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	20
07.00.13	कार्यालय व्यय	5
07.00.14	किराया, दर और कर	53
07.00.21	सामग्री और प्रदाय	46
07.00.31	सहायता अनुदान	75
07.00.50	अन्य प्रभार	221
योग		1384

01.106- लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि 01.106.05 - आवास

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपये में)
04.01.01	बैतन	516
04.01.06	चिकित्सीय उपचार	19
04.01.42	एकमुश्त उपबंध	65
04.02.31	निम्न लागत गृह निर्माण स्कीम	1090
04.03.31	अपना स्व गृह निर्माण करो	668
	स्कीम सहायता अनुदान	
	कुल आवास	2348
	योग (2230)	84821

लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि स्वास्थ्य

भोटर पान	172
मशीनरी और उपस्कर	12
कुल स्वास्थ्य (4250)	184

लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि मनोरंजन

भोटर पान	42
योग मनोरंजन (4250)	42
योग (4250)	226
कुल योग	85047
कुल आय	रु. 160.57 करोड़
कुल व्यय	रु. 8.56 करोड़

अनुसूची-2

वर्ष 2007-2008 के दौरान लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान - कल्याण निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलाप

क्रम सं.	क्रियाकलाप का नाम	इकाई
----------	-------------------	------

क. स्वास्थ्य :

1.	स्थिर-सह-गतिशील/स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आयुर्वेदिक औषधालय	16
2.	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कर्मचारियों के लिए अस्पताल	63
3.	औषधालय/अस्पतालों में उपचार किए गए रोगियों की संख्या	255*03
4.	कैंसर से पीड़ित लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कर्मचारियों का उपचार	6

क्रम सं.	क्रियाकलाप का नाम	इकाई
----------	-------------------	------

5.	हृदय रोग का उपचार	10
6.	गुर्दा रोग का उपचार	1
7.	खान कर्मचारियों की नसबंदी के लिए धन संबंधी प्रतिकर का संदाय	1
8.	विधवा/विधुर की पुत्री के विवाह में व्यय के लिए वित्तीय सहायता	3
9.	अंत्येष्टि के लिए वित्तीय सहायता	1
ख. आवास		
10.	अपना स्वगृह निर्माण करो स्कीम, सामूहिक गृह निर्माण स्कीम, टाईप 1 और 2 गृह निर्माण स्कीम के अधीन स्वीकृत गृहों की संख्या	9
ग. शिक्षा		
11.	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कर्मचारियों के स्कूल जाने वाले बालकों को छात्रवृत्ति और अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना	13851
12.	बर्तन/पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय	6057
घ. मनोरंजन		
13.	टोबी मेट	1
14.	लौह अयस्क खान, मैंगनीज अयस्क खान और क्रोम अयस्क खान कर्मचारियों के लिए किड्स, खेलकूद, सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन	22
15.	खेलकूद के सामान की खरीद	2
16.	कर्मकार चाना विश्रमगृह	1252
ङ. जल प्रदाय		
17.	बड़ी खानों को सहायता	1

[फा. सं. एस-23025/1/08 -डब्ल्यू II.]

अनिल स्वरूप, महानिदेशक (श्रम कल्याण)/संयुक्त सचिव

New Delhi, the 13th November, 2008

S.O. 3198.—In pursuance of Section 10 of the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund Act, 1976 (61 of 1976), the Central Government hereby publishes the statement of accounts and the report of the activities financed under the said Act, the year 2007-2008 as per Schedule-I and Schedule-II, respectively, as under :

**STATEMENT OF ACCOUNTS OF IRON ORE
MINES, MANGANESE ORE MINES AND CHROME
ORE MINES LABOUR WELFARE FUND FOR THE
YEAR 2007-2008**

SCHEDULE-I

INCOME

Opening Balance as on 1-4-2007	Rs. 139.05 crores
Cess transferred during the year 2007-2008	Rs. 21.52 crores
Total Income	Rs. 160.57 crores

EXPENDITURE

Major Head 2230

**01.106—Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and
Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund**

01.106.03—Administration

Head of Account	Units	(Rs. in thousand)
1	2	3
03.01.01	Salaries	9050
03.01.02	Wages	109
03.01.03	Overtime Allowance	24
03.01.06	Medical Treatment	289
03.01.11	Domestic Travel Expenses	459
03.01.13	Office Expenses	1980
03.01.14	Rents, Rates and Taxes	497
03.01.16	Publication	12
03.01.21	Supply and Material	94
03.01.26	Advertisement and Publicity	21
03.01.27	Minor Work	67
03.01.28	Professional Services	40
03.01.50	Other Charges	6
Total		12648

**01.106—Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and
Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund**

01.106.04—Health

Head of Accounts	Units	(Rs. in thousand)
04.00.01	Salaries	29212
04.00.02	Wages	215
04.00.03	Overtime Allowance	6
04.00.06	Medical Treatment	259

1	2	3
04.00.11	Domestic Travel Expenses	375
04.00.13	Office Expenses	2706
04.00.14	Rents, Rates and Taxes	608
04.00.16	Publication	30
04.00.21	Material and Supply	4100
04.00.31	Grants-in-aid	7357
04.00.50	Other Charges	1405
Total		46273

**01.106—Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and
Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund**

01.106.06—Education

Head of Accounts	Units	(Rs. in thousand)
06-00-01	Salaries	440
06-00-06	Medical Treatment	53
06-00-11	Domestic Travel Expenses	77
06-00-13	Office Expenses	85
06-00-14	Rents, Rates and Taxes	21
06-00-21	Material and Supply	119
06-00-34	Scholarships and Stipend	15706
06-00-50	Other Charges	1701
Total		22168

**01.106—Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and
Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund**

01.106.03—Recreation

Head of Accounts	Units	(Rs. in thousand)
07-00-01	Salaries	919
07-00-06	Medical Treatment	45
07-00-11	Domestic Travel Expenses	20
07-00-13	Office Expenses	5
07-00-14	Rents, Rates and Taxes	53
07-00-21	Material and Supply	46
07-00-31	Grants-in-aid	75
07-00-50	Other Charges	221
Total		1384

01.106—Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund

01.106.05—Housing

Head of Accounts	Units	(Rs. in thousand)
07-01-01	Salaries	516
07-01-06	Medical Treatment	19
07-01-42	Lumpsum Provision	65
07-02-31	Low Cost Housing Scheme	1080
07-03-31	BYOHS-Grants-in-aid	668
	Total Housing	2348
	Total (2230)	84821

Major Head 4250

Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund

Health

	Motor Vehicle	172
	Machinery and Equipments	12
	Total Health (4250)	184

Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund

Recreation

	Motor Vehicle	42
	Total Recreation (4250)	42
Total (4250)		226

Grand Total 85047

Total Income Rs. 160.57 crores

Total Expenditure Rs. 8.50 crores

SCHEDULE-II

Activities Financed under the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Labour Welfare Fund during the Year 2007-08

S. No.	Name of the activity	Units
1	2	3

A. HEALTH:

1. State-cum-Mobile/Static Allopathic and Static Ayurvedic Dispensaries. 16
2. Hospitals for the Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines workers. 03
3. Number of patients treated in dispensaries/hospitals. 255903

1	2	3
---	---	---

4. Treatment of Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Workers suffering from Cancer. 6

5. Treatment for Heart Disease 10

6. Treatment for Kidney Disease 1

7. Payment of Monetary Compensation for sterilization to Mines workers. 1

8. Financial assistance for wedding expenses to widow's/widower's daughter. 3

9. Financial assistance for funeral expenses 1

B. HOUSING:

10. Number of houses sanctioned under Build Your Own House Scheme, Group Housing Scheme, Type-I and II Housing Scheme. 9

C. EDUCATION:

11. Award of scholarship and other financial assistance to the school going children of Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Workers 13851

12. Supply of uniform/text books 6957

D. RECREATION:

13. Television Set 1

14. Organising sports, games, social and cultural activities for Iron Ore Mines, Manganese Ore Mines and Chrome Ore Mines Workers. 22

15. Purchase of sports material 2

16. Workers visiting holiday homes 1252

E. WATER SUPPLY

17. Assistance to big mines 1

[F.No. S-23025/1-08-W.11]

ANIL SWARUP, Director General (Labour Welfare)
Jt. Secy.

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2008

का.आ. 3199.—केन्द्रीय सरकार, छोड़ी कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम, 1976 (1976 का 62) की धारा 10 के अनुसरण में, वर्ष 2007-2008 के लिए उक्त अधिनियम के अधीन लेखाओं का विवरण और वित्तपोषित क्रियाकलापों की रिपोर्ट, अनुसूची-1 और अनुसूची-2 के अनुसार क्रमशः निम्न प्रकार से प्रकाशित करती है :—

वर्ष 2007-2008 के लिए बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के लेखाओं का विवरण

अनुसूची-1

आय

01-04-2007 को अरंभिक बकाया	रु. 24.24 करोड़
वर्ष 2007-2008 के दौरान अंतरित उपकर	रु. 184.62 करोड़
कुल आय	रु. 208.86 करोड़

व्यय

मुख्य शीर्ष-2230

01.109 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

01.109.04 - प्रशिक्षण

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
05-00-01	वेतन	26931
05-00-02	मजदूरी	220
05-00-03	अतिकाल भत्ता	69
05-00-06	चिकित्सीय उपचार	972
05-00-11	घरेलू यात्रा व्यय	1932
05-00-13	कार्यालय व्यय	7053
05-00-14	किराया, दरें और कर	1409
05-00-16	प्रकाशन	118
05-00-27	लघु कार्य	27
05-00-28	वृत्तिक सेवाएं	91
05-00-50	अन्य प्रभार	75
योग		38897

01.109 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

01.109.04 - स्वास्थ्य

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
1	2	3
04-00-01	वेतन	228186
04-00-02	मजदूरी	1905
04-00-03	अतिकाल भत्ता	13
04-00-06	चिकित्सीय उपचार	1607
04-00-11	घरेलू यात्रा व्यय	3403
04-00-13	कार्यालय व्यय	10121
04-00-14	किराया, दरें और कर	7880

1	2	3
04-00-16	प्रकाशन	48
04-00-21	सामग्री और प्रदाय	57563
04-00-26	विज्ञापन और प्रकाशन	154
04-00-27	लघु कार्य	1995
04-00-50	अन्य प्रभार	34114
योग		346989

01.109 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

01.109.03 - शिक्षा

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
03-00-26	विज्ञापन और प्रकाशन	413
03-00-34	छात्रवृत्ति और वृत्तिका	789996
03-00-50	अन्य प्रभार	43482
योग		833891

01.109 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

01.109.05 - शिक्षा

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
02-00-01	वेतन	502
02-00-03	अतिकाल भत्ता	10
02-00-06	चिकित्सीय उपचार	21
02-00-11	घरेलू यात्रा व्यय	40
02-00-13	कार्यालय व्यय	34
02-00-21	सामग्री और आपूर्ति	10
02-00-26	विज्ञापन और प्रकाशन	154
02-00-27	लघु कार्य	60
02-00-50	अन्य प्रभार	605
योग		1282

01.109 बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि

01.109.01 - आवास

लेखा का शीर्ष	इकाई	(हजार रुपए में)
1	2	3
01-03-01	वेतन	112
01-01-31	अपना स्वगृह निर्माण करो स्कीम सहायता अनुदान	93038
01-02-33	सामूहिक गृह निर्माण सहायकी	16060

1	2	3
66-00-33	सहायकी	135623
	कुल व्यय 2230	1091873
	मुख्य शीर्ष (2230) के अधीन	1155832
	कुल व्यय	
मुख्य शीर्ष (3601) ईंधनकुपण 01.00.31-		188860
सहायता अनुदान		
मुख्य शीर्ष (3601) के अधीन कुल व्यय		188860
मुख्य शीर्ष 4250 ओडी कर्मकार कल्याण निधि स्वास्थ		
मोटर वान		3380
मशीनरी और उपकरण		1295
योग (4250)		9674
कुल योग		2302304
कुल आय		20886 करोड़
कुल व्यय		230.21 करोड़

અનુમત્તી-૨

वर्ष 2007-2008 के दौरान बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि के अधीन वित्तपोषित क्रियाकलाप

क्रम सं.	क्रियाकलाप का नाम	इकाई का क्रम
1	2	3
	क. स्थापना :	
1.	स्थिर, सह-चल, स्थिर एलोपैथिक और स्थिर आनुवंशिक औषधालय	24
2.	बोर्डो कर्मकारों के लिए अस्पताल	95
3.	विशेषाधीन अस्पताल (पूरा होने के निकट)	98
4.	औषधालय/अस्पताल में उपचारित मरीज	99/2/98
5.	टीसी अस्पताल में अभिभाग औसत रेंजिंग	100/98
6.	तपेदिक में पीड़ित बोर्डो कर्मकारों का आवासीय उपचार	108
7.	जैदा में पीड़ित बोर्डो कर्मकारों का उपचार	109
8.	मनसिद्ध रोगों में पीड़ित बोर्डो कर्मकारों का आवासीय उपचार	11
9.	घरमें कार्य करने के लिए बोर्डो कर्मकारों का वित्तीय सहायता	108/3
10.	पीड़ित बोर्डो कर्मकारों के लिए प्रसूति प्रसूति स्कोम	94/80

1	2	3
11.	बौद्धी कर्मकारों की समस्याओं का निराकरण तथा सघनी प्रशिक्षण का संयोजन	173
12.	हृदय रोगों के रोकथाम में बौद्धी कर्मकारों का उपचार	178
13.	गुपी प्रस्तावनाओं के तहत में बौद्धी कर्मकारों का उपचार	181
14.	अल्पवयस्कों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम	184
15.	लघु बीमारियों का उपचार	185
16.	स्त्री रोग का उपचार	186
17.	उपद्रवक पुच्छोच्छेदन का उपचार	187
18.	विधवा, विधुर, बाली, अमानवीय का काम का विवाह व्यवस्था	188
ख. समाजिक सुधार		
19.	समूह बीमा योजना	189-190
ग. आवास		
20.	एकीकृत गृह निर्माण कामों के अर्थात् स्वयंसेवा गृहों को संरक्षण	191-192
घ. शिक्षा		
21.	बौद्धी कर्मकारों का समूह और अन्य कर्मियों की प्रशिक्षण	193-194
22.	बौद्धी कर्मकारों का समूह और अन्य कर्मियों की प्रशिक्षण पुस्तक/गणनाओं की प्रशिक्षण	195-196
ड. मनोरंजन		
23.	श्रम-दृश्य रोगों के उपचार, कर्मों का माध्यम से बौद्धी कर्मकारों के लिए प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण	197
24.	बौद्धी कर्मकारों के लिए बौद्धी, खेनक, सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा के लिए आयोजित	198
25.	विश्राम गृह में बौद्धी कर्मकार	199

“बीदो नर्मकातो के सुधो न” एतत्सु अलङ्कार उगर्क अंतर्गत आत है।

DOI: 10.1002/9781118710368.ch374

अनिष्ट स्वरूपः मङ्गलः, अथ कल्याणः/संनष्टः मङ्गलः

New Delhi, 07th to 10th November, 2008

S.O. 3199.— In pursuance of Section 10 of the Beedi Workers Welfare Fund Act, 1976 (62 of 1976), the Central Government hereby publishes the statement of accounts and the report of the activities financed under

the said Act, the year 2007-2008 as per Schedule-I and Schedule-II, respectively, as under :—

**STATEMENT OF ACCOUNTS OF BEEDI
WORKERS WELFARE FUND FOR THE YEAR
2007-2008**

SCHEDULE—I

INCOME

Opening Balance as on 1-4-2007	Rs 24.24 crores
Cess transferred during the year 2007-2008	Rs. 184.62 crores
Total Income	Rs. 208.86 crores

EXPENDITURE

Major Head 2230

01.109—Beedi Workers Welfare Fund
1.109.05—Administration

Head of Accounts	Units	(Rs. in thousand)
05-00-01	Salaries	26931
05-00-02	Wages	220
05-00-03	Overtime Allowance	69
05-00-06	Medical Treatment	972
05-00-11	Domestic Travel Expenses	1932
05-00-13	Office Expenses	7053
05-00-14	Rents, Rates and Taxes	1409
05-00-16	Publication	118
05-00-27	Minor Work	27
05-00-28	Professional Services	91
05-00-50	Other Charges	75
Total		38897

01.109—Beedi Workers Welfare Fund
1.109.04—Health

Head of Account	Units	(Rs. in thousand)
1	2	3
04-00-01	Salaries	228186
04-00-02	Wages	1905
04-00-03	Overtime Allowance	13
04-00-06	Medical Treatment	1607
04-00-11	Domestic Travel Expenses	3403
04-00-13	Office Expenses	10121
04-00-14	Rents, Rates and Taxes	7880

1	2	3
04-00-16	Publication	48
04-00-21	Material and Supply	57563
04-00-26	Advertisement and Publicity	154
04-00-27	Minor Work	1995
04-00-50	Other Charges	34114
Total		346989

01.109—Beedi Workers Welfare Fund
1.109.03—Education

Head of Account	Units	(Rs. in thousand)
03-00-26	Advertisement and Publicity	413
03-00-34	Scholarship and Stipend	789996
03-00-50	Other Charges	43482
Total		833891

01.109—Beedi Workers Welfare Fund
1.109.02—Recreation

Head of Account	Units	(Rs. in thousand)
02-00-01	Salaries	502
02-00-03	Overtime Allowance	10
02-00-06	Medical Treatment	21
02-00-11	Domestic Travel Expenses	40
02-00-13	Office Expenses	34
02-00-21	Material and Supply	10
02-00-27	Minor Work	60
02-00-50	Other Charges	605
Total		1282

01.109—Beedi Workers Welfare Fund
1.109.01—Housing

Head of Account	Units	(Rs. in thousand)
1	2	3
01-03-01	Salaries	112
01-01-31	BYOHS-Grants-in-aid	93038
01-02-33	GHS—Subsidies	16000
06-00-33	Subsidies	775623
Total Housing 2230		1071573
Total expenditure under Major Head (2230)		2105832

Major Head-3601, EWS-01.00.31-Grants-in-aid	186800
Total expenditure under Major Head (3601)	186800
Major Head-4250	
Beedi Workers Welfare Fund	
Health	
Motor Vehicle	8380
Machinery and Equipments	1293
Total (4250)	9673
Grand Total	2302305
Total Income	Rs. 208.86 crores
Total Expenditure	Rs. 230.23 crores

SCHEDULE—II

Activities Financed Under the Beedi Workers Welfare Fund During the Year 2007-08

Sl. No.	Name of the activity	Units
1	2	3
A. HEALTH:		
1.	Static-cum-Mobile/Static Allopathic and Static Ayurvedic Dispensaries.	304
2.	Hospitals for Beedi Workers	06
3.	Hospitals under construction (nearly completion)	01
4.	Patients treated in dispensaries/hospitals.	7772986
5.	Average Bed Occupation in TB Hospitals.	12804
6.	Domiciliary Treatment of Beedi Workers suffering from Tuberculosis	688
7.	Treatment of Beedi Workers suffering from Cancer	141
8.	Treatment of Beedi Workers suffering from Mental Diseases	21
9.	Financial Assistance to Beedi Workers for purchase of Spectacles	5083
10.	Maternity Benefit Scheme for Female Beedi Workers	9480
11.	Payment of Monetary Compensation for Sterilization	113
12.	Treatment of Beedi Workers in respect of Heart Diseases	178
13.	Treatment of Beedi Workers in respect of Kidney Transplantation	31
14.	Financial assistance for funeral	1342

1	2	3
15.	Treatment of Minor Diseases	25
16.	Treatment of Gynaecological diseases	18
17.	Treatment of Appendectomy	5
18.	Wedding Expenditure of daughter of Widow/Widower beedi workers	412
B. SOCIAL SECURITY:		
19.	Group Insurance Scheme*	1051361
C. HOUSING:		
20.	Number of houses sanctioned under Integrated Housing Scheme.	39133
D. EDUCATION:		
21.	Award of Scholarship to the school going children of Beedi Workers	628658
22.	Supply of Books/Uniforms to the school going children of Beedi Workers	216561
E. RECREATION:		
23.	Exhibition of films for Beedi Workers through Audio-Visual Sets/Cinema Vans	6
24.	Organizing sports, games, social and cultural activities for Beedi Workers	5
25.	Workers visited holiday homes	1725

*A) Identity Card holders of Beedi workers are covered.

[F.No. S-24025/27/08-W.II]

ANIL SWARUP, Director General (Labour Welfare)/Jt Secy.

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2008

का.आ. 3200.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा-1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 दिसम्बर, 2008, को उस तारीख के रूप में नियत करता है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा-76 की उप धारा (1) और धारा-77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :

राजस्व ग्राम	राजस्व परगना	राजस्व तहसील	जिला
1. लहरगिर्द	झांसी	झांसी	झांसी
2. भगवन्त पुरा	झांसी	झांसी	झांसी
3. कोछ भावर	झांसी	झांसी	झांसी
4. करारी	झांसी	झांसी	झांसी
5. पिछोर	झांसी	झांसी	झांसी
6. करगवां	झांसी	झांसी	झांसी

[सं. एम. 38013/43/2008-एस.एस. 1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 12th November, 2008

S.O. 3200.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st December, 2008 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Uttar Pradesh namely :—

Revenue Village	Revenue Pargana	Tehsil	District
1. Lehar Gird	Jhansi	Jhansi	Jhansi
2. Bhagwantpura	Jhansi	Jhansi	Jhansi
3. Kochha Bhawar	Jhansi	Jhansi	Jhansi
4. Karai	Jhansi	Jhansi	Jhansi
5. Pichhor	Jhansi	Jhansi	Jhansi
6. Kargawan	Jhansi	Jhansi	Jhansi

[No. S-38013/43/2008-SS.I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 3201.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप धारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 दिसम्बर, 2008, को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 [धारा 76 की उप धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध उड़ीसा राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

"अधिनियम के उक्त प्रावधान जिन क्षेत्रों में पहले ही लागू किए जा चुके हैं उनको छोड़कर गंजाम जिले में बरहमपुर की म्युनिसिपल सीमाओं के क्षेत्र इसमें शामिल हैं, तथा

1. गंजाम जिले में बरहमपुर तहसील के अंतर्गत रत्नपुर, शंकरपुर, मर्दाराजपुर सुंदराराजपुर, अंकुशपुर, सानकुसस्थली के राजस्व गांव
2. गंजाम जिले में छत्रपुर तहसील के अंतर्गत रघुनाथपुर, नरेन्द्रपुर के राजस्व गांव
3. गंजाम जिले में कोणिसी तहसील के अंतर्गत हलदीआपदर, रलभा, कोणिसी, हिन्जलापल्ली के राजस्व गांव शामिल हैं।"

[सं. एस. 38013/44/2008-एस.एस. 1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 2008

S.O. 3201.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st December, 2008 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Orissa namely :—

"The areas comprising of the Municipal limits of Behrampur in the district of Ganjam except the areas in which the said provisions of the Act have already been brought into force" and

1. The revenue villages of Ratanpur, Sankarpur, Mardarajpur, Sundararajpur, Ankushpur, Sanakusastali under the Tehsil Behrampur in the District of Ganjam.
2. The revenue villages of Raghunathpur, Narendrapur under Tehsil Chatrapur in the District of Ganjam, and
3. The revenue villages of Haladiapodar, Ralava, Konisi, Hinjalapalli under Tehsil of Konisi in the District of Ganjam.

[No. S-38013/44/2008-SS.I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2008

का.आ. 3202.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 दिसम्बर, 2008, को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के [अध्याय-4 (44 व 45 धारा के सिवाय जो पहले से प्रवृत्त हो चुकी है) अध्याय-5 और 6 धारा 76 की उप धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबन्ध तमिलनाडु राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

केन्द्र

1	2
गोपिचेंड्रिपालयम तालुक, ईरोड जिला व गोपिचेंड्रिपालयम क्षेत्र	1. वीरपाण्डी-गापी लडन 2. परियूर 3. चोबमादेविकरै 4. आलुक्कुलै (क) 5. आलुक्कुलै (ख) 6. मोडचूर 7. कुल्लम्पालयम 8. कल्लंजियम (क)

1	2	Centre Name	Areas Comprising the revenue villages of
	9. कल्लिचियम (ख)	Gopichettipalayam area	1. Veerapandi-Gopi Town
	10. लक्कम्पट्टो आदि के अंतर्गत होने वाले राजस्व गांव	Gopichettipalayam Taluk	2. Poyyur
		Erode district	3. Cholamudevikkalai
			4. Alukkudi (A)
			5. Alukkudi (B)
			6. Aludalur
			7. Kallampalayam
			8. Kalanjiam (A)
			9. Kalanjiam (B)
			10. Kalampuram

(सं. एस. 38013/45/2008-एस एस 1)

एस. डी. जैवियर, अवर सचिव

New Delhi, the 19th November, 2008

S.O. 3202. In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employee's State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby appoints the 1st December, 2008 as the date on which the provisions of Chapter IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter V and VI [except sub-section (i) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following areas in the State of Tamil Nadu, namely:-

[No. S-38013/45/2008-S&H]

S.D. NAVHUK, Order Secy